

सम्यक् करेंट अफेयर्स

► अंतरराष्ट्रीय ► राष्ट्रीय ► राजस्थान

23rd August
NATIONAL SPACE DAY
Aspirations to Gagarin : A road vision to infinite possibilities



FIH HOCKEY WORLD CUP
BELGIUM & NETHERLANDS
2026

समग्र शिशु
बाल स्वास्थ्य
कार्यक्रम



जयपुर घोषणा पत्र +

कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन
कॉन्फ्रेंस-2026

तीज महोत्सव



राष्ट्रीय
खेल
पुरस्कार
2025



सुमित
सरकार



Samyak

An Institute For Civil Services

03 दिवसीय निःशुल्क कक्षा के साथ

ऑफलाइन व LIVE FROM CLASSROOM

बैच प्रारम्भ

IAS

FOUNDATION

@3PM to 7PM

RAS

FOUNDATION

@8AM to 12PM

COMBO COURSE

PSI

PAPER I & II

E.O/R.O

@1PM to 5PM

क्लास 12th के बाद

IAS & RAS

प्रेजुएशन के साथ 2 & 3 वर्षीय कोर्स

@1PM to 5PM

बैच की विशेषताएँ



विषय विशेषज्ञों
द्वारा क्लासेज



टेस्ट
सीरीज



लाइब्रेरी
सुविधा*



प्रिंटेड
बुकलेट्स



पर्सनल
मेंटरशिप

SEPARATE BATCHES FOR HINDI & ENGLISH MEDIUM

H.O: NEAR RIDDHI - SIDDHI, JAIPUR ☎ 9875170111

-:: अनुक्रमणिका ::-

अध्याय	पृष्ठ संख्या
♦ मासिक सारांश	6
♦ राजस्थान परिदृश्य.....	9
महोत्सव/सम्मेलन/अभियान/आपरेशन.....	18
चर्चित व्यक्ति/स्थान/अन्य	18
खेल/खेल व्यक्तित्व/विविध.....	19
♦ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य	21
♦ राष्ट्रीय परिदृश्य	27
♦ आर्थिक परिदृश्य	33
♦ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	34
♦ खेल परिदृश्य.....	42
♦ पुरस्कार एवं सम्मान.....	46
सम्मेलन/बैठक/मेला/ महोत्सव/प्रदर्शनी	50
निर्वाचन एवं नियुक्ति	57
निधन.....	58
अभियान/युद्धाभ्यास	60
♦ महत्वपूर्ण दिवस	61
♦ विशेष लेख : मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन)	65
♦ राजस्थान के विभिन्न आयोग : (संवैधानिक और वैधानिक)	74
♦ राजस्थान की आगामी परीक्षाओं हेतु मॉडल पेपर	93
♦ करेंट अफेयर्स- सितंबर 2026 अंक वस्तुनिष्ठ टेस्ट	114

स्वत्वाधिकारी सम्यक एड्यूटेक,

प्रकाशक एवं सम्पादक वैष्णवी भारद्वाज द्वारा SP-21, गंगाराम नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राजस्थान)-302018 से प्रकाशित एवं महारानी प्रिन्टर्स, प्लॉट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर, राजस्थान-302012 से मुद्रित।

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर, राजस्थान होगा।)

Gmail id - currentaffairs@samyakias.com

मो. 9460480423 | इस अंक का मूल्य : 100 | वार्षिक सदस्यता शुल्क : 1000

इस अंक में प्रकाशित किसी भी सामग्री अथवा चित्र के लिए संपादक की सहमति होना आवश्यक नहीं है। इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया है तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक, उससे किसी व्यक्ति विशेष को पहुंची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

संपादकीय

“सफलता की राह: संकल्प, समर्पण और निरंतरता का सफर”

जीवन में किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करना केवल एक आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और विचारशील यात्रा है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाकर कुछ असाधारण हासिल करने का सपना देखता है, तो उसकी सफलता केवल उसकी प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके दृष्टिकोण से तय होती है।

यह पूरी यात्रा तीन अटूट स्तंभों पर टिकी है- संकल्प, समर्पण और निरंतरता।

“मनुष्य का संकल्प ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।”

सफलता की इस यात्रा का पहला चरण है- दृढ़ संकल्प। संकल्प वह बीज है, जिससे सफलता का वृक्ष अंकुरित होता है। संकल्प का अर्थ केवल इच्छा व्यक्त करना नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर अटल रहने का दृढ़ निश्चय है। जब विचार स्पष्ट और संकल्प अटूट होते हैं, तो मार्ग की हर बाधा मार्गदर्शक बन जाती है।

“कार्यों की सिद्धि केवल इच्छा करने से नहीं, बल्कि कठोर परिश्रम और समर्पण से होती है।”

संकल्प को धरातल पर उतारने का कार्य समर्पण करता है। समर्पण आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान को एक ही दिशा में केंद्रित करने की कला है। यह आपको क्षणिक भटकाव, आलस्य और निराशा से दूर रखता है। सच्चा समर्पण वह है जहाँ आप परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं। जब प्रयास संपूर्ण और निष्ठावान होता है, तो असफलताएँ भी आपको तोड़ने के बजाय परिपक्व बनाती हैं।

“सफलता अचानक नहीं मिलती, यह प्रतिदिन किए गए छोटे-छोटे प्रयासों का योग होती है।”

तीसरा और सबसे निर्णायक आधार है- निरंतरता। संकल्प और समर्पण के बाद भी कई बार परिणाम मिलने में समय लगता है। ऐसे कठिन क्षणों में धैर्य और निरंतरता ही व्यक्ति को टूटने से बचाती है। प्रतिदिन का एक छोटा प्रयास, अनुशासित अभ्यास और अपनी कमियों में निरंतर सुधार की आदत आपको हर दिन आपकी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाती है।

सफलता की यह राह केवल एक परीक्षा या पद को प्राप्त करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह स्वयं को तराशने की प्रक्रिया है। जब आप संकल्प, समर्पण और निरंतरता को अपना जीवन-मंत्र बना लेते हैं, तो सफलता केवल एक पड़ाव बनकर रह जाती है और उत्कृष्टता आपकी पहचान बन जाती है। अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए।

सम्पादक



निबन्ध प्रतियोगिता



निबन्ध का विषय-

1. भारत में हरित ऊर्जा संक्रमण :- नेट जीरो का लक्ष्य ।
2. राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और उसके समक्ष सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ ।



निबन्ध प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्तें और निर्देश-

- निबन्ध लेखन पूरी तरह मौलिक होना चाहिए, नकल या एआई द्वारा जनरेटेड सामग्री मान्य नहीं होगी।
- निर्धारित शब्द सीमा का पालन करें- 600 शब्द (लगभग)
- निबन्ध में व्याकरण, वर्तनी और विराम चिह्नों की शुद्धता पर ध्यान रखें।
- निबन्ध में केवल प्रमाणित और सटीक आंकड़ों या ऐतिहासिक तथ्यों का ही उपयोग करें।
- निबन्ध को निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले ही जमा करें। (30 सितंबर, 2026)
- निबन्ध केवल निम्न माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं-



1. Whatsapp- 9875170111



2. Mail- samyakcurrentaffairs@samyakias.com



3. स्थानीय पता- Samyak- An Institute For Civil Services,
Near Riddhi-Siddhi, Jaipur

- निबन्ध के साथ प्रतियोगी अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, आधिकारिक नाम और पता अवश्य भेजें।



पुरस्कार-

- प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पाने वाले प्रतिभागियों के फोटो को अगले माह की समसमायिकी पत्रिका में स्थान दिया जायेगा और संबंधित माह का अंक उनके निर्धारित पते पर भेजा जायेगा।

मासिक सारांश

- भारत की सबसे बड़ी गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना कहां की जायेगी? - **रामसर, अजमेर**
- 9 अगस्त, 2026 को राजस्थान में पशुओं की नस्ल सुधार और उनके संरक्षण के लिए देश व प्रदेश के पहले 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंटीजिनस फार्म' के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कहां किया गया? - **साण्डेराव गांव, पाली**
- राजस्थान ने 50 हजार मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, इसमें बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी का योगदान कितने मेगावाट है? - **लगभग 223 मेगावाट**
- ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में पारित 'जयपुर घोषणापत्र' कार्य समूह के कितने क्षेत्रों पर आधारित है? - **चार क्षेत्रों पर**
- राजस्थान में भारत सरकार के 'समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' को कौनसे जिलों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा? - **अलवर और भरतपुर जिलों में**
- वर्ष 2026 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? - **दो (डॉ. दिव्येंदु सेन और डॉ. वर्तिका गुलाटी)**
- 2 अगस्त, 2026 को राज्य में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने कितनी टास्क फोर्स का गठन किया है? - **चार टास्क फोर्स**
- जयपुर में आयोजित तीन दिवसीय 'कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस-2026' का विषय क्या था? - **कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ**
- राज्य के कौनसे चार हाटों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित किया जाएगा? - **अलवर, पुष्कर, जैसलमेर, नाथद्वारा हाट**
- रोम (इटली) में आयोजित 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? - **श्री वी. श्रीनिवास**
- 7 अगस्त, 2026 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां किया गया? - **जवाहर कला केंद्र में**
- राज्य में 300 करोड़ की लागत से एआइ हब कहां बनेगा? - **जोधपुर**
- फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैटरर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां और किसी तिथि को आयोजित किया गया? - **सीतापुरा में 1 अगस्त, 2026 को**
- 9 अगस्त, 2026 को आयोजित जल संचयन संकल्प कार्यक्रम का आयोजक कौन था? - **विश्व आदिवासी दिवस पर ग्रामीण विकास एवं शोध परिषद**
- प्रवासी राजस्थानी संगम कहां आयोजित किया गया? - **बेंगलुरु में**
- 15 से 24 अगस्त, 2026 को तीज उत्सव-2026 का आयोजन कहां किया गया? - **बीकानेर हाउस प्रांगण, नई दिल्ली**
- राजस्थान राज्य कृषि विभाग ने किस व्यक्ति को 'किसान ब्रांड एम्बेसडर' एवं ट्रेनर नियुक्त किया है? - **मोती लाल को**
- नेहा सोलंकी को सामाजिक नवाचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रासरूट इनोवेटर रिकॉग्निशन-2026 से सम्मानित किया है, यह राज्य के किस जिले की मूल निवासी है? - **नागौर जिले**
- राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से राजस्थान क्रिकेट में योगदान के लिए किस व्यक्ति को राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? - **डॉ. सीपी जोशी को**
- हाल ही में किसे कैलिफोर्निया स्थित सान्टा क्लारा विश्वविद्यालय ने डीन (अध्यक्ष) नियुक्त किया गया है? - **डॉ. रवि बापना**
- शहराह-द रॉयल रूट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माता कौन है? - **राहुल सूद**
- 42वीं सब-जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में राज्य के तैराकों ने कितने पदक जीते हैं? - **शून्य**
- 2 से 4 अगस्त, 2026 को आयोजित राज्य जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम रही है? - **धौलपुर जिला टीम**
- राजस्थान वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के चुनावों में सर्वसम्मति किसे अध्यक्ष चुना गया है? - **कमलेश शर्मा**
- हाल ही में 'टूर डी फ्रांस फेम्स' का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? - **हर्षिता जाखड़**

- जयपुर निवासी किस युवती ने मिसेज ओशन इंडिया-2026 का खिताब जीता है? - **अदिति चौधरी**
- रुद्रांश खंडेलवाल जो राजस्थान के पैरा निशानेबाज है, उनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2025 के तहत अर्जुन अवॉर्ड देने की घोषणा हुई है, यह राज्य के किस जिले के निवासी है? - **भरतपुर**
- भीलवाड़ा निवासी संध्या विश्रोई ने अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2026 में कितने किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? - **46 किलोग्राम वर्ग**
- अमेरिका के ओरेगन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 पुरुषों की हाई जंप चैम्पियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? - **बसंत कुमार मेघवाल**
- राज्य सरकार ने देश की पहली समर्पित लेक्रोस अकादमी कहां विकसित की है? - **महाराणा प्रताप खेलगांव, उदयपुर में**
- राजस्थान के कोटा जिले में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान का ब्रांड एंबेसडर किसे बनाया गया है? - **अरुंधति चौधरी को**
- केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का कार्यकाल कितने माह बढ़ा दिया है? - **6 माह**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ओली दाराजली डस्टलिक' से सम्मानित किया है? - **उज्बेकिस्तान**
- हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच किस तिथि को त्रिपक्षीय रक्षा समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? - **7 अगस्त, 2026**
- 17वां संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का सम्मेलन का विषय था- **Restoring Land. Restoring Hope**
- शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? - **बिश्केक, किर्गिस्तान**
- भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक ओश्वादबैंक के साथ चल रहे एक बहु-मिलियन डॉलर के अंतरराष्ट्रीय निवेश संधि विवाद में अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है? - **डी.वाई. चंद्रचूड़ को**
- हाल ही में स्पेन के कौनसे शहर में प्रवासन संकट उत्पन्न हुआ है? - **सेउटा शहर**
- अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक' की सूची से हटा दिया है? - **सीरिया को**
- 3 अगस्त, 2026 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहां पर हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? - **आईआईटी दिल्ली में**
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबरधन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कितना वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है? - **₹23,731 करोड़**
- 3 अगस्त, 2026 को ग्लाव झील को देश की 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। यह झील किस राज्य में है- **अरुणाचल प्रदेश**
- मिशन समृद्ध गाँव योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस राज्य के ब्लॉक में लागू किया जा रहा है? - **मध्य प्रदेश**
- एशिया का पहला डेजर्ट-थीम नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क कहां बनेगा? - **गुजरात में**
- इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने किस बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया है? - **परीछा बांध को**
- किस राज्य सरकार ने सांप/स्नेकबाइट के काटने को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? - **महाराष्ट्र**
- मिजोरम सरकार ने किस गीत को आधिकारिक राज्य गीत घोषित किया? - **रो मिन रेल साक आंग चे**
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-31 की अवधि के लिये किन्हें अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है? - **हीटवेव और आकाशीय बिजली (तड़ित)**
- हाल ही में किस देश की संसद ने फांसी की सजा खत्म करने वाला कानून पारित किया है? - **लेबनान**
- "की सेक्टर्स टु पोजिशन इंडिया एज ए ग्लोबल मेन्युफैक्चरिंग हब" नामक शीर्षक से किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गयी है? - **नीति आयोग ने**
- किस देश ने भारतीय सेना के लिये 60 जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है? - **अमेरिका**

- हाल ही में 'फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स' को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? - **भावना कान्त**
- इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई देश की पहली शत प्रतिशत स्वदेशी असॉल्ट राइफल है? - **एके-203 असॉल्ट राइफल 'शेर'**
- नासा द्वारा लांच नैसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को किस लांच व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया है? - **फाल्कन हेवी रॉकेट (स्पेसएक्स)**
- हाल ही में किस एयरोस्पेस स्टार्टअप ने भारत का पहला और पूरी तरह स्वदेशी फुल-फ्लो स्टैज्ड कंबिनेशन रॉकेट इंजन 'एवरेस्ट' बनाया है? - **एस्ट्रोबेस**
- किस राज्य में लेप्रोस्पायरोसिस रोग के प्रकोप के कारण रोग भार एवं मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गयी है? - **केरल**
- किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कृत्रिम 'वायरस' डिजाइन किया है? - **स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी**
- FIH हॉकी विश्व कप 2026 की पुरुष और महिला विजेता टीम रही है? - **जर्मनी (पुरुष) एवं अर्जेंटीना (महिला)**
- बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप-2026 का कौनसा संस्करण आयोजित किया गया था? - **30वां संस्करण**
- विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? - **ओरेगन, अमेरिका**
- हाल ही में ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? - **आर. प्रज्ञानानंद**
- लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर है? - **अर्जेंटीना के**
- विश्व ह्यूमनॉइड गेम्स-2026 का आयोजन कहाँ किया गया? - **बीजिंग, चीन**
- 2026 सिनसिनाटी ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? - **कोको गॉफ**
- लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 से किसे नवाजा गया है? - **अजीत डोभाल को**
- तमिलनाडु की वेलूर जेल में उम्रकैद की सजा प्राप्त लेखक सी. सेल्वम को किस पुस्तक के लिए इयाल अवॉर्ड प्रदान किया गया है? - **ओरु थूकू कैदियिन वाकुमूलम**
- विक्रम साराभाई पदक से किसे सम्मानित किया गया है? - **प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को**
- किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरिटिकल फिजिक्स द्वारा 2026 का 'डिराक मेडल' दिए जाने की घोषणा की गई है? - **दीपक धर**
- 6-7 अगस्त, 2026 को ब्रिक्स वेक्स बाज़ार का आयोजन कहाँ हुआ - **मुंबई**
- सृजन: करघे से आवाज़ें कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? - **विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय**
- हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की 54वीं डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? - **वर्षा अशोक अगलावे**
- हाल ही में किसे बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है? - **मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर**
- जाम्बिया की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? - **आभा नायर पटेल-**
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने किसे विशेष सलाहकार नियुक्त किया है? - **गौतम रंगराजन को**
- संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया? - **विभावादी रंगसिट कैप, थाईलैंड**
- स्फोटक आयुध निस्तारण (ईओडी) अभ्यास 2026 के कौनसे संस्करण का आयोजन किया गया है? - **8वां संस्करण**
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? - **7 अगस्त**
- विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित किया गया है? - **1 से 7 अगस्त के मध्य**
- 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स' पुस्तक के लेखक कौन हैं? - **पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद**
- मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने अपने नाम किया है? - **केजिया लीज मेजो**
- मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का खिताब किसने अपने नाम किया है? - **जोआना उरांगा**

राजस्थान परिदृश्य

साण्डेराव में खुलेगा देश का इकलौता 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडीजिनस फार्म' -

- हाल ही में 9 अगस्त, 2026 को राजस्थान में पशुओं की नस्ल सुधार और उनके संरक्षण के लिए देश व प्रदेश के पहले 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडीजिनस फार्म' के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया।
- स्थान- साण्डेराव गांव, पाली जिले
- लागत- पर ₹60 करोड़ की लागत
- इस केंद्र पर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े की 30 देशी प्रजातियों के नस्ल सुधार व संरक्षण पर काम होगा।

केंद्र पर नस्ल सुधार व संरक्षण किये जाने वाली प्रमुख नस्ल-

- गाय- गिर, कांकरेज, राठी, थारपारकर, साहिवाल, नागौरी, मालवी, हरियाणा तथा विश्व की सबसे छोटी गाय प्रजाति 'पुंगनूर' (मूलतः आंध्र प्रदेश) पर विशेष रिसर्च होगी।
- भैंस- मुरा, सूरती, जाफराबादी, मेहसाना।
- भेड़- मगरा, मारवाड़ी, नाली, चोकला, पूगल, जैसलमेरी, मालपुरा, सोनाड़ी।
- बकरी- बारबरी, सिरोही, जमनापारी, जखराना, सोजत, मारवाड़ी।
- ऊंट व घोड़ा- ऊंट की जैसलमेरी व बीकानेरी तथा घोड़े की मारवाड़ी प्रजाति।

राजस्थान ने 50 हजार मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की-



संक्षिप्त न्यूज

- 2 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री उदयपुर के कृषि महाविद्यालय में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
- 3 अगस्त, 2026 को उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अजमेर आयुर्वेद रसायनशाला के ऑटोमेशन का शुभारम्भ किया।
- 5 अगस्त, 2026 को योजना भवन में स्थित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन (रीति) में आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम तथा गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के सूचकांकों की प्रगति एवं सेचुरेशन हेतु राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- 6 अगस्त, 2026 को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय बीमा गवर्निंग काउंसिल की द्वितीय बैठक आयोजित हुई।

जयपुर घोषणापत्र-

- हाल ही में जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से 'जयपुर घोषणापत्र' को पारित किया गया।
- यह घोषणापत्र सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा स्थापित करेगा।
- यह घोषणापत्र कार्य समूह के 4 मुख्य क्षेत्रों पर आधारित है-
 1. एआई और पर्यटन
 2. सतत और जिम्मेदार पर्यटन
 3. पर्यटन कौशल और क्षमता निर्माण
 4. पर्यटन आदान-प्रदान और निर्बाध यात्रा सुविधा

समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-



- राजस्थान में भारत सरकार के 'समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' को अलवर और भरतपुर जिलों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।
- उद्देश्य- 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास की नियमित निगरानी करना तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना।
- इस कार्यक्रम में बच्चों को सामान्य और जोखिम श्रेणियों में बांटा जाएगा। जोखिम वाले बच्चों का घर पर नियमित फॉलो-अप किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में रेफर किया जाएगा।
- आशा कार्यकर्ताओं को बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग, स्थिति दर्ज करने, अलर्ट प्राप्त करने और अस्पताल रेफरल के बाद फॉलो-अप के लिए 'शैशव ऐप' उपलब्ध कराया जाएगा।

DAW-राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट-

- राजस्थान सरकार ने राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स, प्रशिक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'DAW-राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट' स्थापित करने की घोषणा की है।
- यह रेगिस्तान, अरावली पर्वत शृंखला और झीलों के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ जोड़ने वाला पहला एडवेंचर संस्थान होगा।
- स्वरूप- इसे राष्ट्रीय स्तर के 'ग्रीनफील्ड केंद्र' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- लागत- प्रारंभिक अनुमानित लागत ₹218.75 करोड़।
- **हब एंड स्पोक मॉडल (3 भौगोलिक नोड्स)-**
 1. एयरो नोड- जोधपुर-जैसलमेर क्षेत्र (रेगिस्तानी हवाई गतिविधियों हेतु)
 2. लैंड नोड- माउंट आबू-जवाई क्षेत्र (पर्वतारोहण व ट्रैकिंग हेतु)
 3. एक्वा नोड- उदयपुर क्षेत्र (जल क्रीड़ा व वॉटर स्पोर्ट्स हेतु)
- उद्देश्य- राजस्थान को एडवेंचर टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनाना, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करना और उच्चस्तरीय एथलीट तथा प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-

- वर्ष 2026 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान से दो शिक्षकों का चयन किया गया है। इन्हें 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

चयनित शिक्षक

- **डॉ. दिव्येंद्रु सेन : विद्यालय-** महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पंचपहाड़, झालावाड़
- विशेष योगदान- विद्यालय को डिजिटल लैब में बदलना, पेड़ों पर QR कोड लगवाना (हाइड्रोजन-मालवी में जानकारी), और छात्रों के साथ नासा (NASA) अभियान में एस्टेरॉयड की खोज।
- **डॉ. वर्तिका गुलाटी :** विद्यालय- राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चाकसू, जयपुर
- विशेष योगदान- स्मार्ट क्लास, ई-कंटेंट, दीक्षा पोर्टल और गतिविधि आधारित नवाचारी शिक्षण।

राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ-

- 1 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के दूधतलाई वन परिक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव शुभारंभ किया।
- **चंदन वन परियोजना-** मुख्यमंत्री ने उदयपुर के दूधतलाई वन परिक्षेत्र में चंदन का पौधा लगाकर 33 करोड़ रुपये की लागत वाली 'चंदन वन परियोजना' की शुरुआत की।
- प्रथम चरण- इसके तहत उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में चार चंदन वन विकसित किए जाएंगे। जिससे ग्रामीण आजीविका, जैव विविधता और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

मिशन हरियालो राजस्थान-

- आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य।
- पौधों की सुरक्षा के लिए जियो-टैगिंग और 'वन मित्र' तथा 'वृक्ष मित्र' के माध्यम से सतत निगरानी की व्यवस्था।

नमो नर्सरी एवं नमो वन-

- प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी और पंचायत समिति स्तर पर नमो वन विकसित किए जा रहे हैं।

जनजातीय एवं स्थानीय आजीविका प्रोत्साहन-

- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के तहत 13 जिलों के 600 स्वयं सहायता समूहों को 6 करोड़ रुपये की आजीविका प्रोत्साहन राशि का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया।

राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने चार टास्क फोर्स गठित की-

- 2 अगस्त, 2026 को राज्य में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने चार टास्क फोर्स का गठन किया।

मुख्य उद्देश्य-

- राज्य में निवेश एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
- निवेश प्रस्तावों का त्वरित क्रियान्वयन करना और परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना।

गठित की गई टास्क फोर्स-

- टेक्सटाइल सेक्टर टास्क फोर्स
- हैंडीक्राफ्ट सेक्टर टास्क फोर्स
- लॉजिस्टिक्स सेक्टर टास्क फोर्स
- एग्री, फूड एवं मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर टास्क फोर्स

जवाहर सर्किल में विकसित होगा रोज गार्डन आधुनिक नर्सरी एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स-

1. रोज गार्डन-

- क्षेत्रफल- लगभग 4,000 वर्गमीटर।
- गुलाब के पौधों की संख्या- कुल 4,000 पौधे
- उद्देश्य- "हरियालो राजस्थान" अभियान के तहत जयपुर के निवासियों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र विकसित करना और प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाना।

2. आधुनिक नर्सरी-

- क्षेत्रफल- लगभग 4,000 वर्गमीटर।
- पौधों की विविधता- 32 विभिन्न प्रजातियों के लगभग 3,000 पौधे।
- उद्देश्य- गुणवत्तापूर्ण पौधों का संरक्षण, संवर्धन और शहर में ग्रीन कवर को बढ़ावा देना।

3. अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स-

- विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जायेगा।
- उद्देश्य- युवाओं और उभरती खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच प्रदान करना तथा नागरिकों को स्वस्थ व सक्रिय जीवनशैली हेतु खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना।

कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस-2026 का भव्य समापन-



- हाल ही में 2 अगस्त, 2026 को जयपुर में आयोजित तीन दिवसीय 'कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस-2026' का समापन हुआ।

कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस-2026-

- आयोजन तिथि- 31 जुलाई से 2 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- होटल द ललित, जयपुर
- आयोजक-
 - राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
 - कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन
 - सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
 - निवारण (Mediators of the Supreme Court of India)

- उद्घाटन- मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा
- विषय- कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ
- अगला आयोजन- बहामास में
- उद्देश्य- विवादों के शांतिपूर्ण व त्वरित समाधान के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देना, वैश्विक न्यायिक सहयोग स्थापित करना और न्याय प्रणाली को अधिक जन-केंद्रित बनाना।

प्रमुख पहल और तथ्य-

- इस कॉन्फ्रेंस के समापन पर 'जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मीडिएशन-2026' को अंगीकृत किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने "न्याययान- द डिजिटल वे ऑफ जस्टिस" सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया।

अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में राजस्थान को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार-

- 3 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान को अंगदान संकल्प अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया।

प्रमुख उपलब्धि एवं राष्ट्रीय सम्मान-

- राजस्थान को "स्टेट अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस" से सम्मानित किया गया।
- 'अंगदान संकल्प अभियान' में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर रहा।
- शामिल औद्योगिक क्षेत्र- सीमेंट, सिरेमिक, डेयरी, बायोगैस संयंत्र, ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग, बैटरी निर्माण, डिस्टिलरी, धातु प्रसंस्करण, अस्पताल, होटल एवं रिसॉर्ट, निर्माण परियोजनाएं, औद्योगिक पार्क, अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधाएं।

वर्गीकरण का उद्देश्य या महत्त्व-

- राज्य में उद्योगों के लिए एक समान, वैज्ञानिक और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित होगी।
- उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृतियों एवं सहमति की प्रक्रिया में स्पष्टता रहेगी।
- अनावश्यक भ्रम को समाप्त कर पर्यावरणीय अनुपालना को अधिक सहज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान शीर्ष पर-

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान देश में सबसे अधिक 62.58 लाख किसानों को योजना से जोड़ा गया है।
- राज्य के कुल 2.82 करोड़ हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में से 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बीमित किया गया है (देश में सर्वाधिक)।
- राज्य का 36% फसली क्षेत्र बीमित है, जो राष्ट्रीय औसत (32%) से अधिक है। इस मामले में राजस्थान तीसरे स्थान (झारखंड, छत्तीसगढ़) पर है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-

- प्रारम्भ- वर्ष 2016 में
- प्रीमियम दरें-
 - खरीफ फसलें- 2.0 प्रतिशत
 - रबी फसलें- 1.5 प्रतिशत
 - वाणिज्यिक/बागवानी फसलें- 5.0 प्रतिशत
- विशेष सब्सिडी- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए प्रीमियम पर सरकार द्वारा विशेष/पूर्ण सब्सिडी दी जाती है।
- यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा देती है।
- इसमें प्रीमियम का भार किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वहन करते हैं।

उपज और वनस्पति प्रजाति की प्रसंस्करण इकाइयों को भी मिलेगा ओडीओपी नीति का लाभ-

- 'पंच गौरव' कार्यक्रम के तहत उपज और वनस्पति प्रजाति की प्रसंस्करण इकाइयों को 'राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024' के तहत मिलने वाले लाभ एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- उद्देश्य- स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुधार और बाजार पहुंच को बढ़ावा देना।
- एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 में किए गए प्रमुख संशोधन/सुधार-
 - मार्जिन मनी अनुदान- उद्यम विस्तार पर ₹20 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान।
 - तकनीकी उन्नयन- निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी सुधार के लिए ₹5 लाख तक अनुदान।



राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक



7 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। जिसमें निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये-



1. पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव ('वन स्टेट-वन इलेक्शन')

- **एक साथ चुनाव-** पंचायती राज और नगरय निकाय चुनाव 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की अवधारणा पर कराए जाएंगे।
- **आरक्षण लॉटरी-** राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया।



2. कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग नीति

- राज्य में कृषि/बागवानी में निवेश बढ़ाने, सप्लाई चेन मजबूत करने और किसानों की आय वृद्धि के उद्देश्य से राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को स्वीकृत किया गया।
- **ऋण पर अनुदान-** कृषि/खाद्य प्रसंस्करण और श्रीअन्न इकाइयों के लिए पूंजीगत अनुदान-
 - ₹50 लाख तक के ऋण पर 60 प्रतिशत
 - ₹50-100 लाख पर 50 प्रतिशत
 - ₹1 करोड़ से अधिक पर 40 प्रतिशत (अधिकतम ₹1.5 करोड़)
 - FPO, TSP क्षेत्रों, SC/ST और महिला उद्यमियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान।
- **राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026-** क्लस्टर आधार पर राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से चार श्रेणियों में फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
- **श्रीअन्न (मिलेड्स)-** श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए 'श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी' की स्थापना की जाएगी।



3. श्रम एवं रोजगार सुधार

- **मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम-2026-**
 - न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर साल में दो बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर) संशोधित किया जाएगा।
 - **कार्य के घंटे-**
 - ✓ सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे कार्य।
 - ✓ 6 दिवसीय कार्य सप्ताह में विश्राम सहित प्रतिदिन अधिकतम 10.5 घंटे।
 - ✓ हर 5 घंटे के बाद 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य।
 - 7वां दिन सबैतनिक अवकाश तथा अवकाश के दिन कार्य पर ओवरटाइम दर से वेतन।



4. पर्यावरण एवं ऊर्जा क्षेत्र के निर्णय

- **नवीकरणीय ऊर्जा भूमि आवंटन (संशोधन)-** सौर/पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए 10 प्रतिशत भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- **राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 (संशोधन)-**
 - बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए क्षमता आधारित स्लैब और पंजीकरण शुल्क में छूट।
 - पावर इवैक्यूशन की समय-सीमा 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की गई। (लक्ष्य- 2030 तक। 125 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा।



5. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- **'हर घर तिरंगा-2026' अभियान-**
 - राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 से 17 अगस्त तक प्रदेशभर में अभियान और तिरंगा यात्राएं आयोजित।

जयपुर को ई-बसों की सौगात-

- 11 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय, जयपुर से 'पीएम ई-बस सेवा' के तहत 16 ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- उद्देश्य- प्रदूषण-मुक्त (बिना धुएं और आवाज) और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- राजस्थान में ई-बसों की स्वीकृति व प्रगति-
 - वर्तमान तक प्रदेश के 8 शहरों में अब तक 110 पीएम ई-बसें प्राप्त हो चुकी हैं।
 - प्रथम चरण में आठ प्रमुख शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर) के लिए 675 ई-बसें स्वीकृत की गई थीं।
 - इनके अलावा राज्य सरकार के प्रयासों से 475 अतिरिक्त ई-बसें स्वीकृत की गई हैं।

जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की क्षमता संवर्धन कार्यशाला और पुरस्कार वितरण का आयोजन-

- 5 अगस्त, 2026 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- इसमें SBMG मोबाइल एप लॉन्च किया गया, जिसमें रियल-टाइम मॉनिटरिंग, फ्लोट ट्रेकिंग, फील्ड अटेंडेंस, योजनाएँ और वॉलंटियर मैनेजमेंट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

उत्कृष्ट जिलों का सम्मान-

- वर्ष 2025-26 की समग्र प्रगति के लिए पुरस्कार-
 1. श्रीगंगानगर (प्रथम स्थान)
 2. हनुमानगढ़ (द्वितीय स्थान)
 3. प्रतापगढ़ (तृतीय स्थान)
- प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 के लिए पुरस्कार-
 1. भीलवाड़ा (प्रथम स्थान)
 2. जयपुर (द्वितीय स्थान)
 3. हनुमानगढ़ (तृतीय स्थान)
- वेस्ट टू आर्ट (प्लास्टिक कचरा उपयोग) में राजसमंद जिले को प्रथम स्थान मिला है।

'राज निवेश' सिंगल विंडो सिस्टम का विस्तार-

- 13 अगस्त, 2026 को राज्य सरकार ने उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने तथा निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सिंगल विंडो सिस्टम 'राज निवेश' का विस्तार किया है।
- 'राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस (संशोधन) नियम, 2026' के तहत पोर्टल पर विभागों की संख्या 11 से बढ़ाकर 19 कर दी गई है।
- इसके माध्यम से अब 190 अनुमतियाँ और स्वीकृतियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी जो पहले 41 थीं।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर जेकेके में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित

- 7 अगस्त, 2026 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया।
- राज्य स्तरीय पुरस्कार-
 - प्रथम पुरस्कार- श्री कानाराम (डीगांव, जालोर)- कॉटन एवं सिल्क साड़ी के लिए
 - द्वितीय पुरस्कार- श्री सोहनराम (टांकला, नागौर)- कलात्मक दरी निर्माण के लिए
 - तृतीय पुरस्कार- श्रीमती धापूबाई (असनावर, झालावाड़)- तोता गागरौनी डबल बेडशीट के लिए

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान-

- बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र (आलिसरो की बस्ती) निवासी श्री बरीगा राम को उनकी उत्कृष्ट पट्टू साड़ी बुनाई कला के लिए 'राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार-2025' से सम्मानित किया गया।

राज्य में 300 करोड़ की लागत से बनेगा एआइ हब-

- स्थान- जोधपुर
- लागत- ₹300 करोड़
- नोडल संस्था- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार
- प्रबंधन मॉडल- चयनित एजेंसी द्वारा आगामी 5 वर्षों तक संचालन व रखरखाव।
- यह केवल पारंपरिक डेटा बैकअप केंद्र न होकर एआई कंप्यूट क्षमता से युक्त एकीकृत सेंटर होगा।

राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक



13 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। जिसमें निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये-



1



द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026 (प्रावधान)-

- 29 वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण- राज्य वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, बरगद, पीपल, महुआ और कैर सहित 29 प्रजातियों की अवैध कटाई पर रोक।
- गैर-वन भूमि पर बिना अनुमति पेड़ काटने पर 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
- पेड़ हटाने पर उसी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में नए पौधे लगाना अनिवार्य होगा।

2



राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल-2026 (प्रावधान)-

- दायरा- विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों का सरलीकरण। अनुसूचित जनजातियों और संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्गों को इससे बाहर रखा गया है।
- विवाह एवं लिव-इन-
 - विवाह का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य; बहुविवाह पर रोक।
 - लिव-इन संबंधों की शुरुआत व समापन का पंजीकरण/लिखित सूचना अनिवार्य।
 - पंजीकरण न कराने पर 10,000 रुपये तक और अनदेखी करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना।
- उत्तराधिकार नियम- पुत्र-पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार।

3



ग्रामीण जलापूर्ति संचालन एवं संधारण नीति-

- जल जीवन मिशन 2.0- 19 घटकों को शामिल कर ग्राम पंचायत, क्लस्टर समिति, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है।
- वित्तीय प्रबंधन- टाइड फंड, राज्य वित्त आयोग, सांसद/विधायक निधि और डीएमएफटी फंड से रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

4



कार्मिक एवं सैनिक कल्याण संबंधी निर्णय

- 1971 युद्ध के शहीद परिवार- ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान घायल होकर 31 अक्टूबर 1972 तक वीरगति पाने वाले 35 जवानों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का हक।
- अनुकंपा नियुक्ति में दायरा बढ़ा- मृतक सरकारी कर्मचारी की 'पुत्र वधू' को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया गया।
- पदोन्नति व आरक्षण- वर्ष 2026-27 के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट; दिव्यांग कर्मचारियों को 30 जून 2016 से पदोन्नति में 4 प्रतिशत नोशनल बेंनेफिट।
- मातृत्व व चाइल्ड केयर लीव- एकल महिला कर्मचारियों को साल में 6 चरणों में CCL; सरोगेसी मामलों में सरोगेट मदर को 180 दिन तथा कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश।

5



औद्योगिक एवं अक्षय ऊर्जा भूमि आवंटन

- अल्ट्राटेक सीमेंट- जैसलमेर के पारेवर में 306 हेक्टेयर भूमि आवंटित।
- अक्षय ऊर्जा- बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में सौर व विंड-सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन।
- काश्तकार पुनर्वास- जैसलमेर के नाचना-1 (ग्राम चिन्नु) में एस्केप जलाशय निर्माण से प्रभावित 21 गैर-खातेदार काश्तकारों को पुनर्वास हेतु भूमि आवंटित।

राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 14 को पुलिस पदक-

- राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस-2026 की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस पदकों से अलंकृत किया गया।

राष्ट्रपति पुलिस पदक (विशिष्ट सेवाएं)-

1. श्री सुरेंद्र सिंह राणावत - सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), अमेर
2. श्री महेंद्र कुमार भगत - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ए.एसपी), सीआईडी विशेष शाखा

पुलिस पदक (सराहनीय सेवाएं)-

1. श्री सुमित गुप्ता - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी एसएसबी, जयपुर
2. श्रीमती दीक्षा कामरा - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी एसएसबी, गंगानगर
3. श्रीमती सज्जन कंवर - पुलिस निरीक्षक, सीआईडी 'क'
4. श्री शेरू खान - उप निरीक्षक, अपराध शाखा, जिला जालौर
5. श्री महेश चंद - सहायक उप निरीक्षक, अपराध शाखा, भरतपुर
6. श्री शिवराम - सहायक उप निरीक्षक, एमआईयू, सागवाड़ा, डूंगरपुर
7. श्री कुंजन शर्मा - सहायक उप निरीक्षक, प्रशिक्षण शाखा दूरसंचार, जयपुर
8. श्री ओम सिंह - हेड कांस्टेबल-07, एसडीआरएफ, जयपुर
9. श्री पूरन बहादुर - कांस्टेबल-981, प्रथम बटालियन आरएसी, जोधपुर
10. श्री नरेंद्र सिंह - कांस्टेबल-603, तृतीय बटालियन आरएसी, बीकानेर
11. श्री रामचंद्र सिंह - कांस्टेबल-478, एसपी ऑफिस, जोधपुर ग्रामीण
12. श्रीमती मंजू कुमारी - कांस्टेबल-71, आरपीए, जयपुर
13. श्री अजय कुमार - कांस्टेबल-641, एसपी ऑफिस, नागौर
14. श्री गुरमेल सिंह - कांस्टेबल चालक-1291, पुलिस लाइन, हनुमानगढ़

अटल गौरव स्मृति समारोह और केन्द्रीय गृह मंत्री का राजस्थान दौरा-

- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अगस्त, 2026 को चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया।

अन्य परियोजनाएं एवं वित्तीय सौगातें-

- 17 जिलों को विकास सौगात- 6,453 करोड़ रुपये की कुल लागत से 954 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
- किसान सम्मान निधि- मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के रूप में 66.74 लाख से अधिक किसानों के खातों में 667 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित किये।
- रोजगार उत्सव- 10वें मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत प्रदेश भर में 10,548 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
- अलवर चौक नामांतरण- अलवर के 'भूगोर तिराहे' का नाम बदलकर 'कप्तान छोट्टनलाल मीणा चौक' करने की घोषणा की गयी।

- अलवर सरस डेयरी नवीन प्लांट- 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 3 लाख लीटर/दिन क्षमता के नए प्लांट का शिलान्यास किया गया तथा भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में 4 नए डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट्स की शुरुआत की गयी।
- गोदाम निर्माण- प्रदेश में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 200 गोदामों का निर्माण प्रगति पर, 50 नए गोदाम और स्वीकृत किए गए।

राज्य के हाटों का पीपीपी मॉडल पर होगा संचालन-

- राज्य के पारंपरिक दस्तकारों, बुनकरों, महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और लघु उद्यमियों को आधुनिक विपणन मंच एवं उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य के हाटों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की घोषणा की है।
- यह मुख्यमंत्री द्वारा 27 जून, 2026 को की गई घोषणा के क्रम में राज्य के 4 प्रमुख हाटों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित किया जाएगा जो निम्न है-
 1. अलवर हाट
 2. पुष्कर हाट
 3. जैसलमेर हाट
 4. नाथद्वारा हाट

“राजसखी पंच गौरव रथ” की शुरुआत-

- 16 अगस्त, 2026 को राजीविका, जयपुर द्वारा ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने और उनके स्वदेशी उत्पादों को सीधा बाजार उपलब्ध कराने हेतु “राजसखी पंच गौरव रथ” की शुरुआत की गई है।
- स्थान- एसआईएम, दुर्गापुरा, जयपुर

परफोर्मेंस के आधार पर जिला क्रय विक्रय सहकारी समितियों की रैंकिंग जारी-

- 17 अगस्त, 2026 को सहकारिता विभाग ने राज्यभर की क्रय विक्रय सहकारी समितियों का कार्य के आधार पर आकलन कर ग्रेडिंग प्रदान की है।

रैंकिंग-

- **जिला श्रेणी-**
 - प्रथम स्थान - कोटा जिला क्रय-विक्रय सहकारी समिति
 - द्वितीय स्थान - कोटपूतली-बहरोड़ जिला क्रय-विक्रय सहकारी समिति
 - तृतीय स्थान - चित्तौड़गढ़ जिला क्रय-विक्रय सहकारी समिति
- **व्यक्तिगत श्रेणी-**
 - प्रथम स्थान - परबतसर
 - द्वितीय स्थान - खींवसर
 - तृतीय स्थान - सांगोद

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने 51वें ईजीपीए वार्षिक सम्मेलन में दिया अध्यक्षीय संबोधन-

- राजस्थान के मुख्य सचिव एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS) के अध्यक्ष श्री वी. श्रीनिवास रोम (इटली) में आयोजित 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक सम्मेलन-

- संस्करण- 51वां
- आयोजन तिथि- 24 से 27 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- सैपिएन्जा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, इटली।
- अध्यक्षीय संबोधन- श्री वी. श्रीनिवास द्वारा
- विषय- “Public Governance for the Common Good: Human Intelligence Serving the Global Community”

- भागीदारी- 70 से अधिक देशों से 600 से अधिक प्रतिनिधि और विशेषज्ञ
- नोट- जून, 2025 में श्री वी. श्रीनिवास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS) के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने थे।

‘गोट सीमन लैब’

- अजमेर के रामसर स्थित राजकीय पशु प्रजनन फार्म में भारत की सबसे बड़ी उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।

लागत व बजट-

- परियोजना की कुल लागत ₹875 लाख (8.75 करोड़ रुपये) है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत
- राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत
- **उत्पादन क्षमता-** प्रतिवर्ष 2 लाख सीमन डोजेज तैयार की जाएंगी।

योजना-

- यह केंद्रीय प्रवर्तित योजना- नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत स्थापित की जा रही है।
- प्रयोगशाला को विश्वस्तरीय बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश के ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान’ के साथ समझौता किया है।

उद्देश्य और लाभ-

- गांवों तक पशुपालकों के घर पर ही बकरियों में उच्च गुणवत्ता वाले सीमन कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध होगी।
- राजस्थान की प्रमुख बकरी नस्लों जैसे- सिरौही, मारवाड़ी और जखराना के आनुवंशिक सुधार में मदद मिलेगी।
- वैज्ञानिक पद्धति से सीमन तैयार होने से संक्रामक और आनुवंशिक बीमारियों के फैलने की संभावना कम होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य-

- राजस्थान में लगभग 2 करोड़ बकरियां हैं, जो भारत की कुल बकरी आबादी का 16 प्रतिशत है।
- बकरियों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है।

महोत्सव/सम्मेलन/अभियान/आपरेशन

नेशनल मस्टर्ड डे 2026-

- संस्करण- द्वितीय
- आयोजन तिथि- 31 जुलाई, 2026
- आयोजन स्थल- राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर
- आयोजक- फिक्की और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
- इसमें सरसों उत्पादन में तकनीक-आधारित विकास, किसानों का सशक्तिकरण और सरसों के इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया।

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैटर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन-

- संस्करण- छठवां
- आयोजन तिथि- 1 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा, जयपुर।
- मुख्य अतिथि- वासुदेव देवनानी (राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष)
- इस सम्मेलन में स्मारिका का विमोचन किया गया।

राजिसाकॉन-2026-

- संस्करण- 27वां
- आयोजन तिथि- 1 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- जॉलिवुड रिसोर्ट, पुष्कर (अजमेर)
- आयोजक- इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स राजस्थान स्टेट ब्रांच एवं एनेस्थीसियोलॉजी विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर
- मुख्य अतिथि- वासुदेव देवनानी

अपना संकुल हरियालो संकुल अभियान-

- प्रारम्भ- 3 अगस्त, 2026
- इस अभियान का शुभारंभ शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, राजस्थान में किया।

एग्रीविजन के नॉर्थ वेस्ट जोन की कॉन्फ्रेंस-

- संस्करण- द्वितीय
- आयोजन तिथि- 8 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- राजस्थान कृषि महाविद्यालय (महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध), उदयपुर
- राज्यपाल ने एग्रीविजन की स्मारिका और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया।

जल संचयन संकल्प कार्यक्रम-

- आयोजन तिथि- 9 अगस्त, 2026
- आयोजक- विश्व आदिवासी दिवस पर ग्रामीण विकास एवं शोध परिषद
- इस कार्यक्रम को राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने संबोधित किया।
- भारत में जल संकट के सन्दर्भ में तथ्य-
 - वर्तमान में देश की लगभग 60 करोड़ आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है।
 - भारत दुनिया की 17% आबादी का भरण-पोषण करता है, लेकिन उसके पास वैश्विक ताजे पानी का केवल 4% हिस्सा उपलब्ध है।
 - वैश्विक स्तर पर निकाले जाने वाले कुल भूजल का लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत द्वारा निकाला जाता है।

प्रवासी राजस्थानी संगम-

- आयोजन तिथि- 9 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- बेंगलुरु में
- इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की।

विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी-

- आयोजन तिथि- 10 से 12 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- एमआईटीआरसी कॉलेज, अलवर
- उद्घाटनकर्ता- संजय शर्मा (वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार))
- उद्देश्य- विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा एवं नवाचार की भावना को विकसित करना।

तीज उत्सव-2026-

- आयोजन तिथि- 15 से 24 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- बीकानेर हाउस प्रांगण, नई दिल्ली
- यह उत्सव राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, हस्तशिल्प और खान-पान को जीवंत रूप प्रदान करता है।

चर्चित व्यक्ति/स्थान/अन्य

मोती लाल-

- यह मौजमाबाद, जयपुर के प्रगतिशील किसान है।
- इनको कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 'किसान ब्रांड एम्बेसडर' एवं ट्रेनर नियुक्त किया गया है।
- यह राज्यभर में आयोजित प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं और किसान संवाद कार्यक्रमों में किसानों को मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैविक कृषि पद्धतियों और टिकाऊ कृषि तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान देंगे।

महेंद्र शास्त्री-

- यह अलवर के दिग्गज नेता, कवि एवं साहित्यकार और पूर्व विधायक थे, जिनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने वर्ष 1985 लोकदल के टिकट पर मुंडावर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था।

नेहा सोलंकी-

- यह साइकोलॉजिस्ट है जो नागौर जिले की मूल निवासी है।
- इनको सामाजिक नवाचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रासरूट इनोवेटर रिकॉग्निशन-2026 से सम्मानित किया है।
- नेहा ने सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष सहायक कुर्सी तैयार की, जिससे वे सामान्य गतिविधियों से जुड़ने में सक्षम हो सकते हैं।

नीरज डांगी-

- यह राजस्थान से राज्य सभा में सांसद हैं। इनको कांग्रेस ने राज्यसभा में पार्टी का नया व्हिप/सचेतक नियुक्त किया है।

विकास पाठक-

- यह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है। इनको केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर का महानिरीक्षक (आइजी) नियुक्त किया है।

डॉ. सीपी जोशी-

- राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से राजस्थान क्रिकेट में योगदान के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सीपी जोशी को राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा।
- डॉ. सीपी जोशी के राजस्थान क्रिकेट संघ अध्यक्ष रहते राजस्थान की रणजी टीम वर्ष 2011 और 2012 में लगातार दो बार चैंपियन बनी।

महेंद्र चौधरी-

- यह सीपीआइ (माले) लिबरेशन के पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य और राजस्थान के पूर्व राज्य सचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया।

डॉ. रवि बापना-

- यह जयपुर के मूल निवासी, एआइ और डेटा एनालिटिक्स व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के विशेषज्ञ है। इनको कैलिफोर्निया स्थित सान्टा क्लारा विश्वविद्यालय ने डीन (अध्यक्ष) नियुक्त किया है।
- वे 1 सितम्बर से पदभार संभालेंगे।

गोपाल लाल धोबी-

- यह राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायक थे जिनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होने वर्ष 2003 में कांग्रेस के बाबूलाल सिंघारिया को हराकर राजस्थान विधानसभा में केकड़ी का प्रतिनिधित्व किया था।

शहराह-द रॉयल रूट-

- यह जयपुर के फिल्म निर्माता राहुल सूद द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसका 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल में चयन हुआ है।
- यह फेस्ट 25 से 30 सितंबर, 2026 तक तिरुवनंतपुरम में होगा।

खेल/खेल व्यक्तित्व

42वीं सब-जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप-

- आयोजन तिथि- 6 अगस्त से 9 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- सवाई मानसिंह स्टेडियम तरणताल, जयपुर
- आयोजक- राजस्थान तैराकी संघ द्वारा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में
- प्रतिभागी- लगभग 550 युवा तैराक (बालक और बालिकाएं)
- कर्नाटक ने 4 में से 3 चैंपियनशिप जीतीं और तमिलनाडु ने एक चैंपियनशिप जीती।
- तमिलनाडु के दिवाश्री केशवन ओर मोहम्मद हफीज चैंपियनशिप के सबसे सफल तैराक रहे। इन दोनों ने 5-5 गोल्ड जीते।
- राजस्थान के 8 तैराकों ने 17 इवेंट में हिस्सा लिया, लेकिन एक भी मेडल जीतने में सफल नहीं रहा।

राज्य जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता-

- आयोजन तिथि- 2 से 4 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- धौलपुर
- आयोजक- राजस्थान फुटबॉल संघ
- परिणाम-
 - विजेता- धौलपुर
 - उपविजेता- उदयपुर
 - तीसरा स्थान- अजमेर

कमलेश शर्मा-

- हाल ही में इनको उदयपुर में सम्पन्न राजस्थान वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के चुनावों में सर्वसम्मति से राजस्थान वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है।

वान्या बोहरा-

- यह धौलपुर निवासी आइस स्केटिंग खिलाड़ी है। इन्होंने एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है।

हर्षिता जाखड़-

- यह राजस्थान की 19 वर्षीय साइक्लिस्ट है।
- हर्षिता जाखड़ टूर डी फ्रांस फेम्स के मंच पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला साइक्लिस्ट बन गई हैं।

अदिति चौधरी-

- यह जयपुर निवासी है। इन्होंने मिसेज ओशन इंडिया-2026 का खिताब जीता है।
- वह मिसेज ओशन वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

जयेंद्र चतुर्वेदी-

- यह जयपुर के अंतरराष्ट्रीय चेस खिलाड़ी और अनुभवी अंपायर है। इन्होंने एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप (16-26 अगस्त, 2026) में अंपायरिंग की है।
- इससे पहले भी इन्होंने वेस्टर्न एशियन यूथ चैंपियनशिप, एशियन चेस चैंपियनशिप और अबू धाबी ग्रैंडमास्टर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी अंपायरिंग की हैं।

रुद्रांश खंडेलवाल-

- यह राजस्थान के पैरा निशानेबाज है जो भरतपुर जिले के निवासी है। इनको युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2025 के तहत अर्जुन अवॉर्ड देने की घोषणा हुई है।

प्रखर असावा-

- जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब के खिलाड़ी है। इन्होंने कर्नाटक के कोलार स्थित जायन हिल्स गोल्फ काउंटी में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट में 9वां स्थान हासिल किया।

संध्या विश्नोई

- यह भीलवाड़ा जिले की कुश्ती की खिलाड़ी है। इन्होंने अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में 46 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है।

बसंत कुमार मेघवाल-

- यह राजस्थान के एथलेटिक्स है। इन्होंने अमेरिका के ओरेगन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 पुरुषों की हाई जंप चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है।

विविध तथ्य

- राज्य में 15 अगस्त, 2026 से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, बिक्री, परिवहन और उपयोग पर रोक हेतु व्यापक जनजागरूकता एवं प्रवर्तन (Enforcement) अभियान शुरू हुआ।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली को परिभाषित करने के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति ने राजस्थान के चयनित अरावली जिलों का 7 से 10 अगस्त, 2026 तक फील्ड दौरा किया।
- राज्य सरकार द्वारा उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव में देश की पहली समर्पित लेक्रोस अकादमी विकसित की गई है।
- 9 अगस्त, 2026 को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल से 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का शुभारंभ किया।
- 'महिला सुरक्षा संकल्प' कार्यक्रम- 12 अगस्त, 2026 को अजमेर स्थित मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से इस विशेष कार्यक्रम को संचालित किया गया था।
- हाल ही में आबूरोड के डेरी, बसंतगढ़ और आसपास के क्षेत्र में कॉपर, लेड, जिंक और एसोसिएटेड खनिजों के प्रारंभिक संकेत मिले हैं।
- 17 अगस्त, 2026 को म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्वाइंग जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वह रूस की यात्रा पर जाते समय विमान में ईंधन भरवाने (फ्यूलिंग) के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे।
- 18 अगस्त, 2026 को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की 11वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शासन सचिवालय में आयोजित की गई।
- 20 अगस्त, 2026 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कैंसर उपचार के लिए अत्याधुनिक कार-टी सेल थेरेपी को अनुमत पैकेज में शामिल किया है।
- अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी को राजस्थान के कोटा जिले में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।
- राजस्थान 60 आईएस के लिए कर्मयोगी मिशन चलाने वाला पहला स्टेट बन गया है।
- केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया है।

■■■■■

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

प्रधानमंत्री का उज्बेकिस्तान दौरा

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 अगस्त, 2026 को उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे।

यात्रा के परिणाम व घोषणाएँ-

■ सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर सहयोग-

- टर्मेज़ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थलों (फयाज़ टेपा और कारा टेपा) के संरक्षण व जीर्णोद्धार के लिए आशय पत्र।
- भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और उज्बेकिस्तान की 'उज़ारआर्काइव' एजेंसी के बीच अभिलेखीय कार्य में सहयोग।



■ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा- आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता।

■ पर्यटन, शिक्षा एवं कूटनीति-

- पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए वर्ष 2026-28 का साझेदारी कार्यक्रम।
- उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
- सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (भारत) और उज्बेकिस्तान कूटनीतिक अकादमी के बीच साझेदारी।

■ आर्थिक, वित्तीय एवं प्रांतीय संबंध-

- गुजरात राज्य (भारत) और समरकंद क्षेत्र (उज्बेकिस्तान) के बीच अंतर-प्रांतीय साझेदारी समझौता।

■ प्रमुख रणनीतिक व विकास संबंधी घोषणाएं-

- साझेदारी का विस्तार- द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा देना।
- डिजिटल भुगतान- NIPL (NPCI) और उज्बेकिस्तान के NIPC के बीच वाणिज्यिक समझौता, जिससे भारतीय UPI ऐप्स उज्बेकिस्तान के UzQR को स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे।
- पर्यावरणीय अनुदान- अरल सागर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं पारिस्थितिक सुधार के लिए भारत द्वारा 10 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता।

■ शैक्षणिक व भाषाई प्रोत्साहन-

- हिंदी भाषा के लिए 100 'लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्तियों' की घोषणा।
- ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में ICCR संस्कृत चेयर की स्थापना।

- Note- प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ओली दाराजली डस्टलिक' से सम्मानित किया गया।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता

- हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच 7 अगस्त, 2026 को सऊदी अरब के मक्का स्थित अल-सफा पैलेस में त्रिपक्षीय रक्षा समझौता हस्ताक्षरित हुआ है।
- यह समझौता सितंबर, 2025 के सऊदी-पाकिस्तान द्विपक्षीय रक्षा समझौते का विस्तार करते हुए तुर्किये को शामिल कर एक अंतर-क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के रूप में है।



■ विशेषताएँ एवं प्रावधान-

- सामूहिक रक्षा का सिद्धांत- इसके तहत, हस्ताक्षरकर्ता तीन देशों में से किसी एक देश पर भी सशस्त्र हमला होने की स्थिति में उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर से संबद्धता- इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 (व्यक्तिगत एवं सामूहिक आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार) के तहत स्थापित किया गया है।
- सैन्य एवं तकनीकी समन्वय- तीनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच नियमित संयुक्त अभ्यास, खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान, लॉजिस्टिक्स सहयोग और सैन्य प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है।
- विस्तार का विकल्प- समझौते में अन्य इच्छुक देशों के जुड़ने के लिए भी द्वार खुले रखे गए हैं।

■ सहभागी देशों की रणनीतिक भूमिकाएँ-

देश	रणनीतिक शक्ति एवं हित
सऊदी अरब	□ वित्तीय संसाधन- अमेरिका पर पारंपरिक रक्षा निर्भरता को कम कर अपनी रणनीतिक साझेदारियों में विविधीकरण लाना और क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करना।
तुर्किये	□ उन्नत रक्षा उद्योग- अपने स्वदेशी सैन्य उपकरणों (ड्रोन, मिसाइल, नौसैनिक प्रणालियों) के लिए खाड़ी बाजार का विस्तार करना और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना।
पाकिस्तान	□ सैन्य जनशक्ति व अनुभव- परमाणु क्षमता एवं सैन्य जनशक्ति के बल पर स्वयं को क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करना तथा वित्तीय/कूटनीतिक समर्थन हासिल करना।

■ भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ-

- सऊदी-भारत संबंधों का संतुलन- भारत के सऊदी अरब के साथ प्रगाढ़ आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संबंध हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य निकटता के बीच भारत को अपने कूटनीतिक संतुलन को सतर्कता से बनाए रखना होगा।
- तुर्किये-पाकिस्तान रक्षा साझेदारी- तुर्किये द्वारा पाकिस्तान को उन्नत सैन्य तकनीकों (जैसे कॉम्बैट ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम) के हस्तांतरण से भारतीय सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं।
- पश्चिम एशिया में नया शक्ति-संतुलन- इस समझौते से खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र के सुरक्षा समीकरणों में बदलाव आ सकता है, जिससे भारत के समुद्री व्यापार, ऊर्जा गलियारे और प्रवासी सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं।

संक्षिप्त न्यूज

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ओंटारियो झील का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने के लिए कार्यकारी आदेश हस्ताक्षरित किया है।
- नेपाल में नेपाल-तिब्बत सीमा पर हिमनद ढहने से भोटे कोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में विनाशकारी फ्लैश फ्लड के कारण तिब्बत और नेपाल को विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ा।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) का सम्मेलन-

- कॉप सम्मेलन- 17वां
- आयोजन तिथि- 17 अगस्त से 28 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- उलानबटार, मंगोलिया
- विषय- Restoring Land. Restoring Hope

सम्मेलन का उद्देश्य और प्राथमिकताएं

- भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से मुकाबला-
 - दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत भूमि क्षरण से प्रभावित है।
 - कॉप-17 का लक्ष्य मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक निवेश और रणनीतिक समाधानों को बढ़ाना था।
- चारागाह और पशुपालक वर्ष 2026-
 - वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है।
 - सम्मेलन में चारागाहों के स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और इस पर निर्भर लगभग 50 करोड़ पशुपालकों की आजीविका पर विशेष ध्यान दिया गया।
- खाद्य, जल और राष्ट्रीय सुरक्षा-
 - उपजाऊ भूमि की कमी से खाद्य व जल संकट बढ़ता है।
 - सम्मेलन में भूमि-जल संबंधों को मजबूत करने और ग्रामीण आबादी के विस्थापन को रोकने पर रणनीतिक चर्चा की गयी।
- मेजबान देश (मंगोलिया) की राष्ट्रीय पहलें-
 - मंगोलिया की लगभग 77 प्रतिशत भूमि क्षरण की समस्या से प्रभावित है।
 - बिलियन ट्रीज नेशनल कैम्पेन- 2030 तक 1 अरब पेड़ लगाने का राष्ट्रीय लक्ष्य।
 - Youth4Land- युवाओं की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय मंच।
 - Business4Land- स्थायी भूमि प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की पहल।
- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD)
 - स्थापना- 1994
 - सदस्य- 197 देश
 - यह पर्यावरण और सतत भूमि प्रबंधन को जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
 - लक्ष्य क्षेत्र- शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र (जहाँ सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं।)



संक्षिप्त न्यूज

- हाल ही में भारत और नेपाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़ी आठ नई परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं। इनकी लागत करीब 80.3 करोड़ नेपाली रु. है।
- अमरीका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 15 अगस्त को 'भारत दिवस' घोषित किया है।
- उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सईदोव बख्तियार ओदिलोविच ने 3 अगस्त, 2026 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन

- संस्करण- 26वां
- आयोजन तिथि- 31 अगस्त से 1 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- बिश्केक, किर्गिस्तान
- विषय- SCO के 25 वर्ष: सतत शांति, विकास और समृद्धि की ओर साथ-साथ
- इस शिखर सम्मेलन में इसके 10 सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
- इस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रयास, कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा सहयोग, साइबर अपराध, संगठित अपराध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर सहमती बनी।
- भारत के लिए महत्व- भारत को चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ एक साथ जुड़ने और संवाद करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- **शंघाई फाइव-**
 - स्थापना- वर्ष 1996 में
 - उद्देश्य- सीमा विवादों के समाधान करना।
 - संस्थापक सदस्य देश- चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान
 - इसमें वर्ष 2000 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था।
- **शंघाई सहयोग संगठन-**
 - स्थापना- 15 जून, 2001
 - वर्तमान सदस्य- 10 देश
- **सदस्यता का विस्तार-**
 - वर्ष 2017 में- भारत और पाकिस्तान
 - वर्ष 2023 में- ईरान
 - वर्ष 2024 में- बेलारूस



रूस-यूक्रेन बैंक विवाद में डीवाई चंद्रचूड़ बने आर्बिट्रेटर-

- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक ओश्रादबैंक के साथ चल रहे एक बहु-मिलियन डॉलर के अंतरराष्ट्रीय निवेश संधि विवाद में अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है।

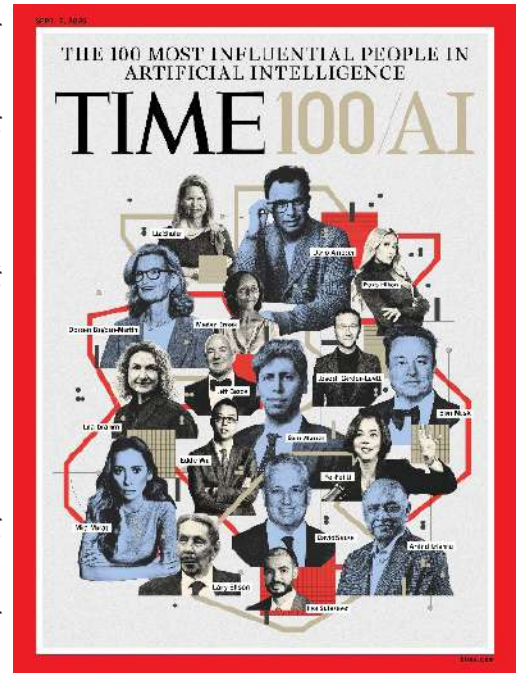


विवाद का मुख्य कारण-

- यूक्रेन के राज्य-स्वामित्व वाले ओश्रादबैंक का आरोप है कि 2022 के सैन्य संघर्ष के बाद डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ापोरिजिया क्षेत्रों में उसकी बैंकिंग शाखाओं, एटीएम और परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया या उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया।
- बैंक ने 1998 के रूस-यूक्रेन द्विपक्षीय निवेश समझौते और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत रूस के खिलाफ सैकड़ों मिलियन डॉलर के नुकसान का दावा पेश किया है।
- इस विवाद के समाधान के लिए तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है-
 1. डायला जिमेनेज
 2. डी.वाई. चंद्रचूड़
 3. स्टावरोस ब्रेकूलाकिस

टाइम-100 एआई 2026 लिस्ट-

- टाइम मैगजीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में 2026 में सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाले 100 दिग्गजों की लिस्ट जारी की है।
- इस लिस्ट में चार अलग-अलग श्रेणियों में दस प्रभावशाली भारतीयों ने जगह बनाई है।



लीडर्स-

- अरविंद कृष्णा- आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ (बिजनेस सिस्टम में एआई को बढ़ावा देने के लिए)।
- अरविंद रमन- निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, अमेरिका (एआई सुरक्षा और मानक तैयार करने के लिए)।

इनोवेटर्स

- संजय मेहरोत्रा- माइक्रोन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और सीईओ (एआई हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर तकनीक)।
- विवेक राघवन- सर्वम एआई के सह-संस्थापक (भारतीय भाषाओं के अनुकूल एआई टूल्स का विकास)।
- उत्कर्ष सक्सेना- अदालत एआई के सह-संस्थापक और सीईओ (भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एआई टूल्स)।
- अनिमा आनंदकुमार- कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर (एआई आधारित वैज्ञानिक मॉडलिंग)।
- सुची सारिया- बाइसियान हेल्थ की संस्थापिका और सीईओ (हेल्थकेयर में बीमारियों की शुरुआती पहचान के लिए एआई)।

शेपर्स-

- सनी गांधी- एनकोड के सह-कार्यकारी निदेशक (जिम्मेदार एआई इस्तेमाल और युवाओं की भागीदारी)।
- मिताली जैन- टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट की कार्यकारी निदेशक (कानूनी जवाबदेही और एआई गवर्नेंस)।

थिंक्स-

- रवि कुमार एस.- कॉग्रिजेंट के सीईओ (वैश्विक कॉर्पोरेट जगत में एआई तकनीक अपनाने के लिए)।

सेउटा शहर-

- यह स्पेन का स्वायत्त शहर है जिसमें हाल ही में प्रवासन संकट देखा गया है।
- यहाँ से लगभग 60,000 प्रवासियों ने स्पेन के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया था।

फ्यूगो ज्वालामुखी-

- यह सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में स्थित सक्रिय फ्यूगो ज्वालामुखी है।
- इसमें हाल ही में भीषण विस्फोट हुआ है।

इंचियोन एयरपोर्ट-

- यह दक्षिण कोरिया का एयरपोर्ट है।
- यह वर्ष 2026 की पहली छमाही में 3.84 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया।
- लंदन का हीथ्रो दूसरा और सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट तीसरा व्यस्त एयरपोर्ट रहा है।

संक्षिप्त न्यूज

- अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक' की सूची से हटा दिया है।
- थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 17 से 19 अगस्त, 2026 तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा की है।
- हाल ही में प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश नाउरू ने अपना नाम 'रिपब्लिक ऑफ नाओएरो' कर लिया है। यह देश वेटिकन सिटी, तुवालु के बाद तीसरा सबसे कम आबादी वाला देश है।
- नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन 10 से 13 अगस्त, 2026 तक मॉरीशस की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा भारत के द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूती देने और हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार मॉरीशस के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
- ई-वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत प्रवेश को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने 11 अंतरराष्ट्रीय पोर्ट जोड़ने की अधिसूचना जारी की है।
- लेबनान की संसद ने फांसी की सजा खत्म करने वाला कानून पारित कर दिया। लेबनान पश्चिम एशिया का पहला देश बन गया, जिसने फांसी औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है।
- हाल ही में यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून 'ईयू एआई एक्ट' को पूर्णतः लागू कर दिया है।

ऑफलाइन व LIVE FROM CLASSROOM

बैच प्रारम्भ

RAS

FOUNDATION



Samyak
An Institute For Civil Services



**FREE
03 DAYS
DEMO
CLASSES**

COURSE FEATURES

 विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज	 ई-नोट्स/ प्रिंटेड बुकलेट्स
 पर्सनल मेंटरशिप	 टेस्ट सीरीज
 लाइब्रेरी सुविधा	 लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेज

हिन्दी माध्यम @ 8 AM TO 1 PM

ENGLISH MEDIUM @ 3 PM TO 7 PM

राष्ट्रीय परिदृश्य

प्रधानमंत्री का आंध्र प्रदेश का दौरा और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास-

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अगस्त, 2026 को आंध्रप्रदेश के विजयनगरम् जिले के भोगापुरम में 17,900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
- प्रमुख विकास परियोजना-
 - भोगापुरम में नए हवाई अड्डे का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखने की घोषणा की गई।
 - विशाखापत्तनम से कृष्णपट्टनम तक बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मुलापेटा व रामायपट्टनम में नए बंदरगाहों के निर्माण से एकीकृत तटीय आर्थिक गलियारा विकसित किये जाने घोषणा की गयी।
 - विशाखापत्तनम में नए सेमीकंडक्टर संयंत्र का शिलान्यास किया गया।
 - विशाखापत्तनम आर्थिक क्षेत्र को एशिया के अग्रणी आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य उल्लेखित किया गया।
 - धीमसा नृत्य विश्व रिकॉर्ड- 13,000 से अधिक जनजातीय बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक 'धीमसा नृत्य' ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है।

आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन-

- 3 अगस्त, 2026 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया।
- यह सेंटर करघा आधुनिकीकरण, श्रमिक कार्यक्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टिकाऊपन, कार्यात्मक नवाचार और डिजिटल तकनीकों में शोध को बढ़ावा देगा।

अन्य प्रमुख पहल-

- **हैंडलूम 4.0 मोबाइल ऐप-** यह कारखाने/करघे की उत्पादकता, गुणवत्ता, रखरखाव और स्थिरता की डिजिटल मॉनिटरिंग सक्षम करेगा।

- **हैंडलूम e-विद्या-** यह हैंडलूम पारिस्थितिकी तंत्र में क्षमता निर्माण के लिए एक समग्र डिजिटल लर्निंग और नॉलेज प्लेटफॉर्म है।

- **HandloomX-** यह एक एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेशन प्लेटफॉर्म जो मंत्रालय की 5F वैल्यू चेन में काम कर रहे स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स का समर्थन करेगा।

- **कलागृह हैंडलूम स्टूडियो (GenZ डिज़ाइन स्टूडियो)-** यह कस्टमाइज़ेशन और विज़ुअलाइज़ेशन के माध्यम से समकालीन उपभोक्ताओं को प्रामाणिक हैंडलूम उत्पादों से जोड़ने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करेगा।

- **श्रेड्स ऑफ वलर-** यह एक स्थिरता पहल है जो वैज्ञानिक रूप से रीसायकल किए गए रक्षा वस्त्रों को कुशल शिल्पकलाओं के साथ प्रीमियम हैंडलूम फैब्रिक्स में परिवर्तित करती है।

गोबरधन योजना-



- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबरधन योजना को मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना-गोबरधन

- अनुमोदन वर्ष- अगस्त, 2026
- वित्तीय परिव्यय- ₹23,731 करोड़
- कार्यान्वयन अवधि- वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 (10 वर्ष)
- मंत्रालय- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

□ उद्देश्य-

- घरेलू संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना।
- बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करना।
- देश में एक जीवंत चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।

■ गोबरधन के प्रमुख विकास इंजन-

क्र.	घटक	मुख्य प्रावधान/प्रावधान विवरण
1	सुनिश्चित संपीड़ित बायोगैस निकासी	■ संपीड़ित बायोगैस ब्लेंडिंग/मिश्रण दायित्व लक्ष्य- ■ वित्त वर्ष 2026-27- 3 प्रतिशत ■ वित्त वर्ष 2027-28- 4 प्रतिशत ■ वित्त वर्ष 2028-29 से आगे- 5 प्रतिशत
2	स्थिर मूल्य निर्धारण ढांचा	■ प्रशासित मूल्य- ₹2,110 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट ■ अवधि- न्यूनतम 10 वर्ष का राजस्व स्थिरता ढांचा।
3	पूंजी सहायता	■ अनुदान- ₹2 करोड़ प्रति TPD (टन प्रति दिन) स्थापित संपीड़ित बायोगैस क्षमता तक। ■ पात्रता- ग्रीनफील्ड एवं क्षमता विस्तार करने वाली ब्राउनफील्ड परियोजनाएं।
4	पाइपलाइन अवसंरचना विकास	■ क्लस्टर-आधारित एवं स्वतंत्र पाइपलाइन अवसंरचना का विकास, जिससे संपीड़ित बायोगैस संयंत्र मुख्य पाइपलाइनों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क से जुड़ेंगे।
5	क्रेडिट गारंटी सहायता	■ पात्र MSME आधारित संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और क्रेडिट जोखिम साझा करना।

6

संपीड़ित बायोगैस इकोसिस्टम चैलेंज फंड

- जिला स्तर पर संसाधन मानचित्रण, कच्चे माल के एकीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने, जैविक खाद के मूल्यवर्धन और क्षमता निर्माण हेतु समर्पित निधि।

■ महत्व एवं प्रभाव-

- संपीड़ित बायोगैस रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस के समतुल्य है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी।
- किसानों, पशुपालकों, चारा संग्राहकों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय के नए स्रोतों का सृजन होगा।
- पराली (कृषि अवशेष), गोबर, प्रेस मड (गन्ने की मैली) और नगरपालिका जैविक कचरे का प्रभावी उपयोग होगा।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा जैविक खाद के उत्पादन से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा।

लखनऊ में सीएसआईआर-एनबीआरआई द्वारा विकसित 'इको-एजुकेशनल हब' राष्ट्र को समर्पित-

- 8 अगस्त, 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लखनऊ के बंधरा स्थित महर्षि पाराशर बायोरिसोर्स सेंटर में CSIR-NBRI द्वारा विकसित अपनी तरह के पहले इको-एजुकेशनल हब को राष्ट्र समर्पित किया।
- इस हब का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधानों और प्रौद्योगिकियों को प्रयोगशालाओं से निकालकर समाज, किसानों, उद्यमियों और विद्यार्थियों तक पहुंचाना तथा आजीविका सृजन को बढ़ावा देना है।

ग्लाव झील-



- 3 अगस्त, 2026 को अरुणाचल प्रदेश की ग्लाव झील को देश की 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया है।
- यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर आर्द्रभूमि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा मिला है।

■ ग्लाव झील-

- अवस्थित- कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर (अरुणाचल प्रदेश)
- यह मीठे पानी की झील है।
- इसके जलग्रहण क्षेत्र में 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियां और 49 ऑर्किड प्रजातियां पाई गयी है।

■ रामसर स्थल-

- यह आर्द्रभूमि होती है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया जाता है।

■ रामसर कन्वेंशन-

- यह आर्द्रभूमि संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- इस पर फरवरी, 1971 में यूनेस्को के तत्वावधान में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किया गया था।
- उद्देश्य- आर्द्रभूमि का संरक्षण करना और वैश्विक जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए उनके सतत उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- भारत 1982 में रामसर सम्मेलन का एक अनुबंधित पक्ष बना और अब इसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 101 रामसर स्थल हैं।
- यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक 176 रामसर स्थल हैं, उसके बाद मेक्सिको और भारत का स्थान आता है।
- भारत में-
 1. सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य- तमिलनाडु
 2. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल सुंदरवन आर्द्रभूमि
 3. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्थल- रेणुका झील (हिमाचल प्रदेश) व वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि परिसर (तमिलनाडु)

ई-समुद्र-

- 8 अगस्त, 2026 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री सेवाओं के डिजिटलीकरण और नाविकों के कल्याण के लिए 'ई-समुद्र' डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है।
- 'ई-समुद्र' प्लेटफॉर्म नाविकों, शिपिंग कंपनियों और बंदरगाहों के लिए सेवाओं को एक ही मंच पर एकीकृत करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे समुद्री गवर्नेंस पारदर्शी और सुगम बनेगी।

■ अन्य डिजिटल पहलें-

- ई-नाविक (e-Navik)- 24x7 शिकायत निवारण प्रणाली।
- डी-एसईए (d-SEA)- डिजिटल सीफरर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट।

■ स्मरणीय तथ्य-

- भारत विश्व में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है।
- देश में सक्रिय नाविकों की संख्या 2013 में 1.03 लाख से बढ़कर 2025 में 3.23 लाख से अधिक हो गई है।
- भारत विश्व का अग्रणी जहाज रीसाइक्लिंग केंद्र है और शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है।

वर्ष 2026-2030 की अवधि के लिए तीन संचार मित्रों का ITU जेनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय के रूप में चयन-

- अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की 'संचार मित्र' योजना के तहत तीन भारतीय युवाओं को जेनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय (GCYE) के तीसरे समूह (2026-2030) के रूप में चुना है।

चयनित जेनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय (2026-2030)-

नाम	स्थान	संबद्धता
अंकित कुमार पाल	दिल्ली	संचार मित्र (दूरसंचार विभाग)
मनीष कुमार मंडल	बेंगलुरु	संचार मित्र (दूरसंचार विभाग)
सुस्मिता साई	गुवाहाटी	संचार मित्र (दूरसंचार विभाग)

संचार मित्र योजना-

- उद्देश्य- युवा शक्ति-भारत के युवाओं को डिजिटल सशक्तीकरण और सामाजिक पहुंच के लिए उत्प्रेरक के रूप में जोड़ना।
- संचार मित्र के रूप में नामित छात्र समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों आदि में जागरूकता अभियान सक्रिय रूप से संचालित करते हैं।
- इन अभियानों में नागरिक-केंद्रित दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार धोखाधड़ी की रोकथाम और मोबाइल सुरक्षा जैसे प्रमुख दूरसंचार संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

इंडिया कोड पोर्टल का शुभारंभ-

- 13 अगस्त, 2026 को पुनर्गठित 'इंडिया कोड पोर्टल' का शुभारंभ किया गया।
- यह पहल भारत के डिजिटल कानूनी इकोसिस्टम को अधिक पारदर्शी, सुलभ और नागरिक-केंद्रित बनाने में सहायक होगी।

आरएसवीसी-अमृत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ-

- 15 अगस्त, 2026 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने आरएसवीसी एएमआरआईटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।

RSVC-AMRIT डिजिटल प्लेटफॉर्म-

- डेवलपर एवं सहयोग- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के सहयोग से नाबार्ड द्वारा विकसित
- यह रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC) इकोसिस्टम की डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करेगा।
- उद्देश्य- ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद करना।

अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (AppCoMS 2.0) का शुभारंभ-

- 17 अगस्त, 2026 को केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दूसरी अपीलों और शिकायतों के त्वरित व पारदर्शी निस्तारण के लिए 'AppCoMS 2.0' (अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली) का शुभारंभ किया है।

विषय	विवरण
पोर्टल का नाम	AppCoMS 2.0 (अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली)
उद्घाटनकर्ता	मुख्य सूचना आयुक्त श्री राज कुमार गोयल
शुभारंभ तिथि	17 अगस्त, 2026
संबंधित अधिनियम	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मुख्य उद्देश्य	डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और अपील निस्तारण को सुगम बनाना

प्रमुख विशेषताएं और सुविधाएं-

- ई-मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से व्यक्तिगत यूजर अकाउंट बनाने की सुविधा, जिससे सीधे दूसरी अपील या शिकायत दर्ज की जा सकेगी।
- आवेदक अपने मामलों की समय-सीमा देख सकेंगे, सुनवाई संबंधी नोटिस डाउनलोड कर सकेंगे तथा आदेशों/निर्णयों की डिजिटल प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे।
- लोक अधिकारियों को अलग अकाउंट की सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपीलों का विवरण देखने के साथ-साथ पोर्टल के जरिए सीधे दस्तावेज जमा कर सकेंगे।
- सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा जारी नोटिसों और आदेशों पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाएगा।

मिशन समृद्ध गांव योजना का शुभारंभ-



- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में 'मिशन समृद्ध गांव' योजना का शुभारंभ किया।
- 'मिशन समृद्ध गांव' के माध्यम से गरीबी-मुक्त, रोजगारयुक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न गांवों के निर्माण की दिशा में समग्र एवं एकीकृत मॉडल विकसित करने की योजना है।
- 'मिशन समृद्ध गांव' समग्र विकास से गरीबी-मुक्त, रोजगारयुक्त और सुविधासंपन्न गांवों का मॉडल तैयार करने की पहल है।
- मध्य प्रदेश के चयनित ब्लॉकों में पायलट मॉडल विकसित कर देशभर में दोहराने का लक्ष्य है।
- समग्र ग्राम विकास में कृषि, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं, खाद्य प्रसंस्करण, रोजगार और सरकारी योजनाओं के अभिसरण पर जोर रहेगा।
- मिशन के तहत महिला किसानों की पहचान, उन्हें कृषि संबंधी सलाह और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसरों से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- 25 अगस्त, 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन से 'मिशन समृद्ध गाँव' योजना का शुभारंभ किया है।
 - इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी-मुक्त, रोजगारयुक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न आत्मनिर्भर गाँवों का निर्माण करना है।
 - यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी और देवास जिले के खातेगांव ब्लॉक में लागू की जायेगी। इन ब्लॉकों में सफलता मिलने के बाद मॉडल को देश के अन्य क्षेत्रों में दोहराया जाएगा।
- एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन-**
- हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास नड्डी में एशिया की सबसे लंबी 4.3 किलोमीटर लंबी जिपलाइन बनाई जा रही है।
 - उद्देश्य- कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करना और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना।
 - विशेषता-
 - लंबाई- 4.3 किलोमीटर
 - लागत- 7.41 करोड़ रुपये
 - प्रमुख स्टेशन- गल्लू (शुरुआती बिंदु), बल गांव, नड्डी और मैगी पॉइंट खड्ड (समापन बिंदु)

संक्षिप्त न्यूज

- 1 अगस्त, 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र- विवेका स्मारक का उद्घाटन किया।
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने एनएच-48 के दिल्ली-जयपुर खंड पर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है।
- देश में पायलटों की कमी दूर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 7 एयरपोर्ट पर 11 नए फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने की घोषणा की है।
- हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत में पाए जाने वाले तितलियों और पतंगों की सूची प्रकाशित की है। भारत में कुल 13,703 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया की कुल प्रजातियों का 8.25% है। इसमें 1,417 तितलियां और 12,286 पतंगों की प्रजातियां शामिल हैं।
- हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में 'इंडिया साउथ सेंटरल' क्लाउड रीजन शुरू किया। यह नया क्लाउड रीजन व्यवसायों को सुरक्षित भरोसेमंद और डेटा नियमों के अनुरूप डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
- आंध्रप्रदेश पेडस्ट्रियन सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें सड़कें वाहनों के बजाय लोगों के अनुकूल बनेगी।
- विश्व का सबसे बड़ा ट्रम्प प्रोजेक्ट हैदराबाद में 2031 तक बनेगा।
- गुजरात में एशिया का पहला डेजर्ट-थीम नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क बनेगा। करीब 103 हेक्टेयर में बनने वाले इस पार्क में 83 प्रजातियों के 2,700 जानवर होंगे।
- परीछा बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर बनाया गया है। यह करीब 140 साल पुराना है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है।
- असम सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और गरिमा के लिए असम राज्य बाल संरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी। इससे राज्य में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।
- महाराष्ट्र सरकार ने सांप/स्नेकबाइट के काटने को अधिसूचित बीमारी घोषित किया। अब सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और डॉक्टरों को स्नेकबाइट के हर संदिग्ध या पुष्ट मामले और उससे होने वाली मौत की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा।
- तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुफ्त इलाज की सालाना सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किये जाने की घोषणा की है।

- केरलम राज्य लाइलाज बीमारी से पीड़ित और खतरनाक बेसहारा कुत्तों को दयामृत्यु देने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मंजूर करने वाला पहला राज्य बन गया है।
- हाल ही में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्रप्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूरु में भारत का पहला गैर-जीएमओ, उच्च-विस्तारक पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया है।
- गोवा ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, लैब और क्लीनिकों को कैंसर का पता चलने के बाद इसकी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को देना जरूरी होगा।
- मिजोरम सरकार ने 'रो मिन रेल साक आंग चे' को आधिकारिक राज्य गीत घोषित किया।
- तमिलनाडु सरकार ने हाथियों के संरक्षण और इंसानों के साथ उनके टकराव को कम करने के लिए तीन नए हाथी गलियारे अधिसूचित किए हैं। ये तीनों गलियारे कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य के होसुर वन प्रभाग में हैं।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में देश के पहले समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर को मंजूरी दे दी है।
- खिजड़िया पक्षी अभयारण्य- यह जामनगर में स्थित अभयारण्य है जो ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क के प्रजनन स्थल के रूप में पहचाना गया है।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-31 की अवधि के लिये हीटवेव और आकाशीय बिजली (तड़ित) को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है।
- 21 अगस्त, 2026 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई की जल आपूर्ति और स्वच्छता अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए 230 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।



Samyak
An Institute For Civil Services

क्लास 12th के बाद

IAS & RAS

ग्रेजुएशन के साथ 2 & 3 वर्षीय कोर्स

OFFLINE & LIVE FROM CLASSROOM

बैच प्रारम्भ

COURSE FEATURES

 विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज

 प्रिंटेड बुकलेट्स

 पर्सनल मेंटरशिप

 टेस्ट सीरीज

 लाइब्रेरी सुविधा

FREE 03 DAYS DEMO CLASSES

आर्थिक परिदृश्य

गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 300 गीगावाट का आंकड़ा पार-

- भारत ने 31 जुलाई, 2026 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है।
- **गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का विवरण-**
 - सौर ऊर्जा - 164.59 गीगावाट
 - पवन ऊर्जा - 58.14 गीगावाट
 - जल विद्युत - 57.24 गीगावाट
 - जैव-ऊर्जा - 11.75 गीगावाट
 - परमाणु ऊर्जा - 8.78 गीगावाट
- देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो वर्तमान में लगभग 552 गीगावाट है, में गैर-जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न विद्युत क्षमता का हिस्सा 54 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

संक्षिप्त न्यूज

- हाल ही में नीति आयोग ने “की सेक्टर्स टु पोजिशन इंडिया एज ए ग्लोबल मेन्युफैक्चरिंग हब” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।
- 25 अगस्त, 2026 को ‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’ के लक्ष्यों को मजबूती देने के उद्देश्य से ‘क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकाथॉन 2026’ लॉन्च की गयी है।
- 10 अगस्त, 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया तथा इसके माध्यम से 6,000 से अधिक कृषि विद्यार्थियों को 21.35 करोड़ रु. की स्कॉलरशिप जारी की है।
- भारत सरकार ने दस व बीस रुपए के प्लास्टिक बैंक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है।
- हाल ही में भारतीय संसद ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को मंजूरी दी। यह वर्ष 1891 के पुराने कानून की जगह लेगा। नए कानून के तहत बैंकों के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में कानूनी सबूत माना जाएगा।
- हाल ही में भारत सरकार ने बीकानेर (राजस्थान) और बीना (मध्य प्रदेश) में नए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने की घोषणा की है।
- क्रोल की वर्ष 2025 की इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड्स रिपोर्ट में शाहरुख 177.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ पहले स्थान पर है।
- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह पुरानी पीएलआई योजना का विस्तार है। स्थानीय वैल्यू एडिशन 23% से बढ़ाकर 35-40% करने का लक्ष्य है।
- हाल ही में फोर्ब्स की ‘100 टू वॉच’ लिस्ट में 19 कंपनियों के साथ भारत शीर्ष पर रहा है।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय मध्यस्थता परिषद का गठन किया है। इसका गठन मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत किया गया है। यह देश में मध्यस्थता से जुड़े ढांचे को लागू और मजबूत करने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी।
- इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप द्वारा जारी वैश्विक वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स-2026 में मुंबई ने 77 अंकों के साथ दुनिया के 50वें स्थान पर रहा है। यह इस सूची में शामिल होने वाली भारत का एकमात्र शहर है।

■■■■

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

रक्षा-प्रौद्योगिकी

अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण-

- हाल ही में 6 अगस्त, 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-4' का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को सामरिक बल कमान के तत्वावधान में लॉन्च किया गया।

अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल-

- विकसित- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
- मारक क्षमता- लगभग 4,000 किमी.
- पेलोड क्षमता- लगभग 1,000 किग्रा पेलोड
- मिसाइल की लंबाई- लगभग 20 मीटर
- स्वरूप- बैलिस्टिक मिसाइल/सतह-से-सतह पर मार करने वाली
- यह अग्नि मिसाइल शृंखला की एक स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है।

अग्नि मिसाइल शृंखला की 5 प्रमुख मिसाइलें-

 अग्नि-1 सीरीज की पहली मिसाइल। रेंज 700-1200km। कम दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित।	 अग्नि-2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज 2000-2500km। सड़क और रेल, दोनों मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है।	 अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज 3000-3500km। दुश्मन के रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित।
 अग्नि-4 डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, मॉडर्न एवियोनिक्स, एडवांस्ड नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल। अग्नि-2 और अग्नि-3 के बीच की क्षमता का अंतर भरती है। रेंज 3500-4000km।	 अग्नि-5 सबसे लंबी दूरी की अग्नि मिसाइल। रेंज 5000km से ज्यादा। इसके लेटेस्ट वर्जन में MIRV तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है, जिससे एक ही मिसाइल कई अलग-अलग लक्ष्यों पर वार करने में सक्षम हो सकती है।	

मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने को मंजूरी-

- हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
- उद्देश्य- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और घरेलू उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना।

लाभ/महत्व-

- स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा- घरेलू रक्षा उद्योग निर्धारित मानकों और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार पारंपरिक मिसाइलों का निर्माण देश में ही कर सकेंगे।
- MSMEs के लिए अवसर- इस पहल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे।
- आयात पर निर्भरता में कमी- भारत में ही उन्नत रक्षा प्रणालियों के विनिर्माण से विदेशी सैन्य उपकरणों पर निर्भरता कम होगी और परिचालन क्षमता बढ़ेगी।
- तकनीकी सुधार और अनुकूलन- घरेलू स्तर पर तकनीक उपलब्ध होने से आवश्यकतानुसार सुधार, बदलाव और गुणवत्ता संवर्धन की प्रक्रिया तेज होगी।
- डीआरडीओ और उद्योगों का समन्वय- डीआरडीओ प्रौद्योगिकियों के सुगम हस्तांतरण, अनुकूलन और प्रणालियों को सेना में शामिल करने के लिए भारतीय उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करेगा।

सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला ने पेश किए स्वदेशी अत्यंत छोटे और लघु गैस टर्बाइन इंजन-



- 25 अगस्त, 2026 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्- राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला ने 05, 50 और 100 किलोग्राम थ्रस्ट वाले तीन स्वदेशी लघु गैस टर्बाइन इंजन पेश किए हैं।

इंजन मॉडल एवं थ्रस्ट क्षमता-

- NJ-05 - 05 किलोग्राम थ्रस्ट
- NJ-50 - 50 किलोग्राम थ्रस्ट
- NJ-100 - 100 किलोग्राम थ्रस्ट
- ये इंजन सुव्यवस्थित एवं कॉम्पैक्ट प्रणोदन प्रणालियों, सामरिक मानवरहित विमानों, ड्रोन, इंटरसेप्टर्स और सघन मिसाइल प्रणालियों के संचालन हेतु विकसित किए गये हैं।

यार्ड 3037 'श्रुति' जलावतरित-

- 11 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत यार्ड-3037 'श्रुति' को को गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में जलावतरित किया गया।
- निर्माण- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL), गोवा तथा GRSE, कोलकाता
- नामकरण- 'श्रुति' नाम चारों वेदों का प्रतीक है।
- यह पोत समुद्री निगरानी, खोज व बचाव, अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत और एंटी-पायरेसी (समुद्री डकैती रोधी) अभियानों में नौसेना की क्षमता बढ़ाएगा।

उथले जल की पनडुब्बी रोधी युद्धक नौका 'मंगरोल' का जलावतरण-



- 21 अगस्त 2026 को, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि द्वारा निर्मित तीसरी उथले जल की पनडुब्बी रोधी युद्धक नौका 'मंगरोल' को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।
- यह तटीय जलक्षेत्र में पनडुब्बी रोधी अभियान, पानी के भीतर निगरानी, निम्न-तीव्रता समुद्री संचालन और समुद्री बारूदी सुरंगों से बचाव अभियान में सहायक होगी।
- यह अत्याधुनिक टॉरपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट, उन्नत रडार और सोनार प्रणाली से सुसज्जित है।
- नामकरण- इसका नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित तटीय शहर एवं प्रमुख मत्स्य पालन बंदरगाह 'मैंग्रोल' के नाम पर रखा गया है।

डीएससी ए24 (यार्ड-329) का जलावतरण-



- 1 अगस्त, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता (टीटागढ़) में पांच गोताखोरी सहायक जहाजों की श्रृंखला के पांचवें पोत 'डीएससी ए-24' का औपचारिक जलावतरण किया गया।
- इनका निर्माण 'इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग' के मानकों के अनुरूप हुआ है।
- निर्माता एवं डिजाइन- मेसर्स टीआरएसएल (टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड), कोलकाता
- विस्थापन क्षमता- 300 से 400 टन विस्थापन क्षमता
- यह द्वि-पतवार डिजाइन वाला पोत हैं जो चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में बेहतर स्थिरता और परिचालन दक्षता प्रदान करता हैं।
- यह पोत भारतीय नौसेना के गोताखोरी अभियानों, पानी के भीतर जांच, तटीय क्षेत्रों में तैनाती और बचाव कार्यों की क्षमता को मजबूत करेगा।

एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन-



- भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से दो एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन को 30 महीने के लीज पर लेने के लिए 1,943 करोड़ रुपये का समझौता किया है।
- इससे भारतीय नौसेना को समुद्र में जहाजों और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए लंबी दूरी की क्षमता मिलेगी जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी समुद्री निगरानी और जागरूकता क्षमता को मजबूत कर पायेगा।

एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन-

- निर्माता- जनरल एटॉमिक्स
- उड़ान क्षमता- 30 से 40 घंटे तक
- यह उच्च-ऊंचाई और लंबी अवधि तक उड़ान भरने वाला समुद्री निगरानी ड्रोन है।
- यह सतह और पानी के नीचे (पनडुब्बी रोधी क्षमता) दोनों जगह गश्त करने में सक्षम है।
- इसमें उन्नत मैरीटाइम रडार और ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगा होता है।

बहु-उद्देशीय पोत 'समर्थक'-

- सुपुर्दगी- 27 अगस्त, 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया।
- निर्माण- लार्सन एंड टुब्रो द्वारा
- सामग्री- इसमें 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल किया गया है।
- मुख्य उपयोग व भूमिकाएं- बहु-उपयोगी परीक्षण और मूल्यांकन प्लेटफॉर्म, समुद्री निगरानी, टोह लेने, अपतटीय गश्त और मानवीय सहायता व आपदा राहत कार्य।

जैवलिन मिसाइल-



- अमेरिकी सरकार ने भारतीय सेना के लिये 60 जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है।
- विशेषता-
 - मारक क्षमता- 2.5 से 4 किमी.
 - मिसाइल भार- लगभग 22 किलोग्राम
 - निर्माण- जेवलिन जॉइंट वेंचर
 - यह मैन-पोर्टेबल, शोल्डर फायर, मध्यम दूरी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
 - यह निष्क्रिय इमेजिंग-इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करती है।

आईएनएस निपुण-

- हाल ही में आईएनएस निपुण को 31 अगस्त, 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह भारत का दूसरा स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है।

- स्थान- नेवल डॉकयार्ड, मुंबई (पश्चिमी नौसेना कमान)
- पोत का प्रकार- गोताखोरी सहायता पोत (निस्तार श्रेणी का)
- निर्माता- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम
- आईएनएस निपुण के नौसेना में शामिल होने से गहरे समुद्र में गोताखोरी, पानी के भीतर अभियानों और पनडुब्बी बचाव अभियानों की क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

भावना कान्त-

- भारतीय वायुसेना की स्कवाड्रन लीडर भावना कान्त 'फाइटर

कॉम्बैट लीडर कोर्स' को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। उन्होंने भारत की पहली महिला 'टॉप गन' होने का गौरव प्राप्त किया है।

एके-203 असॉल्ट राइफल 'शेर'-

- यह उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरवा प्लांट में इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई देश की पहली शत प्रतिशत स्वदेशी असॉल्ट राइफल है।

अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी

नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप-

- हाल ही में नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।
- लॉन्च व्हीकल- फाल्कन हेवी रॉकेट (स्पेसएक्स)
- उद्देश्य- डार्क एनर्जी, बाह्य ग्रहों और इन्फ्रारेड खगोल भौतिकी के रहस्यों को सुलझाना।
- इसे पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 2 (L2) के पास स्थापित किया जाएगा।
- विशेषता- मुख्य दर्पण का आकार- 7.9 फीट व्यास (हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुख्य दर्पण के समान आकार का)
- प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण-
 - वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट- इसका दृश्य क्षेत्र हबल टेलीस्कोप से कम से कम 100 गुना बड़ा है, जिससे यह तेजी से विस्तृत आकाश का सर्वे कर सकता है। अपने मिशन काल के दौरान यह लगभग 1 अरब आकाशगंगाओं के प्रकाश का मापन करेगा।
 - कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट- यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपकरण है। इसका उपयोग पास के बाह्य ग्रहों की उच्च-कंट्रास्ट इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए किया जाएगा।
 - मिशन अवधि- प्राथमिक मिशन जीवनकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।



एवरेस्ट रॉकेट इंजन-

- हाल ही में बेंगलूर स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप 'एस्ट्रोबेस' ने भारत का पहला और पूरी तरह स्वदेशी फुल-फ्लो स्टैज्ड कंबिनेशन रॉकेट इंजन 'एवरेस्ट' बनाया है।
- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर केवल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप रॉकेट के 'रेप्टर' इंजन में इस जटिल तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
- विशेषताएं-
 - तकनीक- फुल-फ्लो स्टैज्ड कंबिनेशन तकनीक, जो रॉकेट इंजन की कार्यकुशलता और थ्रस्ट-टू-वेट अनुपात को अधिकतम करती है।
 - ईंधन- लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन का संयोजन।
 - क्षमता व थ्रस्ट- 80-टन क्षमता का यह इंजन अंतरिक्ष के निर्वात में 800 किलोन्यूटन का भारी थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है।
 - भारत वैश्विक स्तर पर अति-उन्नत रॉकेट प्रोपल्शन तकनीक वाले देशों की विशेष लीग में शामिल हो गया है।



जैव-प्रौद्योगिकी, सूचना-प्रौद्योगिकी व अन्य प्रौद्योगिकी

लेप्टोस्पायरोसिस रोग-

- हाल ही में केरल राज्य में लेप्टोस्पायरोसिस रोग के प्रकोप के कारण रोग भार एवं मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गयी है।

लेप्टोस्पायरोसिस

- यह संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है।
- यह एक जूनोटिक रोग (पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित) है।
- वाहक- कृतक, मवेशी, भैंस, सूअर, कुत्ते, घोड़े, भेड़ एवं बकरियों सहित अनेक जंगली तथा घरेलू स्तनधारी

संचरण-



लक्षण-

- बुखार, दिमागी बुखार
- सिरदर्द
- मांसपेशियों में दर्द
- पीलिया
- **उपचार-** एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा (डॉक्सीसाइक्लिन, पेनिसिलिन-जी, सेफ्ट्रायक्सोन)

अफ्रीकन स्वाइन फीवर की स्वदेशी वैक्सीन-

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल के वैज्ञानिकों ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है। इस वैक्सीन के निर्माण में क्षीणीकृत जीनोटाइप-II एएसएफ वायरस तथा एमए-104 कोशिका रेखा का उपयोग किया गया है।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर-

- यह पहली बार वर्ष 1921 में केन्या में दर्ज किया गया था।

- भारत में- वर्ष 2020 में (पहला मामला)
- संचरण- संक्रमित सूअरों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सम्पर्क से
- यह मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है।
- यह घरेलू एवं जंगली सूअरों को प्रभावित करता है जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस के कारण होता है।

स्तनकैंसर की पहचान के लिए उन्नत प्रकाश-चालित बहुक्रियाशील नैनोबोट विकसित-

- हाल ही में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान, मोहाली और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के शोधकर्ताओं ने उन्नत प्रकाशचालित बहुक्रियाशील नैनोबोट विकसित किये हैं जो स्तन कैंसर की पहचान करने में सहायक सिद्ध होंगे।
- यह नैनोबोट्स अपकनवर्जन नैनोपार्टिकल पर आधारित हैं जो निकट-अवरक्त प्रकाश (980 nm) का उपयोग करते हैं।
- निकट-अवरक्त प्रकाश के संपर्क में आने पर नैनोबोट में मौजूद पॉलीडोपामीन ताप उत्पन्न करता है। इससे एक तापीय प्रवणता बनती है, जिससे नैनोबोट्स सक्रिय रूप से लेजर स्रोत (ट्यूमर स्थल) की ओर गति करते हैं।
- इन नैनोबोट्स की सतह को फोलिक एसिड से क्रियाशील बनाया गया है, जो स्तन कैंसर कोशिकाओं पर पाए जाने वाले फोलेट रिसेप्टर्स को पहचानकर केवल ट्यूमर कोशिकाओं को ही लक्षित करते हैं।

'परम प्रज्ञा' एआई सुपरकंप्यूटर का उद्घाटन-

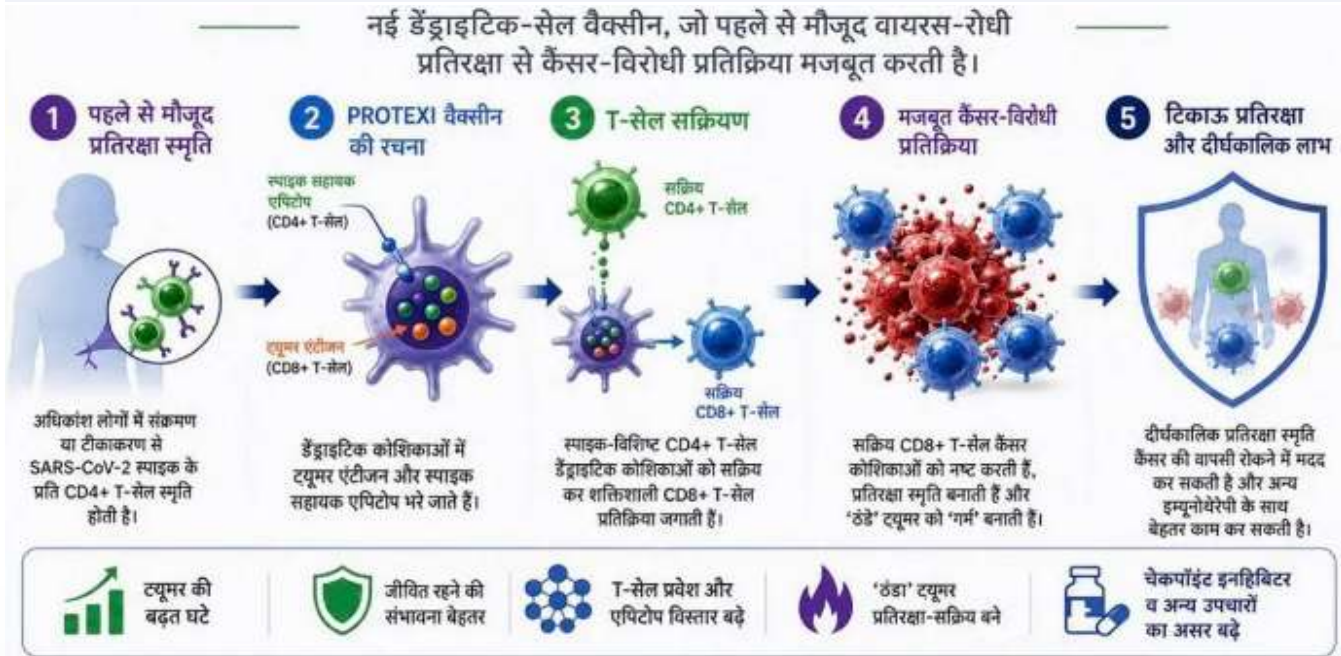
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2026 को आईआईटी-दिल्ली के सोनीपत कैम्पस में 'परम प्रज्ञा' एआई सुपरकंप्यूटर का उद्घाटन किया।
- इस सुपरकंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डीएसी) द्वारा बनाया गया है।
- इसकी क्षमता 250 पेटाफ्लॉप्स है और यह सामान्य लैपटॉप से 2.5 लाख गुना तेज गणना करता है।
- देश का पहला स्वदेशी सुपरकंप्यूटर 'परम 8000' वर्ष 1991 में विजय भटकर के नेतृत्व में बना था।

सुपरकंप्यूटर-

- यह सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक तेज, शक्तिशाली और विशाल गणना क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं।
- इनकी कार्यक्षमता को FLOPS (Floating-point Operations Per Second) में मापा जाता है।

कोविड की इम्यून मेमोरी से विकसित की कैंसर से लड़ने की तकनीक

PROTEXI : कोविड की प्रतिरक्षा स्मृति को कैंसर के विरुद्ध हथियार में बदलना



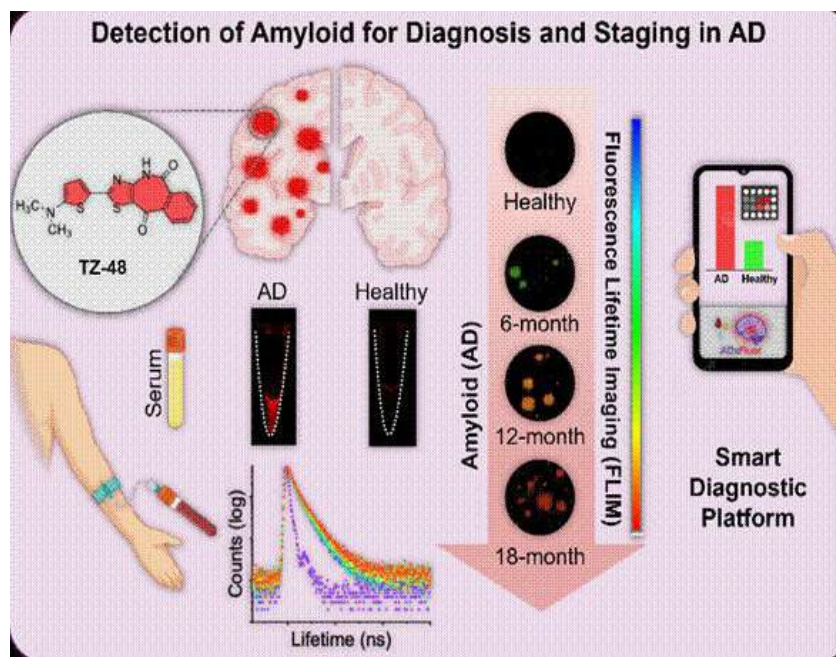
- जयपुर मूल के भारतीय जीवविज्ञानी डॉ. तेज कुमार पारीक और उनकी टीम ने कोविड-19 से शरीर में बनी इम्यून मेमोरी का उपयोग करके कैंसर से लड़ने का नया डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन प्लेटफॉर्म 'प्रोटेक्सी' विकसित किया है।

तकनीक या कार्यप्रणाली-

- अफेरेसिस प्रक्रिया- मरीज के शरीर से श्वेत रक्त कोशिकाएं निकालकर उन्हें प्रयोगशाला में डेंड्राइटिक कोशिकाओं में बदला जाता है।
- एंटीजन और स्पाइक प्रोटीन का संयोजन- इन डेंड्राइटिक कोशिकाओं में कैंसर एंटीजन के साथ SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के हिस्से जोड़े जाते हैं।
- इम्यून मेमोरी का उपयोग- पारंपरिक कैंसर वैक्सीन CD4 T-सेल प्रतिक्रिया जगाने में कमजोर होती हैं। 'प्रोटेक्सी' कोविड संक्रमण या टीकाकरण से पहले से बनी CD4 T-सेल की एंटी-वायरल मेमोरी को फिर से सक्रिय कर देती है।
- कैंसर कोशिकाओं पर हमला- सक्रिय CD4 T-सेल की मदद से CD8 T-सेल को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर तेजी से हमला करने के लिए तैयार किया जाता है।

अल्जाइमर रोग के लिए स्मार्टफोन-आधारित डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म विकसित-

- हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग की शुरुआती पहचान और निगरानी के लिए 'TZ-48' नामक फ्लोरेसेंस प्रोब और 'ADxFluor' नामक स्मार्टफोन-आधारित डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
- **TZ-48 प्रोब-** यह छोटा अणु अल्जाइमर के प्रमुख बायोमार्कर एमिलॉयड- β ($A\beta$) तंतुओं के संपर्क में आने पर अपनी चमक की तीव्रता और लाइफटाइम सिग्नल को बदलता है।
- **ADxFluor प्लेटफॉर्म-** स्मार्टफोन-एकीकृत यह ऐप TZ-48 की फ्लोरेसेंस प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड और प्रोसेस करके सेरेब्रोस्पाइक इनल फ्लूइड तथा रक्त सीरम में $A\beta$ के स्तर का त्वरित और निष्पक्ष मापन करता है।

**लाभ**

यह पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और एमआरआई जैसे महंगे, जटिल और सीमित उपलब्धता वाले परीक्षणों की तुलना में यह एक सुलभ, सस्ता और पोर्टेबल 'पॉइंट-ऑफ-केयर' डायग्नोस्टिक किट है।

A β प्लाक अल्जाइमर का एक प्रारंभिक संकेतक है। यह तकनीक न केवल स्वस्थ और अल्जाइमर से पीड़ित नमूनों में सटीक अंतर करती है, बल्कि बीमारी के विभिन्न चरणों के निर्धारण में भी सक्षम है।

यह प्रोब ब्लड-ब्रेन बैरियर को आसानी से पार कर मस्तिष्क के ऊतकों में A β प्लाक की सटीक लेबलिंग और इमेजिंग कर सकता है।

सी-डॉट द्वारा 14 स्वदेशी क्वांटम उत्पादों का अनावरण-

- 31 अगस्त, 2026 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने अपने 43वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान 14 स्वदेशी क्वांटम उत्पादों का अनावरण किया।
- उद्देश्य- भविष्य की क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से भारत की दूरसंचार अवसंरचना को सुरक्षित बनाना तथा रणनीतिक व रक्षा संचार को सशक्त करना।
- उत्पाद-

क्र.	उत्पाद का नाम	श्रेणी/प्रकार	मुख्य विशेषताएं एवं उपयोग
1	क्यू-अक्षय CD	QKD प्रणाली	■ 1U आकार की फाइबर-आधारित प्रणाली। ■ COW और DPS प्रोटोकॉल पर आधारित।
2	क्यू-अक्षय MD	QKD प्रणाली	■ मेजरमेंट डिवाइस इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल पर आधारित अगली पीढ़ी की सुरक्षा।
3	सी-एसपीडी (C-SPD)	उप-मॉड्यूल	■ सिंगल-फोटॉन डिटेक्टर। ■ क्वांटम संचार प्रणालियों का महत्वपूर्ण घटक।
4	सी-आरडी (C-RD)	उप-मॉड्यूल	■ वाइडबैंड RF ड्राइवर। ■ तीव्रता और चरण मॉड्युलेटर के संचालन हेतु।
5	क्यू-सेतु	लेयर 3 एन्क्रिप्टर	■ 80 Mbps तक डेटा संचरण। NIST PQC एल्गोरिदम पर आधारित।
6	क्यू-महासेतु	लेयर 2/3 एन्क्रिप्टर	■ 40 Gbps क्षमता। ■ एंटरप्राइज और महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क के लिए।
7	क्यू-विक्रम	रक्षा-स्तरीय एन्क्रिप्टर	■ लेयर 2/3 नेटवर्क के लिए 1 Gbps तक डेटा संचरण। ■ संवेदनशील संचार हेतु।
8	क्यू-अमोघ	ऑप्टिकल एन्क्रिप्टर	■ लेयर 1 पर 200 Gbps तक की उच्च-गति क्षमता। ■ ऑप्टिकल लिंक सुरक्षा हेतु।

9	क्यू-दर्शन	IP फोन	■ NIST PQC आधारित क्वांटम-सुरक्षित वीडियो IP फोन।
10	क्यू-वचन	इन-लाइन नोड	■ PQC एल्गोरिदम पर आधारित। ■ मौजूदा IP फोन को क्वांटम सुरक्षा देने हेतु।
11	क्यू-रक्षक	नेटवर्क समाधान	■ उद्यम नेटवर्क और संचार अवसंरचना की सुरक्षा के लिए।
12	क्यू-वायु	वायरलेस समाधान	■ पॉइंट-टू-पॉइंट वायरलेस संचार लिंक हेतु क्वांटम-प्रतिरोधी सुरक्षा।
13	क्यू-वज्र 1000	एक्सेस नोड	■ GPON और वायरलेस रेडियो जैसे मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करने हेतु।
14	क्यू-पराक्रम	रक्षा-स्तरीय एन्क्रिप्ट	■ लेयर 2/3 हेतु 1 Gbps क्षमता। ■ NIST PQC व स्वदेशी मालिकाना एल्गोरिदम।

ज्ञानी अर्थ नामक एआई स्टैक लॉन्च-

- 28 अगस्त, 2026 को उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में ज्ञानी एआई द्वारा विकसित स्वतंत्र एआई स्टैक 'ज्ञानी अर्थ' का शुभारंभ किया।
- इसमें इवोन 3.3 (वृहत भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (प्लेटफॉर्म) शामिल हैं।



विविध तथ्य-

- 13 अगस्त, 2026 को इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने उच्च आवर्धन क्षमता वाली स्वदेशी दूरबीन 'गरुड़' आम लोगों के इस्तेमाल के लिए असेन्य बाजार में पेश की है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड रक्षा उत्पादन विभाग के तहत आने वाली 'मिनी रत्न श्रेणी-I' की रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
- केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए लोइटर म्यूनिशन सिस्टम, गोला-बारूद और अन्य उपकरणों की खरीद के उद्देश्य से टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है।
- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी सी गार्डियन हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्रोरेंस रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को 30 महीने की अवधि के लिए पट्टे पर लेने हेतु जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स, इंक. के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 21 अगस्त, 2026 को प्रादेशिक सेना ने 'साइबरपीस' के साथ मिलकर टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 (टीसीक्यू 3.0) की शुरुआत की है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है, जिसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान विकसित करना है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के 651 जिलों में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के असर का मूल्यांकन किया है। इनमें सबसे अधिक जोखिम वाले 109 जिलों में राजस्थान के 17 जिले शामिल हैं।
- हाल ही में अमरीका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कृत्रिम 'वायरस' डिजाइन किया है।
- रक्षा मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता घटाने के लिए 405 रणनीतिक वस्तुओं की छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की।
- रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ की सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक घरेलू कंपनियों को ट्रांसफर करने की मंजूरी प्रदान की है।
- डीआरडीओ ने लद्दाख के लेह जिले में न्योमा-मुध ड्रॉप जोन पर स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का उच्च-ऊंचाई परीक्षण किया। यह परीक्षण 22,000 फीट की ऊंचाई पर, शून्य से 15 डिग्री नीचे तापमान में किया गया।

■■■■

खेल परिदृश्य



हॉकी

FIH हॉकी विश्व कप 2026-



- आयोजन तिथि- 15 से 30 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- बेल्जियम और नीदरलैंड्स में
- प्रतिभागी टीम- 16 पुरुष टीमों और 16 महिला टीमों

परिणाम-

- पुरुष-
 - विजेता- जर्मनी
 - उपविजेता- स्पेन
 - तीसरा स्थान- अर्जेंटीना
 - भारतीय पुरुष टीम- 8वां स्थान
- महिला -
 - विजेता- अर्जेंटीना
 - उपविजेता- नीदरलैंड्स
 - तीसरा स्थान- बेल्जियम
 - भारतीय महिला टीम- 5वां स्थान

लद्दाख में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृत्रिम आइस हॉकी रिक-

- हाल ही में लेह-लद्दाख के एनडीएस स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृत्रिम आइस हॉकी रिक का उद्घाटन किया गया है।
- यह कृत्रिम आइस हॉकी रिक लद्दाख में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देगा।
- लागत- लगभग ₹42 करोड़



बैडमिंटन

बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप-2026



- संस्करण- 30वां
- आयोजन तिथि- 17-23 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम, नई दिल्ली

विजेता और उपविजेता-

■ पुरुष एकल-	■ महिला एकल-
■ विजेता- एलेक्स लेनियर ■ उपविजेता- कोडाई नाराओका	■ विजेता- एन से-योंग ■ उपविजेता- अकाने यामागुची
■ पुरुष युगल-	■ महिला युगल-
■ विजेता- लियांग वेइ केंग और वांग चांग ■ उपविजेता- गोह सज़ी फी और नुर इज्द्दीन	■ विजेता- बेक हा-ना और ली सो-ही ■ उपविजेता- लियू शेंगशु और टैन निंग

- भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला युगल सेमी-फाइनल मुकाबले में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मौजूदा चैंपियन लियू शेंगशु और टैन निंग से हार का सामना किया

अश्मिता चालिहा-

- यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने 9 अगस्त, 2026 को कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है।
- अश्मिता ने फाइनल में चीन की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हान कियान शी को हराया है।



एथलेटिक्स

विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2026



- आयोजन स्थल- ओरेगन, अमेरिका
- आयोजन तिथि- 5-9 अगस्त, 2026
- भागीदारी- 147 से अधिक देशों के 1,800 से अधिक एथलीट।
- कुल स्पर्धाएँ- कुल 46 स्वर्ण पदक स्पर्धाएँ आयोजित की गईं (22 पुरुष, 22 महिला और 2 मिश्रित वर्ग)।
- भारत के पदक विजेता-
 - आशीष यादव- पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक
 - बसंत कुमार मेघवाल- पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक
 - शाहनवाज खान- पुरुषों की लंबी कूद में कांस्य पदक
 - भारत ने 2021 और 2022 में भी इस प्रतियोगिता में तीन पदक जीते थे जबकि 2024 में वह केवल एक पदक ही जीत पाया था।



शतरंज

बोधना शिवानंदन और श्रेयस रॉयल-

- ब्रिटेन में आयोजित ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप-2026 में भारतीय मूल की बोधना शिवानंदन और श्रेयस रॉयल ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है।
- बोधना ब्रिटेन की अब तक की सबसे कम उम्र की महिला चेस चैंपियन बन गई हैं।
- श्रेयस रॉयल ने ओवरऑल ब्रिटिश खिताब अपने नाम किया है।

ग्रैंड चेस टूर-

- हाल ही में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने सेंट लुइस, मिसौरी में आयोजित 2026 ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स में फैबियानो कारुआना को 15- 13 के स्कोर से हराया है। उन्हें विजेता के रूप में 2,00,000 डॉलर की पुरस्कार राशि मिली है।



फुटबॉल

लियोनल मेसी-

- यह अर्जेटीना के दिग्गज फुटबॉलर है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है।



क्रिकेट

सुभादीप घोष-

- इनको बीसीसीआइ ने भारतीय पुरुष टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया है।
- वह टी. दिलीप का स्थान लेंगे।

कर्ण शर्मा-

- यह 38 वर्षीय भारतीय लेग स्पिनर है।
- इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।



अन्य

विश्व ह्यूमनॉइड गेम्स-2026



- संस्करण- द्वितीय
- आयोजन तिथि- 22-26 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- बीजिंग, चीन
- खेल स्पर्धाएं- 51 स्पर्धाएं
- प्रतिभागी- 16 देशों की 666 टीमों के 2,056 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स
- इसे रोबोटिक्स की दुनिया का ओलंपिक माना जाता है
- टियांगोंग अल्ट्रा- प्रतियोगिता की 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में चीनी रोबोट 'टियांगोंग अल्ट्रा' ने 9.39 सेकंड का समय नि-कालकर इंसानी दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट (9.58 सेकंड) का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।

अंडर-23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप-

- आयोजन तिथि- 9 से 14 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल लागोस, नाइजीरिया

भारत का प्रदर्शन-

- भारत ने इस चैंपियनशिप में पहली बार ओवरऑल खिताब जीता है।
- भारत ने अंडर-23 और सीनियर दोनों वर्गों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- भारत ने 35 पदक (13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य) जीते हैं।

■ स्वर्ण पदक विजेता-

1. निखिल वाघ (अंडर-23 पुरुष साबरे)	-	स्वर्ण पदक
2. जॉयस अशिता (अंडर-23 महिला फॉयल)	-	स्वर्ण पदक
3. प्राची लोहान (अंडर-23 महिला एपी)	-	स्वर्ण पदक
4. जेफरलिन (अंडर-23 महिला साबरे)	-	स्वर्ण पदक
5. तनिष्का खत्री (सीनियर महिला एपी)	-	स्वर्ण पदक
6. कनागलक्ष्मी (सीनियर महिला फॉयल)	-	स्वर्ण पदक
7. राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन (सीनियर पुरुष एपी)	-	स्वर्ण पदक
8. करण सिंह (सीनियर पुरुष साबरे)	-	स्वर्ण पदक
9. भारत (सीनियर पुरुष साबरे टीम)	-	स्वर्ण पदक
10. भारत (सीनियर महिला साबरे टीम)	-	स्वर्ण पदक
11. भारत (सीनियर पुरुष एपी टीम)	-	स्वर्ण पदक
12. भारत (सीनियर महिला एपी टीम)	-	स्वर्ण पदक
13. भारत (सीनियर महिला फॉयल टीम)	-	स्वर्ण पदक

ओवैस याकूब-

- यह जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले मिक्सड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं। इन्होंने बुल्गारिया में 'BRAVE CF 107' प्रतियोगिता में जीत दर्ज की।

अरिहा पंगमबम-

- यह मणिपुर की 22 वर्षीय एयरोबिक जिम्नास्टिक्स खिलाड़ी हैं। इन्होंने एशियन एयरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है।

बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट-

- आयोजन तिथि- 30 जुलाई से 4 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- बटुमी शहर, जॉर्जिया
- प्रतिभागी देश- 12 देशों के लगभग 250 खिलाड़ी
- भारत ने 16 पदक (10 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य) जीते हैं।

विविध तथ्य-

- भारतीय युवा तन्वी शर्मा ने 2 अगस्त, 2026 को ताइपे में आयोजित ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त थूई लिन्ह गुयेन को 21-16 21-16 से हराकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीता है।
- हाल ही में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रगनानंदा ने अमेरिका का 'सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज' खिताब जीता है।

- ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 के समापन पर खेलों का आधिकारिक ध्वज भारत को सौंपा गया। इसे पीटी उषा, हर्ष संघवी और नीरज चोपड़ा ने स्वीकार किया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद (गुजरात) में होगा।
- जॉन टर्नर- यह इंग्लैंड के युवा पेसर है जिन्होंने 25 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
- हाल ही में रोमानिया में हुए भाषा विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते। श्रीलक्ष्मी वेंकटरामन ने स्वर्ण, जबकि आख राव, निशांत लक्ष्मणन और अद्वय मिश्रा ने कांस्य जीते। प्रतियोगिता में अनजानी भाषाओं के व्याकरण व पैटर्न को हल करना होता है।
- हाल ही में जापान की गोल्फ खिलाड़ी कुवाकी शिहो ने जर्मनी की एस्थर हेन्सेलीट को दूसरे प्ले-ऑफ होल में हराकर महिला ब्रिटिश ओपन खिताब जीता है।
- हाल ही में मैग्स कार्लसन ने पेरिस में हुए एस्पोंर्ट्स वर्ल्ड कप की शतरंज प्रतियोगिता जीती है। उन्होंने फाइनल में बेलारूस के डेनिस लाज़ाविक को हराया है।
- ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे किए। वह टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
- भारत ने 2026 एशियन गेम्स के लिए अपनी ई-स्पोर्ट्स टीम को मंजूरी दी है।
- हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीटीएफआइ) की सरकारी मान्यता निलंबित कर दी है। यह निलम्बन समय पर चुनाव नहीं कराने और शासन व्यवस्था से जुड़े मामलों के चलते किया गया है।
- हाल ही में ब्रिटेन की एमी हंट यूरोपियन एथलेटिक्स के एक ही संस्करण में चार गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं।
- हाल ही में 2026 सिनसिनाटी ओपन में महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने और पुरुष एकल का खिताब आर्थर फिल्स ने जीता है।
- ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- हाल ही में भारतीय स्कवैश खिलाड़ी वेलावन सेंथिलकुमार ने बुडापेस्ट में आयोजित टूर्नामेंट में PSA कॉपर-स्तरीय खिताब अपने नाम किया है।



पुरस्कार एवं सम्मान

लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026-



- 1 अगस्त, 2026 को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को 'लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026' से सम्मानित किया।
- **लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड-**
 - स्थापना- वर्ष 1983
 - संस्थापक- लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट
 - पुरस्कार राशि- ₹1 लाख का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र
 - प्रदत्त तिथि- प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त
 - यह पुरस्कार राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है।

संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025-

- भारत की राष्ट्रपति ने 8 अगस्त, 2026 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए।
- राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए।
- **संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025-**
 1. राम मेहर (ओडिशा)
 2. रुनिमा चेटिया चौधरी (असम)
 3. शाह मोहम्मद अंसारी (उत्तर प्रदेश)

■ राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025-

1. अन्नामलाई मुरुमुथु और कुमारन बालारमन (तमिलनाडु)
2. गंजी वेंकटेश (तेलंगाना)
3. मुराकाला नटराजु (आंध्र प्रदेश)
4. नसीम अंसारी (उत्तर प्रदेश)
5. मंजूर अहमद हाजम और फैयाज अहमद वानी (जम्मू और कश्मीर)
6. कमल गौड़ (मध्य प्रदेश)
7. अभिनव बासक (पश्चिम बंगाल)
8. प्रफुल्ल कुमार साहू (ओडिशा)
9. ज्योति भुयान (असम)
10. ताखेल्लाम्बम रानी देवी (मणिपुर)
11. बारंगा राम (राजस्थान)
12. वंकर केशाभाई लखनभाई (गुजरात)
13. रीति डोले (असम)
14. शीतल तमांग (सिक्किम)

■ डिजाइन विकास, विपणन एवं स्टार्टअप-

1. गोपीनाथन एम.वी. (तमिलनाडु)
2. मंतु बासक (पश्चिम बंगाल)
3. एम/एस एन. वेंकटेश्वर राव (आंध्र प्रदेश)
4. एम/एस सीएच 31 कोविलवड़ी हैडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी (तमिलनाडु)
5. एम/एस मार्वेल्ला एसोसिएट्स (असम)

■ हथकरघा पुरस्कार-

- ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के हथकरघा विपणन सहायता (एचएमए) घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन पहल, स्टार्ट-अप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं।

‘बुक ऑफ द ईयर- नॉन-फिक्शन (हिंदी)’ पुरस्कार-

- प्रकाशन विभाग को 10 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ‘FICCI PubliCon 2026’ पब्लिशिंग अवॉर्ड्स में ‘बुक ऑफ द ईयर- नॉन-फिक्शन (हिंदी)’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

विवरण	जानकारी
पुरस्कार श्रेणी	बुक ऑफ द ईयर – नॉन-फिक्शन (हिंदी)
आयोजक / मंच	FICCI PubliCon 2026 (फिक्की पब्लिशिंग अवॉर्ड्स)
विजेता संस्था	प्रकाशन विभाग (Publications Division - DPD)
पुरस्कृत पुस्तक	‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’
आयोजन तिथि व स्थल	10 अगस्त 2026, नई दिल्ली

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025

- 18 अगस्त, 2026 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की है।
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रति वर्ष खेलों में उत्कृष्टता की पहचान और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं।
- चयन समिति- सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है।
- **अर्जुन पुरस्कार 2025-**
 - ‘खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार’ पिछले चार वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना के लिए दिया जाता है।

क्रम	खिलाड़ी का नाम	खेल
1.	श्री तेजस्विन शंकर	एथलेटिक्स
2.	श्री मुहम्मद अजमल वी	एथलेटिक्स
3.	सुश्री प्रियंका गोस्वामी	एथलेटिक्स
4.	सुश्री त्रिशा जॉली	बैडमिंटन
5.	सुश्री पुल्लेला गायत्री गोपीचंद	बैडमिंटन

6.	श्री नरेन्द्र	मुक्केबाजी
7.	श्री विदित संतोष गुजराती	शतरंज
8.	सुश्री दिव्या जितेंद्र देशमुख	शतरंज
9.	श्री धनुष श्रीकांत	बधिर निशानेबाजी
10.	सुश्री लालरेमसियामी	हॉकी
11.	श्री राजकुमार पाल	हॉकी
12.	श्री सुरजीत	कबड्डी
13.	सुश्री पूजा	कबड्डी
14.	श्री रुद्रांश खंडेलवाल	पारा-शूटिंग
15.	सुश्री एकता भायन	पारा-एथलेटिक्स
16.	श्री अरविंद सिंह	नौकायन
17.	श्री अखिल श्योरान	निशानेबाजी

अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) 2025-

- ‘अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम)’ उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं।

क्रम	खिलाड़ी का नाम	खेल
1.	श्री आई अरुमइनायागम	फुटबॉल

■ द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025-

- 'खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार' प्रशिक्षकों को लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है।

नियमित श्रेणी-

क्रम	प्रशिक्षक का नाम	खेल
1.	श्री परवीर सिंह	एथलेटिक्स
2.	श्री छोटे लाल यादव	मुक्केबाजी
3.	सुश्री नेहा नंदकुमार चव्हाण	निशानेबाजी

लाइफटाइम श्रेणी-

क्रम	प्रशिक्षक का नाम	खेल
1.	श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव	मुक्केबाजी
2.	श्री वीरेन्द्र कुमार	कुश्ती

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025-

- 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' कॉर्पोरेट इकाई (सार्वजनिक/निजी), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में स्पष्ट भूमिका निभाई है।

क्रम	संगठन का नाम
1.	आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे

इयाल अवॉर्ड-

- हाल ही में हत्या के आरोप में तमिलनाडु की वेलूर जेल में उम्रकैद की सजा प्राप्त लेखक सी. सेल्वम की पुस्तक ओरु थूकू कैदियिन वाकुमूलम को कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन की ओर से इयाल अवॉर्ड के लिए चुना गया है।
- पहली बार यह पुरस्कार किसी ऐसे लेखक को मिला है, जो 32 वर्षों से जेल में है।

विक्रम साराभाई पदक-

- हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है।

- वह इस सम्मान को पाने वाली देश की पहली महिला वैज्ञानिक और चौथी भारतीय बन गई हैं।
- यह पदक इसरो और अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हर दो साल में खगोल वैज्ञानिकों को दिया जाता है।

डिराक मेडल पुरस्कार-



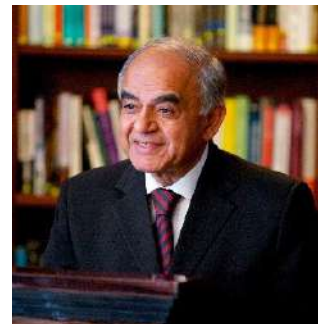
- हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक दीपक धर को इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरिटिकल फिजिक्स द्वारा 2026 का 'डिराक मेडल' दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार विज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है।
- इस साल यह पुरस्कार चार वैज्ञानिकों को दिया जायेगा।
 1. प्रोफेसर दीपक
 2. बर्नार्ड डेरिडा (फ्रांस)
 3. मार्क मेजार्ड (इटली)
 4. हैम सोम्पोलिंस्की (इजराइल)

डिराक मेडल पुरस्कार-

- स्थापित- वर्ष 1985
- संस्थापक- एब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स (आईसीटीपी)
- यह पुरस्कार महान भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक के सम्मान में स्थापित किया गया था।

लाइफटाइम लिबर्टेरियन अवॉर्ड-

- हाल ही में भारतीय लेखक गुरचरण दास को नेपाल के काठमांडू में आयोजित 40वें विश्व सम्मेलन में 'लाइफटाइम लिबर्टेरियन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।
- वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय लेखक हैं। उन्हें यह पुरस्कार लिबर्टी इंटरनेशनल ने स्वतंत्रता, उद्यमशीलता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया है।



विविध तथ्य-

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पुडुचेरी पुलिस को 'प्रेसिडेंट कलर्स' दिया। यह किसी सैन्य या पुलिस इकाई का देश का सर्वोच्च सम्मान है।
- हाल ही में आर्टेमिस-II मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है।
- 8 अगस्त, 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को उसकी बहादुरी, उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के लिए प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति कलर्स' प्रदान किया।
- भारत सरकार ने 13 अगस्त, 2026 को 115 कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किये।
- डॉ. पद्मा गुरमैत को सोवा-रिंग्पा चिकित्सा में अनुकरणीय काम के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया।
- भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति ने नेपाली सेना के 'मानद जनरल' की रैंक से सम्मानित किया है।
- दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ उत्कृष्ट सेवा के लिए 210 भारतीय पीसकीपर्स को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया।



Samyak
An Institute For Civil Services

Join our Social Media Platforms



सम्मेलन/बैठक /मेला/महोत्सव/प्रदर्शनी

अंतरराष्ट्रीय

भारत-रवांडा संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) का सत्र-

- संस्करण- प्रथम
- आयोजन तिथि- 30 और 31 जुलाई, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- नेतृत्व-
 - भारत- श्री अमित कुमार
 - रवांडा- श्री वर्जिल रवान्यागाटारे
- उद्देश्य- भारत-रवांडा द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा करना, व्यापार में विविधता लाना, दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाना और रसद संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक स्थायी, संरचित और आवधिक शीर्ष तंत्र की स्थापना करना।

भारत-रूस कार्य समूह का सत्र-

- संस्करण-12वां
- आयोजन तिथि- 7 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- अध्यक्षता-श्री अमरदीप सिंह भाटिया व श्री एलेक्सी गृजदेव
- उद्देश्य- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग के तहत आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग को सुनिश्चित किया जाना।

भारत-नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का सत्र-

- सत्र/संस्करण- चौथा सत्र
- आयोजन तिथि- 10-11 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- नेतृत्व-
 - भारतीय- श्री अमित कुमार
 - नामीबियाई- सुश्री एनडीता एनघिपोंडोका-रोबियाती
- भारत-नामीबिया व्यापार और आर्थिक प्रगति-
 - वस्तु व्यापार- द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 के \$568.40M से बढ़कर 2025-26 में \$592.94 मिलियन हो गया (भारत का निर्यात- \$349.09M, आयात- \$243.85M)।

- सेवा व्यापार- वर्ष 2024 में 7.34% की वृद्धि के साथ \$380 मिलियन तक पहुंचा।
- नामीबिया में 15 जून 2026 को शुरू की गई यूपीआई-आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली “Wayame” का विस्तार जारी रखने तथा RBI और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच फिनटेक सहयोग ढांचे पर सहमति बनी।

भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन-

- आयोजन तिथि- 19-21 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- सिंगापुर
- इस सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर और अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया।

मलेशिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक-

- बैठक/संस्करण- दूसरी
- आयोजन तिथि- 18 अगस्त, 2026
- यह बैठक लोक प्रशासन और शासन सुधारों के क्षेत्र में सहयोग विषय पर आयोजित हुई थी।

भारत और ब्रिटेन ने रक्षा सलाहकार समूह की बैठक-



- संस्करण/बैठक- 25वीं बैठक
- आयोजन तिथि- 21 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- सह-अध्यक्षता- रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और श्री जेरेमी पोकलिंगटन
- इसमें ‘भारत-ब्रिटेन विजन 2035’ और ‘दस-वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप’ के तहत अनुसंधान एवं विकास पर विशेष बल देते हुए रक्षा औद्योगिक सहयोग की समीक्षा की गयी।

भारत-नेपाल संयुक्त कार्य समूह की बैठक-

- संस्करण/बैठक- 14वीं
- आयोजन तिथि- 20-21 अगस्त 2026
- आयोजन स्थल- देहरादून
- नेतृत्व-
 - भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती पौसुमी बासु ने किया।
 - नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आनंद कफ्ले ने किया।
- इसमें दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की तथा इन क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की।

भारत-कंबोडिया व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह की बैठक-

- संस्करण/बैठक- तीसरी
- आयोजन तिथि- 24 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- नोम पेन्ह, कंबोडिया
- सह-अध्यक्षता- श्री अमित वर्मा और श्री लॉन्ग केमविचेट।
उद्देश्य- द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना।
- कंबोडिया वर्तमान में आसियान में भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो इस समूह के साथ भारत के कुल व्यापार का 0.31 प्रतिशत हिस्सा है।

भारत और न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद-

- संवाद क्रम- दूसरा
- आयोजन तिथि- 25 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- वेलिंगटन
- सह-अध्यक्षता-
 - श्री अमिताभ प्रसाद
 - श्री रिचर्ड श्मिट
- उद्देश्य- समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तथा समग्र रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना।

भारत-मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक

- संस्करण/बैठक- 7वीं
- आयोजन तिथि- 24 से 25 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- मोरक्को
- सह-अध्यक्षता-

□ श्री जितिन प्रसाद, श्री उमर हेजीरा

- उद्देश्य- द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और व्यापार बढ़ाना, बाजार पहुंच सुनिश्चित करना, निवेश और औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देना।

भारतीय-वियतनाम तटरक्षक बल के बीच उच्च स्तरीय बैठक-

- संस्करण/बैठक- सातवीं
- आयोजन तिथि- 25 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- चेन्नई
- अध्यक्षता-
 - परमेश शिवमणि
 - जनरल लुओंग दिन्ह हंग
- इस बैठक में समुद्री खोज एवं बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

भारत-कुवैत संयुक्त रक्षा समिति की बैठक-

- संस्करण/बैठक- प्रथम
- आयोजन तिथि- 28 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- सह-अध्यक्षता- श्री अमिताभ प्रसाद और राएद अलसकरान ने
- बैठक में दोनों देशों ने प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, सैन्य चिकित्सा, अधिकारिक सैन्य वार्ता, रक्षा उद्योग तथा अनुसंधान एवं विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की बैठक-

- संस्करण/बैठक- चौथी
- आयोजन तिथि- 24 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- ब्यूनस आयर्स
- नेतृत्व-
 - भारत का नेतृत्व वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने किया।
 - अर्जेंटीना का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध सचिव फर्नांडो ब्रून ने किया।
- प्रमुख तथ्य-
 - वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।

- भारत, अर्जेंटीना का पाँचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा।
- कैटामार्का में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी 'काबिल' की पहली लिथियम खनन परियोजना के दूसरे चरण की ड्रिलिंग पूर्ण हो चुकी है।
- इस बैठक में फाइव-जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विमानन और परमाणु व अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है।

भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की बैठक-

- संस्करण/बैठक- 8वीं
- आयोजन तिथि- 31 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- ब्रासीलिया, ब्राजील
- सह-अध्यक्षता- राजेश अग्रवाल और तातियाना लैसर्दा प्राजेरेस
- तथ्य-
 - भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025-26 में 15.07 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
 - दोनों पक्षों ने विविध, संतुलित और निरंतर साझेदारी के माध्यम से, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग सामान और मशीनरी के क्षेत्र में, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई।

ब्रिक्स एंटी-करप्शन वर्किंग ग्रुप (एसीडब्ल्यूजी) की बैठक-

- संस्करण- द्वितीय
- आयोजन तिथि- 4-5 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- हैदराबाद
- आयोजक- भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
- हैदराबाद की बैठक 2-3 जून, 2026 को वर्चुअल तौर पर हुई पहली ब्रिक्स एंटी-करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के नतीजों पर आधारित थी।

एसेट रिकवरी पर ब्रिक्स एक्सपर्ट नेटवर्क बैठक-

- संस्करण- द्वितीय
- आयोजन तिथि- 4-5 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- हैदराबाद
- आयोजक- भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
- इसमें ब्रिक्स सदस्यों ने एसेट रिकवरी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमापार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।

ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक-

- आयोजन तिथि- 3-4 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- विषय- सुदृढशीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास (ब्रिक्स)
- इस बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन (जेएसपी), 2026 का मसौदा और ब्रिक्स जेएसपी 2026 का संक्षिप्त संस्करण जारी किया गया।

ब्रिक्स वेक्स बाज़ार-



- आयोजन तिथि- 6-7 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- मुंबई
- उद्देश्य- दृश्य-श्रव्य और रचनात्मक उद्योगों में संवाद, व्यावसायिक जुड़ाव, ज्ञान के आदान-प्रदान और सीमा-पार साझेदारी के अवसर पैदा करके ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के बीच सहयोग को सुदृढ करना।
- यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मार्केटप्लेस है।
- नोट- ऑरेंज इकोनॉमी या रचनात्मक अर्थव्यवस्था- यह उन आर्थिक गतिविधियों का समूह है, जो रचनात्मकता, संस्कृति, कला और बौद्धिक संपदा पर आधारित होती हैं। इसमें विचारों को सांस्कृतिक और डिजिटल उत्पादों में बदला जाता है।

ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक-

- बैठक/संस्करण- 13वीं
- आयोजन तिथि- 7 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- भुवनेश्वर, ओडिशा
- अध्यक्षता- प्रल्हाद जोशी (केंद्रीय शिक्षा मंत्री)
- केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत 5 अगस्त, 2026 को भुवनेश्वर में तीसरी ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का भी आयोजन किया।

ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक-

- संस्करण/बैठक- 11वीं
- आयोजन तिथि- 8 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- भोपाल, मध्यप्रदेश
- उद्देश्य- ब्रिक्स देशों में संस्कृति समन्वय को बढ़ावा देना।
- इस बैठक में भारत सहित 14 देशों ने भाग लिया, जिनमें 10 ब्रिक्स सदस्य देश और 4 भागीदार देश शामिल था।

ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक-

- आयोजन तिथि- 8 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- उदयपुर, राजस्थान
- आयोजक- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
- उद्देश्य- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा कानून व नीति में उभरती चुनौतियों का समाधान करने में सहयोग को मजबूत करना।
- यह बैठक वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत हुई।

ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ट्रैक)-

- संस्करण/बैठक- 7वीं
- आयोजन तिथि- 17 से 21 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- पुणे, महाराष्ट्र
- आयोजक- केन्द्रीय दूरसंचार विभाग
- विषय- एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन (आईसीटी)
- उद्देश्य- सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करना और एक सुरक्षित, समावेशी और लचीले डिजिटल भविष्य को आगे बढ़ाना।
- यह ब्रिक्स मंच के अंतर्गत देश भर में आयोजित की जा रही प्रमुख क्षेत्रों पर बैठकों की श्रृंखला का एक हिस्सा थी।

ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक

- संस्करण/बैठक- 12वीं
- आयोजन तिथि- 17-18 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- अध्यक्षता- भूपेंद्र यादव (केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री)
- विषय- सुदृढशीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास

प्राथमिकता वाले क्षेत्र- चार मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र-

1. सतत जीवन शैली
2. वनीकरण और जंगल की आग का प्रबंधन
3. सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था)
4. जलवायु अनुकूलन

ब्रिक्स युवा परिषद बैठक एवं युवा शिखर सम्मेलन-

- आयोजन तिथि- 19-20 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- गांधीनगर, गुजरात
- आयोजक- युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
- प्रमुख लक्ष्य एवं प्रभाव-
 - सदस्य देशों के बीच 'ब्रिक्स युवा सहयोग ढांचा' तैयार कर दीर्घकालिक सहयोग की नींव रखी गयी।
 - युवा नेताओं, स्वयंसेवकों और उद्यमियों के विचारों को व्यापक ब्रिक्स नीतिगत निर्णयों में शामिल किया गया।
 - ब्रिक्स राष्ट्रों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक जुड़ाव को सुदृढ़ किया गया।

ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक-

- आयोजन तिथि- 22 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

महासागर और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक-

- बैठक/संस्करण- 8वीं
- आयोजन तिथि- 12-14 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- गोवा
- आयोजक- राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) द्वारा
- इस कार्य समूह की बैठक ने महासागर और ध्रुवीय अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक अनुसंधान गतिविधियों के विकास पर विचार-विमर्श और चर्चा की गयी।

ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक-

- आयोजन तिथि- 22 और 23 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक-

- संस्करण- 10वां
- आयोजन तिथि- 6 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- जयपुर
- अध्यक्षता- भारत (ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 के तहत)
- विषय- "लचीलेपन, नवाचार, सहकारिता और स्थिरता के लिए निर्माण"
- नेतृत्व- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद।
- परिणाम-
 - 'दसवीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के संयुक्त घोषणापत्र' (Joint Declaration) को अपनाया गया।
 - PartNIR (न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर ब्रिक्स पार्टनरशिप) के तहत विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति हुई, जिसमें SME वर्किंग ग्रुप के लिए सहयोग ढांचा, फोटोवोल्टिक (सोलर) उद्योग वर्किंग ग्रुप के लिए कार्य योजना, और स्टार्टअप्स द्वारा नवाचार-संचालित विकास की कार्य योजना को अंतिम रूप देना शामिल है।

ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक-

- संस्करण- 16वां
- आयोजन तिथि- 7 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- जयपुर
- अध्यक्षता- केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल
- इससे पहले 3 और 4 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी।
- यह बैठक भारत के 'विकसित भारत@2047' के दृष्टिकोण में योगदान देने के उद्देश्य से आयोजित की गयी।

ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक-

- आयोजन तिथि- 12 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- जयपुर
- विषय- "द रोल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल इन मंबर कंट्रीज"
- मुख्य वक्ता- निर्मला सीतारमन (केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री)

ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) की बैठक-

- संस्करण/बैठक- दूसरी
- आयोजन तिथि- 19 अगस्त, 2026

- आयोजन स्थल- जयपुर
- अध्यक्षता- सचिव भुवनेश कुमार
- यह बैठक 25 मई 2026 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित पहली ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक पर आधारित थी।

राष्ट्रीय

नशा मुक्त युवा- विकसित भारत संकल्प अभियान-

- प्रारम्भ तिथि- 2 अगस्त, 2026
- लॉन्च- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
- उद्देश्य- युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना।
- यह अभियान मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलेगा।
- इस अभियान के तहत, नशामुक्त समाज के निर्माण में जागरूकता बढ़ाने और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।



जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन-



- आयोजन तिथि- 5 अगस्त 2026
- आयोजन स्थल- डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली
- आयोजक- वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद
- उद्देश्य- भारत के जीआई-टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देना और जीआई इकोसिस्टम में हितधारकों के बीच सहयोग को सुगम बनाना।

इंडिया मेडिकल डिवाइस-2026 सम्मेलन-

- संस्करण- 9वां
- आयोजन तिथि- 7-8 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- आयोजक- औषधि विभाग (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)
- विषय- विकसित भारत की ओर: गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को आगे बढ़ाना।
- यह सम्मेलन भारत की बढ़ती मेडटेक क्षमताओं को प्रदर्शित करने, वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

बायोफैच इंडिया 2026 कार्यक्रम-

- आयोजन तिथि- 6-8 अगस्त 2026
- आयोजन स्थल- इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा
- आयोजक- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

उद्देश्य-

- भारत के जैविक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार संबंधों का विस्तार करना।
- भारत के प्रमाणित जैविक उत्पादों की वैश्विक पहचान को बढ़ाते हुए भारतीय जैविक उद्यमों के लिए नए व्यापार के अवसर पैदा करना।
- बायोफैच इंडिया 2026 एपीईडीए, न्यूनबर्ग मेसे इंडिया और आईएफओएम-ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल की एक संयुक्त पहल है।
- यह प्रदर्शनी जैविक, प्राकृतिक और स्थायी खाद्य क्षेत्रों के भागीदारों को एक साथ लाती है, जो व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान और बिजनेस नेटवर्किंग के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है।

हर घर तिरंगा 2026 अभियान-

- आयोजन तिथि- 9 से 17 अगस्त, 2026
- आयोजन- सम्पूर्ण देश में
- यह अभियान नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से फहराने और देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का जश्न मनाने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान करता है।

शाइन-

- आयोजन तिथि- 11-12 अगस्त 2026
- आयोजन स्थल- देश भर में 83 केंद्र (ICMR संस्थान, MRHRU और संबद्ध फील्ड इकाइयां)
- आयोजक- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग-भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (डीएचआर-आईसीएमआर)
- लक्षित छात्र- कक्षा 9 से 12 के लगभग 30,000 छात्र (सरकारी व निजी स्कूल)
- यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम है, जो छात्रों को वैज्ञानिक शोध और सार्वजनिक स्वास्थ्य नवाचारों से सीधे जोड़ने का अवसर देता है।
- SHINE- Science, Health and Innovation for NextGen Explorers

IIHT SUTRA 2026-

- संस्करण- प्रथम
- आयोजन तिथि- 12 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में
- आयोजक- विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय
- विषय-"IIHTs: भारतीय हथकरघा क्षेत्र के भविष्य को बुनना- शिक्षित करना, नवाचार करना, बदलना"

राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइनर सम्मेलन 2026-

- आयोजन तिथि- 10 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में
- आयोजक- विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय
- इसमें भारत के हथकरघा क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु डिजाइन-आधारित नवाचार का प्रदर्शन किया गया।

सृजन: करघे से आवाजें कार्यक्रम-

- आयोजन तिथि- 13 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली में
- आयोजक- विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय
- उद्देश्य- महिला बुनकरों की व्यक्तिगत कहानियों, आकांक्षाओं और आवाजों को हथकरघा क्षेत्र के मुख्य संवाद में स्थापित करना।
- भारत के 6 अलग-अलग हैंडलूम क्लस्टरों से 100 से अधिक महिला बुनकर ने अपनी साझा बुनाई विरासत, रचनात्मकता और अनुभवों को साझा किया।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक-

- बैठक/संस्करण-31वाँ
- आयोजन तिथि- 20 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- महाबलीपुरम, तमिलनाडु
- अध्यक्षता- अमित शाह (केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)
- क्षेत्रीय परिषद-
 - स्थापना- राज्यों और उनसे संबंधित मामलों के पुनर्गठन की योजना के एक भाग के रूप में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।
 - उद्देश्य- केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों-राज्यों के मध्य सहयोग, समन्वय और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना।
- वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद् और सदस्य-
 - उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र
 - मध्य क्षेत्रीय परिषद्- छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
 - पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् - बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल
 - पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्- गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र
 - दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश

राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान-II

- आयोजन तिथि- 21 अगस्त से 21 नवंबर, 2026 (तीन महीनों के लिए)
- उद्देश्य- ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- इस अभियान को विशेष रूप से ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और उस पर गहनता से ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2026

- संस्करण/बैठक- नौवां
- आयोजन तिथि- 24-25 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- उद्घाटन- अमित शाह (केन्द्रीय गृह मंत्री)
- यह सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से लगभग 850 अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

केमकनेक्ट-2026-

- आयोजन तिथि- 24 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- आईआईटी मद्रास
- आयोजक-रसायन और पेट्रो रसायन विभाग तथा आईआईटी-मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से

सुजल ग्राम संवाद-

- संस्करण- 10वां, आयोजन तिथि- 25 अगस्त, 2026
- आयोजक- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय)
- अध्यक्षता- अशोक के.के. मीना
- यह संवाद जल जीवन मिशन 2.0 के तहत समुदाय-नेतृत्व वाले जल शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

विविध तथ्य-

- 17 अगस्त, 2026 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कोलकाता में कौशल मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन 'कौशल मंथन' आयोजित किया गया।
- 17 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का आयोजन होगा।
- भारतीय तटरक्षक बल फरवरी, 2027 में नई दिल्ली में वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन (सीजीजीएस) के पांचवें संस्करण की मेजबानी करेगा।

निर्वाचन और नियुक्ति

राष्ट्रीय

वर्षा अशोक अगलावे-

- यह वरिष्ठ जीवाश्म वैज्ञानिक है।
- इनको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की 54वीं डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है।
- वह जीएसआई के 176 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख बनी हैं।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण-
 - स्थापना- वर्ष 1851
 - मुख्यालय- कोलकाता में
 - क्षेत्रीय कार्यालय- छह (कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद और शिलांग)
 - यह खान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।



एस. सोमनाथ-

- यह इसरो के पूर्व अध्यक्ष है।
- इनको भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड में चार साल के लिए अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी दोबारा नियुक्त किया गया है।

विश्वेश नेगी-

- इनको ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है।



तेजपाल सिंह-

- इन्होंने वायु सेना के उप प्रमुख का पद संभाला। तेजपाल सिंह ने एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का स्थान लिया है, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए।

विली वॉल्श-

- यह आयरलैंड के विमानन विशेषज्ञ है।
- इन्होंने इंडिगो का सीईओ बनाया गया है।

श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा-

- इन्होंने 1 अगस्त, 2026 को रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) का पदभार संभाला है। यह इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस (आईडीएएस) की 1991 बैच की अधिकारी है।

राहुल नवीन-

- यह प्रवर्तन निदेशालय के निदेश है। भारत सरकार ने इनका कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया है। ये 13 अगस्त, 2027 तक इस पद पर रहेंगे।
- राहुल नवीन 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं।

तेजपाल सिंह-

- यह वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी है। इन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाला है।
- उन्होंने एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का स्थान लिया है।

अंतरराष्ट्रीय

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर

- यह बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के नेता थे।
- यह बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं।

अबेलाडो गैब्रियल डे ला एस्प्रीएला ओटेरो-

- यह कोलंबियाई राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने 7 अगस्त, 2026 से कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की हैं।
- यह 'डिफेंडर्स ऑफ़ द होमलैंड' राजनीतिक दल के संस्थापक है।

हाकाइंडे हिचिलेमा-

- यह पुनः जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं।
- हिचिलेमा को 29 लाख से अधिक वैध मत प्राप्त हुए।
- हिचिलेमा सत्तारूढ़ यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट से संबंधित हैं।

आभा नायर पटेल-

- जाम्बिया की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है।
- आभा नायर भारतीय मूल की हैं।
- उनके माता-पिता वर्ष 1973 में नौकरी के लिए दिल्ली से जाम्बिया चले गए थे।

नाथन थॉमस-

- यह फ्लोरिडा (अमरीका) निवासी है। इन्होंने 18 साल 346 दिन की उम्र में कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हासिल की।

गौतम रंगराजन-

- भारतीय मूल के रणनीतिकार है। इनको ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने विशेष सलाहकार नियुक्त किया है।
- वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को संरचना और प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर सलाह देंगे।

सुंदर कटवाला-

- भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक, पत्रकार और विचारक हैं। इनको ब्रिटेन के 'नेशनल लॉटरी कम्युनिटी फंड' के बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

विविध तथ्य-

- एयर मार्शल तेजपाल सिंह- इन्होंने 1 अगस्त, 2026 को उप वायु सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया।
- एडमिरल ए एन प्रमोद- इन्होंने 1 अगस्त, 2026 को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा- इन्होंने 3 अगस्त, 2026 को नौसेना संचालन महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है।
- मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति मुखर्जी को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है।
- एंड्रास बाका- हाल ही में हंगरी की संसद ने इनको राष्ट्रपति चुना है।

निधन**राष्ट्रीय****सुमित सरकार-**

- यह भारत के प्रख्यात इतिहासकार थे जिनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने 'द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल', 'मॉडर्न इंडिया' जैसी प्रसिद्ध कृतियों की रचना की थी।

**प्रदीप रावत-**

- यह जाने-माने अभिनेता थे जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने फिल्म 'गजनी' में विलेन की भूमिका निभाई थी।

एम. पी. परमेश्वरन-

- यह भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक, लेखक और वामपंथी विचारक थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया।

एम.एस. लिब्रहान-

- पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

- इन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस की जांच की थी।
- वह मद्रास और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे।

जनरल विश्वनाथ शर्मा

- यह भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे वर्ष 1988 से 1990 तक भारतीय थल सेना के 14वें प्रमुख रहे।
- वे स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे।

ए. बालकृष्णन-

- यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल और विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने वायु सेना में 16 वर्षों तक सेवा की और 1973 में सेवा छोड़कर केंद्र के साथ पूर्णकालिक रूप से काम करना शुरू किया था।

सज्जन कुमार-

- यह कांग्रेस के पूर्व सांसद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे तीन बार लोकसभा सांसद रहे थे।
- यह 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी और तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

श्री डी. वाई. पाटिल



- यह भारत के प्रख्यात शिक्षाविद और समाजसेवी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है।
- यह त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे।
- इनको वर्ष 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

सौकार जानकी-

- यह दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री थी जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में छह दशकों में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया।

राजा सेन-

- यह बंगाली सिनेमा के निर्देशक थे जिनका 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनको तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

जीवी नारायण राव-

- यह तेलुगु सिनेमा के अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था।

सन्देश कोहली-

- यह भारतीय फिल्म डायरेक्टर थे जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने फूल और कांटे जैसी प्रसिद्ध फिल्मों को डायरेक्ट किया था।

अंतरराष्ट्रीय

निर्मल पुर्जा-

- यह मशहूर नेपाली पर्वतारोही थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 8,000 मीटर से ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियां सिर्फ 6 महीने में चढ़ ली थीं।
- पुर्जा की इस उपलब्धि पर '14 पीक्स: नर्थिंग इज इम्पॉसिबल' नाम की फिल्म भी बनी थी।

वेंडेल बेरी-

- यह अमेरिकी कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और पर्यावरण कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अमेरिकी ग्रामीण जीवन, कृषि, भूमि-उपयोग और औद्योगिक खेती पर लिखे गए उनके विचारोत्तेजक लेखन के लिए जाने जाते थे।

विविध तथ्य

- हेराल्ड पंचम- यह नॉर्वे के राजा थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है।
- हेडन पेनेटिएर- यह अमेरिकी एक्ट्रेस हैं जिसका 36 साल की उम्र में निधन हो गया।
- विश्व नाथ शर्मा- यह भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है।

■■■■

अभियान/ओपरेशन /युद्धअभ्यास

संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-

- संस्करण- 15वां
- आयोजन तिथि- 18 से 31 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- विभावादी रंगसिट कैप, थाईलैंड
- आयोजक- भारत-थाईलैंड
- उद्देश्य- भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना।
- इस अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2025 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था।
- वर्ष 2006 में शुरू हुआ मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को सुदृढ़ बनाने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच है।



स्फोटक आयुध निस्तारण (ईओडी) अभ्यास 2026-

- संस्करण- 8वां संस्करण
- आयोजन तिथि-10 से 14 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि
- उद्देश्य- दोनों देशों की विशेषज्ञ गोताखोरी एवं टीमों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना।
- भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना वर्ष 2005 से संयुक्त रूप से जहाज का मलबा हटाने एवं बचाव व विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास आयोजित करती आ रही हैं।

‘रोटर क्लैप-III’ युद्धाभ्यास-

- आयोजन- अगस्त, 2026 (शुरुआती सप्ताह में)
- आयोजन स्थल- पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर
- आयोजक- भारतीय वायुसेना
- इस युद्धाभ्यास का मुख्य विषय ‘काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स’ था।
- उद्देश्य- कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोनों और मानव-रहित हवाई खतरों का पता लगाना, उनकी निगरानी करना और उन्हें नष्ट करने की रणनीतियों को जांचना था।
- भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ‘तरंगशक्ति-2026’ सितम्बर के अंत से जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित होगा।
- ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026- यह मिस्र और चीन के बीच आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास था।



■■■■

प्रमुख दिवस

विश्व स्तनपान सप्ताह/दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त
- विषय- जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान- जो प्रभावी है, उसे मजबूत करना।
- उद्देश्य- शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- प्रथम- 1992 में आयोजित
- प्रमुख तथ्य- भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1-7 अगस्त 2026 के दौरान इसका आयोजन किया।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 7 अगस्त
- आयोजन का उद्देश्य-
 - भारत के हथकरघा बुनकरों एवं उनके योगदान को सम्मान देना।
 - हथकरघा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- प्रथम बार आयोजित- 7 अगस्त, 2015

प्रमुख तथ्य-

- भारत सरकार ने 29 जुलाई 2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था।
- पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया।
- 7 अगस्त का चयन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के शुभारंभ की स्मृति में किया गया।

अगस्त क्रांति दिवस/भारत छोड़ो आंदोलन दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 8 अगस्त
- उद्देश्य-
 - 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को स्मरण करना।
 - आंदोलन के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना।
- 8 अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया।

विश्व के आदिवासी/स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 9 अगस्त
- विषय- स्वदेशी दाइयों का सम्मान- जीवन एवं कल्याण की सुरक्षा
- उद्देश्य-
 - विश्व के स्वदेशी समुदायों के अधिकारों एवं योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
 - उनकी संस्कृति, परंपराओं एवं ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण।
- प्रथम- वर्ष 1995 में पहली बार मनाया गया।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 दिसंबर, 1994 के प्रस्ताव 49/214 द्वारा 9 अगस्त को यह दिवस घोषित किया था।

विश्व जैव ईंधन दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 10 अगस्त
- उद्देश्य-
 - जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
 - जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयासों को रेखांकित करना।
 - ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।

विश्व शेर दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 10 अगस्त
- उद्देश्य- शेरों के संरक्षण और उनके आवास को बचाने के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना।
- एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी, जो 2025 में बढ़ कर 891 हो गई है।

विश्व हाथी दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 12 अगस्त
- उद्देश्य- हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना।
- इस दिवस को आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त, 2012 को लॉन्च किया गया था।
- भारत दुनिया के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथियों का घर है, जो वैश्विक हाथी संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

- भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से तैयार 'भारत के हाथी गलियारे, 2023' के अनुसार, ये गलियारे चार क्षेत्रों में फैले हुए हैं। पूर्वी-मध्य क्षेत्र में सर्वाधिक 52 गलियारे हैं, इसके बाद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 48, दक्षिणी क्षेत्र में 32 और उत्तरी क्षेत्र में 18 गलियारे हैं। राज्यों में पश्चिम बंगाल 26 गलियारों के साथ शीर्ष पर है, जो कुल राष्ट्रीय औसत का 17% से अधिक है।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 12 अगस्त
- विषय- अलग-अलग परिस्थितियाँ, समान आकांक्षाएँ
- उद्देश्य-
 - युवाओं से संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना।
 - युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना तथा युवाओं के अधिकारों एवं अवसरों को मजबूत करना।
 - विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले युवाओं की समान आकांक्षाओं को रेखांकित करना।
- प्रथम- 12 अगस्त, 2000
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने Resolution 54/120 के माध्यम से इसे मान्यता दी।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस-

- आयोजन- प्रतिवर्ष 14 अगस्त
- यह राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, जो 1947 के भारत विभाजन की विभीषिका के स्मरण के रूप में मनाया जाता है।
- इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वर्ष 2021 में मनाए जाने की घोषणा की थी।

भारत का स्वतंत्रता दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 15 अगस्त
- विषय- "Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047"
"150 Years of Vande Mataram"

विश्व मानवीय दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 19 अगस्त
- उद्देश्य-
 - मानवीय सहायता प्रदान करने वाले कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों का सम्मान।
 - संकटों से प्रभावित लोगों के प्रति वैश्विक एकजुटता।
 - मानवीय सहायता के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना।

- प्रथम- 19 अगस्त, 2009
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2008 में Resolution 63/139 द्वारा इसे स्थापित किया।

सद्भावना दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 20 अगस्त
- उद्देश्य-
 - राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना।
 - सभी समुदायों के बीच सौहार्द एवं भाईचारे की भावना मजबूत करना।

भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 20 अगस्त
- उद्देश्य-
 - अक्षय एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना।
 - जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के महत्व को समझाना।
 - स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस-

- आयोजन- प्रतिवर्ष 23 अगस्त
- भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

विश्व झील दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 27 अगस्त
- उद्देश्य-
 - झीलों एवं उनके पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
 - झीलों के प्रदूषण, अतिक्रमण, अत्यधिक दोहन एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान देना।
 - झीलों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय खेल दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 29 अगस्त
- उद्देश्य-
 - खेल एवं शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना।
 - खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सम्मान करना।
 - युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना।
 - स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना।

- यह मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी थे।
- सामान्यतः राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 29 अगस्त
- उद्देश्य-
 - परमाणु हथियार परीक्षणों के मानवीय एवं पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति जागरूकता।
 - सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रयास।
 - परमाणु-मुक्त विश्व के लक्ष्य को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 30 अगस्त
- उद्देश्य-
 - लघु उद्योगों/MSMEs के योगदान को रेखांकित करना।
 - छोटे उद्यमों, उद्यमिता एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना।
 - आर्थिक विकास में छोटे उद्योगों की भूमिका को बढ़ावा देना।
- प्रथम- 30 अगस्त, 2001

विश्व स्तनपान सप्ताह-

- आयोजन- 1 से 7 अगस्त, 2026
- थीम- “जीवन की सशक्त और स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान : कारगर उपायों को सुदृढ़ बनाना”

विविध

‘ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स’ पुस्तक-



- लॉन्च/विमोचन- 12 अगस्त, 2026
- लेखक- पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद
- विमोचक- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
- यह पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की आत्मकथा है।

‘संकल्प से सिद्धि का मोदी युग’ पुस्तक-



- विमोचन तिथि- 27 अगस्त, 2026
- विमोचन स्थल- उपराष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन
- विमोचनकर्ता- उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन
- लेखक- श्री घनश्याम तिवारी (राज्यसभा सांसद)
- यह पुस्तक पिछले बारह वर्षों में भारत की यात्रा का वर्णन करती है।

गांधी: फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ आनंद टी. हिंगोरानी-

- हाल ही में सैफ्रनआर्ट ने महात्मा गांधी के 688 हस्तलिखित संदेशों को 16.20 करोड़ रु. में नीलाम किये हैं।
- इन्हें गांधी: फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ आनंद टी. हिंगोरानी नाम से नीलाम किया गया था।
- गांधीजीने ये संदेश अपने सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी आनंद टी. हिंगोरानी को पत्नी विद्या के निधन के बाद दो साल तक लिखे थे। इन्हें बाद में ‘ए थॉट फॉर द डे’ किताब में शामिल किया गया था।

मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-



- हाल ही में केरल की केजिया लीज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज अपने नाम किया है।
- मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले का आयोजन सीतापुरा, जयपुर में हुआ था। इसमें तमिलनाडू की वैष्णवी गणेश दूसरे और गुजरात की अनुश्री सातवलेकर तीसरे स्थान पर रहीं।

मिस टीन इंटरनेशनल 2026-

- हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस टीन इंटरनेशनल 2026 के ग्रैंड फिनाले में क्यूबा की जोआना उरांगा ने मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब जीता है।
- रनर अप-
 - प्रथम रनर अप- नामीबिया की चैंटल बोएरेन
 - द्वितीय रनर अप- पराग्वे की जूलियाना ओकारिज
 - तृतीय रनर अप- अमेरिका की एंड्रिया अल्मेस्टिका

एन. चंद्रशेखरन-

- यह टाटा संस के चेयरमैन है। इन्होंने 12 अगस्त, 2026 को टाटा संस के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है।

लक्ष्मणन मय्यप्पन-

- यह दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। इन्होंने मात्र 16 साल और 170 दिन की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता हासिल की।
- यह वर्तमान में दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में रहते हैं।

पिया डांडिया-

- यह भारतीय-अमरीकी शिक्षिका है। इन्होंने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव जीता है।

विविध तथ्य-

- 13 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने रक्षा मंत्रालय की गृह पत्रिका 'सशक्त भारत' के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' विशेषांक का विमोचन किया।
- कैलिफोर्निया विधानसभा ने 8 नवंबर को 'दिवाली दिवस' के रूप में मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है।

■■■■■



डॉ० हेमेन्द्र कुमार सिंह

मानवरहित हवाई वाहन

(UAV-Unmanned Aerial Vehicle/ Drone)



मानवरहित हवाई यान जो स्वायत्त रूप से या दूरस्थ रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ड्रोनो के विकास ने तीव्र तकनीकी प्रगति की है। ड्रोन अब कृषि, अवसंरचना, परिवहन और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों के लिए नवोन्मेषी समाधान प्रदान कर रहे हैं।

आहुति Mk-II (Ahuti Mk II)

हैदराबाद के एक डिफेंस-टेक स्टार्टअप Apollyon Dynamics द्वारा विकसित भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक मल्टीरोटर इंटरसेप्टर ड्रोन है, जिसने 498 किमी प्रति घंटे की प्रमाणित शीर्ष गति दर्ज कर 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराया है।

इसे हवा में आ रहे दुश्मन के ड्रोन, कामिकेज (सुसाइड) ड्रोन या लोइटरिंग म्यूनिशन को तुरंत ट्रैक करके हवा में ही मार गिराने (इंटरसेप्ट करने) के उद्देश्य से बनाया गया है।

UAV के प्रकार संरचना और उपयोग के आधार पर प्रमुख प्रकार

1



मल्टीरोटर यूएवी

इनमें दो से अधिक रотор होते हैं। ये फसल निरीक्षण जैसे कार्यों के लिए आदर्श माने जाते हैं।

2



सिंगल-रोटर यूएवी

इनमें हेलीकॉप्टर की तरह एक मुख्य रотор होता है। ये लंबी दूरी की उड़ान भर सकते हैं और हवाई इमेजिंग तथा सटीक छिड़काव के लिए एक ही स्थान पर स्थिर रह सकते हैं। ये आमतौर पर गैस इंजनों द्वारा संचालित होते हैं।

3



स्थिर पंख वाले यूएवी

ये सामान्य विमानों की तरह होते हैं और हवा में बने रहने के लिए एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते।

4



फिक्सड-विंग मल्टीरोटर हाइब्रिड यूएवी

ये फिक्सड-विंग और मल्टीरोटर यूएवी का एक हाइब्रिड रूप हैं। इनमें ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने और उतरने के साथ-साथ अन्य कार्य करने की क्षमता होती है। इनकी उड़ान अवधि अधिक होती है और ये हवा में काफी देर तक रह सकते हैं।

5



लचीले झिल्लीदार पंखों वाले यूएवी

ये तेज हवाओं और भीषण गर्मी की स्थिति में भी लक्षित उड़ान भर सकते हैं। ये अधिक भार वहन कर सकते हैं, भंडारण में आसान होते हैं, तथा इनमें बेहतर नियंत्रण और गतिशीलता होती है।



नोट: विभिन्न प्रकार के यूएवी का चयन उनके उद्देश्य, उड़ान क्षमता और संचालन क्षेत्र के आधार पर किया जाता है।



यूएवी के प्रकार



>> ————— ऊंचाई और उड़ान अवधि के आधार पर प्रमुख प्रकार ————— <<

1



तेज़, कम ऊंचाई से गहन प्रवेश एवं आक्रमण क्षमता



निम्न ऊंचाई पर गहन प्रवेश (LADP)



ऊंचाई: 0.5-1 किमी



उद्देश्य: कम ऊंचाई, लंबी दूरी और उच्च गति से भेदन की आवश्यकता वाले मिशनो के लिए उपयुक्त।



उदाहरण: यूएवी मॉडल Y1, यूएवी मॉडल Y2

2



निगरानी, टोही और दीर्घ अवधि तक उड़ान क्षमता



मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक उड़ान भरने वाले (MALE) यूएवी



ऊंचाई: 3 किमी-9 किमी



उड़ान अवधि: 24 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है।



उद्देश्य: मुख्य रूप से निगरानी, टोही और आक्रमण अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है।



उदाहरण: प्रीडेटर, एमक्यू-9 रीपर



नोट: विभिन्न प्रकार के यूएवी का चयन मिशन की आवश्यकता, उड़ान ऊंचाई और सहनशक्ति के आधार पर किया जाता है।

यूएवी (ड्रोन) का वर्गीकरण – आकार के आधार पर

श्रेणी	आकार और वजन	रेंज और उड़ान समय	उद्देश्य/उपयोग	उदाहरण
1. माइक्रो और नैनो यूएवी	 आकार: बहुत छोटे वजन: • नैनो: 250 ग्राम तक • माइक्रो: 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक	 रेंज: 10 किमी से कम  उड़ान समय: लगभग 1 घंटा तक (कम ऊंचाई और कम समय के लिए)	 खुफिया जानकारी जुटाना, लेकिन सैन्य ड्रोन के रूप में कम उपयोग (एआई और मशीन लर्निंग क्षमता की कमी के कारण)। झुंड ड्रोन के बड़े में उपयोग बहुत खतरनाक, क्योंकि वर्तमान में कोई प्रभावी प्रतिउपाय नहीं है।	 एयरोविरोनमेंट नैनो हर्मिंगबर्ड  डेलफलाई एमएवी
2. छोटे यूएवी	 आकार: लंबाई में 2 से 4 मीटर के बीच वजन: आमतौर पर 25 से 150 किलोग्राम के बीच	 रेंज: सामान्यतः 10 से 50 किमी  उड़ान समय: 1 से 3 घंटे तक	 हवाई फोटोग्राफी, मानचित्रण और निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखी।	 डीजेआई फैटम सीरीज  सेंसफलाई ईबी
3. मध्यम यूएवी	 आकार: लंबाई में 4 से 6 मीटर के बीच वजन: 150 से 600 किलोग्राम तक	 रेंज: 50 से 200 किमी  उड़ान समय: 10 से 20 घंटे तक	 अधिक भार वहन करने और लंबी अवधि के मिशनों में सक्षम होना।	 जनरल एटॉमिक्स एमक्यू-1 प्रीडेटर  एलघिट हरमैस 900
4. बड़े यूएवी	 आकार: लंबाई में 6 मीटर से अधिक वजन: 600 किलोग्राम से अधिक	 रेंज: 200 किमी से अधिक (वैश्विक स्तर तक)  उड़ान समय: 20 घंटे से अधिक (अत्यधिक लंबी अवधि)	 भारी भार वाले लंबे समय तक चलने वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे सैन्य निगरानी या माल परिवहन।	 आरक्यू-4 ग्लोबल हॉक  जनरल एटॉमिक्स एमक्यू-9 रीपर

नोट: रेंज, उड़ान समय और वजन मिशन, मॉडल और निर्माता के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

प्रकार	विशेषता (Feature)
	मैन्युअल ड्रोन (Manual) रिमोट कंट्रोल से पूरी तरह संचालित।
	स्वचालित ड्रोन (Autonomous) जीपीएस, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा नियंत्रित।
	सेमी-ऑटोनोमस (Semi-Autonomous) आंशिक रूप से मानव और मशीन, दोनों द्वारा नियंत्रित।

ड्रोन के प्रकार

नियंत्रण प्रणाली (Control System) के आधार पर:

नोट : विभिन्न ड्रोन अपने नियंत्रण तंत्र और उपयोग के आधार पर अलग-अलग कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं।

कुछ अन्य ड्रोन

मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के गुणधर्म

- मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) में स्वायत्त संचालन मंडराना ऊर्ध्वाधर लैंडिंग (कुछ प्रकारों में) कई ऊर्जा स्रोत और पेलोड बहुमुखी प्रतिभा जैसे विविध गुण होते हैं जो व्यापक नागरिक और सैन्य अनुप्रयोगों को सक्षम बनाते हैं।
- **ऊर्ध्वाधर लैंडिंग क्षमता** : सभी यूएवी ऊर्ध्वाधर लैंडिंग नहीं कर सकते। यह क्षमता कुछ विशेष प्रकार के ड्रोन में पाई जाती है जैसे कि घूर्णनशील पंखों वाले ड्रोन (उदाहरण के लिए क्वाडकोप्टर हेलीकोप्टर) और वीटीओएल (वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग) ड्रोन। स्थिर पंखों वाले यूएवी को आमतौर पर टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे की आवश्यकता होती है और वे ऊर्ध्वाधर लैंडिंग नहीं कर सकते।
- **स्वचालित रूप से स्थिर रहना** : केवल घूर्णनशील पंखों वाले यूएवी जैसे क्वाडकोप्टर और हेलीकोप्टर, ही एक ही स्थान पर स्थिर रह सकते हैं। स्थिर पंखों वाले यूएवी आगे की ओर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और स्थिर नहीं रह सकते।
- **ऊर्जा स्रोत** : ड्रोन विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं। कई छोटे ड्रोन बैटरी पर निर्भर होते हैं जबकि अन्य गैसोलीन इंजन हाइब्रिड सिस्टम या ईंधन सेल और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं।
- **स्वायत्त संचालन** : आधुनिक यूएवी में अक्सर जीपीएस नेविगेशन बाधा से बचाव और स्वचालित उड़ान पथ सहित स्वायत्त क्षमताएं होती हैं जिससे निरंतर मानवीय नियंत्रण की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **पेलोड की बहुमुखी प्रतिभा** : यूएवी विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जा सकते हैं जैसे कैमरे सेंसर या डिलीवरी पैकेज, जो उन्हें हवाई फोटोग्राफी से लेकर लॉजिस्टिक्स तक के अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखी उपकरण बनाते हैं।

ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में ड्रोन के प्रमुख उपयोग








★ सैन्य अनुप्रयोग ★

1 सैन्य ड्रोन



सैन्य ड्रोन युद्ध की प्रकृति को अधिक किफायती, सटीक और प्रभावी बना सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का उपयोग किया गया है।

2 निगरानी और टोही ड्रोन (ISR)



ये ड्रोन लंबे समय तक निगरानी कर सकते हैं और लक्ष्यों की स्थिति, भूभाग तथा दुश्मन की गतिविधियों की वास्तविक समय जानकारी देते हैं। इजरायल निर्मित हेरॉन ड्रोन 24 घंटे से अधिक समय तक मंडरा सकते हैं।

उदाहरण: निशांत यूएवी, TAPAS-BH-201, रूस्तम (DRDO), MQ-1 प्रीडेटर।

3 मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन (UCAV)



ये युद्ध अभियानों के लिए डिज़ाइन किए गए यूएवी हैं। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले कर सकते हैं तथा मिसाइल, बम और अन्य हथियार ले जा सकते हैं।

उदाहरण: शाहिद 129 (ईरान), घटक (आगामी भारतीय UCAV), हंटर-किलर (यूएसए)।

4 स्वार्म ड्रोन



ये ड्रोन का समूह होता है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करता है।

उदाहरण: हेरॉन TP जैसे उन्नत ड्रोन समूह-आधारित संचालन में उपयोगी हैं।

5 कामिकेज़ ड्रोन



इनमें विस्फोटक भरे होते हैं और ये लक्ष्य पर गिरकर नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें लोडिंग म्यूनिशन्स या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है।

उदाहरण: यूकेन-रूस संघर्ष में आत्मघाती ड्रोन, भारत का नागास्र।

प्रकाशन तिथि - प्रत्येक माह की 15 तारीख

पेज नं- 68

नागरिक अनुप्रयोग

1

हवाई सर्वेक्षण और मानचित्रण



स्थिर पंखों वाले यूएवी कृषि, आपदा प्रबंधन, खनन, वानिकी और शहरी नियोजन के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग प्रदान करते हैं, जो उपग्रह मानचित्रण की तुलना में लगभग 40% कम लागत पर संभव है।
उदाहरण: चक्रवात फानी के बाद पुरी में ड्रोन सर्वेक्षण।

2

राजमार्ग निगरानी



NHA परियोजनाओं में मासिक ड्रोन रिकॉर्डिंग निर्माण प्रगति की निगरानी, चरणों की तुलना, गुणवत्ता सत्यापन और विवाद समाधान हेतु डिजिटल साक्ष्य के रूप में उपयोगी है।

3

कानून प्रवर्तन और भीड़ प्रबंधन



मुंबई पुलिस जैसे संस्थान स्मार्ट पुलिसिंग के लिए ड्रोन का उपयोग भीड़ निगरानी, अपराध स्थल विश्लेषण और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कर सकते हैं।

4

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा



ड्रोन दूरस्थ क्षेत्रों में दवाओं, टीकों, रक्त के नमूनों और अंगों की संपर्कहित डिलीवरी में सहायक हैं। तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश की 'Medicine from the Sky' परियोजनाएँ इसका उदाहरण हैं।

5

कृषि



मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर युक्त कृषि ड्रोन मिट्टी और फसल स्वास्थ्य का उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण करते हैं। महिंदा एग्री सोल्यूशंस और मास्त ड्रोन के परीक्षणों से छोटे किसानों की पैदावार बढ़ी और लागत घटी। 'स्वानित्य योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का ड्रोन सर्वेक्षण भूमि विवाद कम करने में सहायक है।

6

नमो ड्रोन दीदी योजना



नवंबर 2023 में शुरू इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराकर कृषि दक्षता, फसल उत्पादकता, लागत में कमी और सतत आजीविका को बढ़ावा देना है।

7

आपदा प्रबंधन



NECTAR द्वारा विकसित विशेष ड्रोन बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी, भारी उपकरण वहन, लाइव हवाई दृश्य और खोज-बचाव अभियानों के बेहतर समन्वय में सहायक हैं।

8

रेलवे निगरानी



रेलवे ट्रैक, पुल और यादों के निरीक्षण के लिए ड्रोन उपयोगी हैं। रेलवे सुरक्षा बल इन्हें निगरानी, भीड़ नियंत्रण और अतिक्रमण रोकने के लिए भी तैनात करता है।

9

पर्यावरण संरक्षण



पन्ना टाइगर रिजर्व और काजीरंगा वन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन डेटा संग्रह, वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार की रोकथाम में मदद कर रहे हैं।



सार:

ड्रोन प्रौद्योगिकी रक्षा, निगरानी, कृषि, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढाँचा, रेल, पर्यावरण और महिला सशक्तीकरण सहित अनेक क्षेत्रों में परिवर्तनकारी भूमिका निभा रही है।



ड्रोन प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ

ड्रोन उपयोग से जुड़ी प्रमुख सामाजिक, नैतिक, पर्यावरणीय और कानूनी चुनौतियाँ



1

निजता

उच्च-रिजॉल्यूशन कैमरों से लैस ड्रोन बहुत ऊँचाई से तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे व्यक्तिगत स्थानों में घुसपैठ, बिना सहमति के निगरानी और गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका बढ़ती है।



2

नैतिक चिंताएँ

संघर्ष क्षेत्रों में ड्रोन सटीक हमले और सैन्य कर्मियों के लिए जोखिम में कमी जैसे सामरिक लाभ देते हैं। लेकिन इससे दूरस्थ युद्ध की नैतिकता, मानवीय जिम्मेदारी और युद्ध में प्रत्यक्ष मानवीय भागीदारी पर बहस बढ़ती है।



3

पर्यावरण पर प्रभाव

ड्रोन, विशेषकर जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ड्रोन, कार्बन उत्सर्जन में योगदान कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन की समस्या को बढ़ा सकते हैं।



4

हवाई क्षेत्र संबंधी मुद्दे

ड्रोन हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते हैं और कई ड्रोन जेट विमानों के समान ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। इससे टक्कर, आपात स्थिति और विमानन सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।



5

कानूनी और नियामक चुनौतियाँ

ड्रोन प्रौद्योगिकी की प्रगति कई बार कानूनी और नियामक ढाँचों के विकास से आगे निकल जाती है। सरकारें ड्रोन-आधारित लक्षित कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उचित बताती हैं, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं।



6

स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव

स्पष्ट नियमों और दिशानिर्देशों की कमी से जवाबदेही, पारदर्शिता और नियंत्रण से जुड़े प्रश्न उठते हैं। इससे ड्रोन उपयोग के दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ती है।



सार:

ड्रोन प्रौद्योगिकी जितनी उपयोगी है, उतनी ही उससे जुड़ी चुनौतियों को समझना और संतुलित नीतियों, सुरक्षा मानकों तथा जवाबदेह उपयोग को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

भारत का ड्रोन नियामक ढाँचा



भारत में ड्रोन ईकोसिस्टम को सरल, उदार और प्रोत्साहन-आधारित बनाने वाले प्रमुख तत्व

1



1. नियामक ढाँचा: ड्रोन नियम 2021

(वर्ष 2022 और 2023 के संशोधनों सहित)

ड्रोन नियम 2021 ने प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और परिचालन दायरे का विस्तार करके भारत के ड्रोन ईकोसिस्टम को महत्वपूर्ण रूप से उदार बनाया है।

2



2. प्रमुख सुधार

- अनुमोदन और फॉर्म की संख्या घटाई गई
- शुल्क को युक्तिसंगत किया गया
- ग्रीन एयरस्पेस तक पहुँच का विस्तार किया गया
- व्यापक नागरिक उपयोग की अनुमति दी गई
- पारंपरिक पायलट लाइसेंस के स्थान पर DGCA द्वारा जारी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट लागू किए गए

3



3. डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म

ई-गवर्नेंस और सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से ड्रोन पंजीकरण, पायलट सर्टिफिकेशन, टाइप सर्टिफिकेशन और एयरस्पेस अनुमति की सुविधा प्रदान की जाती है।

4



4. विनिर्माण सहायता

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना घरेलू ड्रोन और उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देती है तथा स्टार्टअप्स और MSME को सहायता प्रदान करती है।

5



5. कर प्रोत्साहन

ड्रोन पर GST को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे लागत कम हुई है और वाणिज्यिक अभियोग तथा प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा मिला है।

6



6. क्षमता निर्माण

- कार्यक्रम प्रशिक्षण और साझेदारी के माध्यम से मानवरहित विमान प्रणालियों (UAS) में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।
- NIDAR (National Innovation Challenge for Drone Application and Research) स्वायत्त ड्रोन नवाचार और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन को प्रोत्साहित करता है।



सार:

भारत का ड्रोन नियामक ढाँचा नियमों के सरलीकरण, डिजिटल मंजूरी, विनिर्माण प्रोत्साहन, कर राहत और क्षमता निर्माण के माध्यम से ड्रोन क्षेत्र को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है।



भारत में ड्रोन क्षेत्र की प्रमुख पहलें

2030 तक ड्रोन महाशक्ति बनने की दिशा में भारत सरकार की प्रमुख पहलें



1.



1. मेक इन India पहल

यह पहल ड्रोन क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण, निवेश और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य भारत में ड्रोन निर्माण को मजबूत करना है।



2.



2. उत्पादन-लिंकड इंसेंटिव (PLI) योजना

यह योजना भारतीय ड्रोन निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें ड्रोन से संबंधित सॉफ्टवेयर भी शामिल है और इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।



3.



3. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म

यह प्लेटफॉर्म उड़ान, निर्माण और अन्य गतिविधियों के लिए लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देता है तथा ड्रोन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।



4.



4. कृषि ड्रोन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

ये SOP कृषि ड्रोन के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग का मार्गदर्शन करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि उनका उपयोग नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो।



5.



5. निजी निवेश और स्टार्टअप

ड्रोन शक्ति योजना भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देती है। इससे स्टार्टअप्स को ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।



सार: भारत सरकार की ये पहलें स्वदेशी निर्माण, डिजिटल शासन, कृषि उपयोग और स्टार्टअप प्रोत्साहन के माध्यम से भारत को 2030 तक ड्रोन महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं।



स्वदेशी ड्रोन

• भारत ने स्वदेशी ड्रोन विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है •

1

अभ्यास

(डीआरडीओ, एडीई बेंगलुरु द्वारा निर्मित)



प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित एक किफायती सुपरसोनिक मिसाइल प्रदर्शक।

2

घातक

(डीआरडीओ, एडीई बेंगलुरु)



भारत का एक स्वदेशी, जेट-संचालित और रडार से बचने वाला (स्टेलथ) मानवरहित लड़ाकू विमान है।

3

एचएएल कैट्स (कॉम्बेट एयर टीमिंग सिस्टम)

(एचएएल और न्यूस्पेस आर एंड डी द्वारा निर्मित)



एक स्वदेशी मानवरहित हवाई युद्ध कार्यक्रम है। यह प्रणाली मानवयुक्त लड़ाकू विमान (मंदरशिप) के साथ मिलकर काम करने वाले एआई-सक्षम ड्रोन और विंगमैन का एक समूह तैयार करती है।

4

रुस्तम-1 और 2

(एडीई बेंगलुरु)



निगरानी और टोही अभियानों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक यूएवी। डीआरडीओ द्वारा निर्मित, 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम।

5

तापस-बीएच-201

(टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस-वियॉन्ड होराइजन-201)
(एडीई, बेंगलुरु)



विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए एक बहु-भूमिका वाला मानवरहित हवाई वाहन।

6

डीआरडीओ इंपीरियल ईगल

(डीआरडीओ की एडीई और सीएसआईआर की राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला)



इसका मुख्य उपयोग जासूसी, निगरानी और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है।

7

डीआरडीओ लक्ष्य

(एडीई बेंगलुरु)



एक स्वदेशी पायलट रहित लक्ष्य विमान (पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट - पीटीए) है, जिसे बेंगलुरु स्थित वैज्ञानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

8

डीआरडीओ नेत्र

(डीआरडीओ एवं आईडियाफोर्ज)



हवाई और समुद्री सतह के लक्ष्यों की निगरानी, ट्रैकिंग, पहचान और वर्गीकरण के लिए एक एईडब्ल्यू एंड सीएस (एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम)।

9

डीआरडीओ निशांत

(एडीई बेंगलुरु)



निगरानी और टोही अभियानों के लिए एक सामरिक यूएवी।

10

एनएएल/एडीई गोल्डन

(डीआरडीओ की एडीई और सीएसआईआर का एनएएल)



पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए एक बुनियादी प्रशिक्षण विमान।

11

एनएएल/एडीई पुष्पक

(डीआरडीओ की एडीई और सीएसआईआर का एनएएल)



विभिन्न परिवहन कार्यों के लिए एक सहायक परिवहन विमान।

12

वाहन-50

(बीईएल द्वारा निर्मित)



यह लॉजिस्टिक्स ड्रोन है जो पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में 50 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है।



आत्मनिर्भर भारत - स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी

राजस्थान के विभिन्न आयोग

राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission)

- भारतीय संविधान के भाग-14 में लोकसेवा आयोग का उल्लेख है। इसमें लोकसेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) है। इसी तरह राजस्थान सरकार की प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों का उल्लेख है। अनुच्छेद 310 में लोक सेवकों के प्रसादपर्यंत का सिद्धांत है, वहीं अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों के संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य सरकार को सलाह देती है लेकिन राज्य सरकार इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन सरकार को विधानमण्डल में सलाह न मानने का कारण बताना होगा।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोकसेवा आयोगों का गठन किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की तीन रियासतों जोधपुर (1939), जयपुर (1940), बीकानेर (1946) में लोकसेवा आयोगों का गठन किया गया।
- राजस्थान के राजप्रमुख मानसिंह द्वितीय द्वारा 16 अगस्त, 1949 को जारी अध्यादेश जो 20 अगस्त, 1949 को प्रभावी हुआ, की धारा 1(3) की पालना में 22 दिसंबर, 1949 को गजट का प्रकाशन हुआ। इसी दिन राजस्थान लोकसेवा आयोग की स्थापना मानी जाती है। इसका मुख्यालय जयपुर था, सर एस.के. घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने। जो नियुक्ति के समय राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
- पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर, 1958 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। आयोग के नए भवन (घूँघरा घाटी) तथा मोनोग्राम का उद्घाटन राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह ने 21 अक्टूबर, 2000 को किया।
- वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि-6 वर्ष या 62 वर्ष (जो भी पहले हो) है।
- 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों का प्रावधान था। जिसे 14 जुलाई, 2025 के मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार अध्यक्ष सहित 11 सदस्य कर दिया गया है।

राजस्थान लोकसेवा आयोग के नियम व अधिनियम -

1. कार्यों की सीमाएँ विनियमन 1951
2. सेवा शर्तें विनियम 1974
3. प्रक्रिया विनियम एवं विधि मान्यकरण अधिनियम 1975
4. राज. लोकसेवा आयोग (राजपत्रित कर्मचारी) सेवा नियम एवं विनियम 1991
5. राजस्थान लोकसेवा आयोग (लिपिकीय एवं अधीनस्थ कर्मचारी) सेवा नियम एवं विनियम 1999

अनुच्छेद 315- लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान -

- **अनुच्छेद 315(1)** - प्रत्येक राज्य में एक लोकसेवा आयोग होगा तथा गठन राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि से व राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 315(2)**- संयुक्त लोकसेवा आयोग का प्रावधान- राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर संसद संयुक्त लोकसेवा आयोग का गठन कर सकती है। जैसे 1966 में पंजाब व हरियाणा लोकसेवा आयोग का गठन।
- **अनुच्छेद 315(3)** - पूर्वोक्त किसी विधि में ऐसे आनुषंगिक और पारिमाणिक उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।
- **अनुच्छेद 315(4)** - यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा।

अनुच्छेद 316 : अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का उल्लेख।

- **अनुच्छेद 316(1) : नियुक्ति का प्रावधान** - राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। (राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर)

नोट - राजस्थान लोकसेवा आयोग अब तक :-

» (1949) स्थापना के समय 1+2 (अध्यक्ष एस.के. घोष व सदस्य- देवीशंकर तिवाड़ी एवं एन.आर. चंदोल्कर)

1968	1+3 (4)
1973	1+4 (5)
1981	1+5 (6)
2011	1+7 (8)
2025	1+10 (11)

- » **योग्यता** - राज्य लोकसेवा आयोग के आधे सदस्य (50 प्रतिशत) ऐसे होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रखते हों।
- » **कार्यवाहक अध्यक्ष** - किसी कारण से आयोग के अध्यक्ष का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में आयोग के अन्य सदस्य को राज्यपाल कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है। (15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा संशोधित)
- » **अनुच्छेद 316(2) पदावधि :-** राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पदग्रहण से 6 वर्ष या 62 वर्ष (इन दोनों में से जो पहले हो) तक। (41वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की अधिकतम आयु 60 से बढ़ाकर 62 की गई।)
- » **त्यागपत्र:-** राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य स्वहस्ताक्षर सहित लेख से अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं।
- » **अनुच्छेद 316(3) -** लोकसेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- **अनुच्छेद 317 -** लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन का प्रावधान।
- » **अनुच्छेद 317(1) -** कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर उसकी जाँच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। (अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार)
- » **अनुच्छेद 317 (2) -** राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को जाँच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है।
- » **अनुच्छेद 317(3) -** कदाचार के अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटा सकता है।
- दिवालिया घोषित होने पर
 - मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम होने पर
 - लाभ का पद स्वीकार करने पर
- **अनुच्छेद 318 -** लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
- राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा।
 - आयोग के कर्मचारिवृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में उपबंध राज्यपाल कर सकेगा। परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 319 लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध-**
- **अनुच्छेद 319(ख)** राज्य लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोकसेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष और किसी और राज्य लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।
- **अनुच्छेद 319 (घ)** राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अथवा उसी राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा लेकिन वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा।
- अनुच्छेद 320 - लोकसेवा आयोग के कर्तव्य/कार्य**
- **अनुच्छेद 320(1) -** राज्यलोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।
- **अनुच्छेद 320(2) -** यदि दो या अधिक राज्य संघ लोकसेवा आयोग से अनुरोध करते हैं तो यह भी उसका कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं संयुक्त भर्ती की स्कीम बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करे।
- **अनुच्छेद 320(3)** राज्य लोकसेवा आयोग से -
- (क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषय
 - (ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति/अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर।
 - (ग) राज्य सिविल सेवकों की हैसियत से सेवा पर प्रभाव डालने, सभी आनुशासनिक विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएँ हैं।
 - (घ) लोकसेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों के दावों के संबंध में।
 - (ङ) पेंशन के संबंध में/क्षतिपूर्ति के मामलों में परामर्श।
- निर्देशित किए गए किसी विषय पर राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श देने का कर्तव्य होगा।
- » **अनुच्छेद 320(4)** खण्ड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस रीति

के संबंध में जिसमें अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाए।

» **अनुच्छेद 320(5)** किसी राज्यपाल द्वारा खण्ड (3) के अधीन बनाए गए सभी विनियम बताए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन राज्य विधानमंडल द्वारा उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं।

- **अनुच्छेद 321 :-** लोकसेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति - राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर राज्य लोकसेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है।
- **अनुच्छेद 322 :-** लोक सेवा आयोग के व्यय - राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।
- **अनुच्छेद 323 :-** लोकसेवा आयोग के प्रतिवेदन
- **अनुच्छेद 323(2) :-** राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा।
- **राजस्थान लोकसेवा आयोग के प्रथम सचिव-** श्यामसुंदर शर्मा
- **राजस्थान लोकसेवा आयोग की प्रथम महिला सचिव-** ओटिमा बोरडिया
- राजस्थान लोकसेवा आयोग को 6 भागों में बांटा गया।
1. प्रशासनिक 2. भर्ती 3. परीक्षा 4. लेखा 5. विधि 6. शोध

राज. लोकसेवा आयोग के नवाचार :

- काउंसिलिंग/साक्षात्कार पत्र डाउनलोड प्रणाली (वर्ष 2018 से)
- आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (Visitor Management System) (वर्ष 2018 से)
- ऑनलाइन स्क्राइब (श्रुतिलेखक) पैनल (वर्ष 2019 से)
- प्री-लिटीगेशन कमेटी (वर्ष 2019 से)
- शिकायत निवारण पोर्टल - 29 नवंबर, 2021 से प्रभावी।
- M.L. कुमावत समिति (2021)-वार्षिक भर्ती कैलेंडर का सुझाव
- वन टाइम रजिस्ट्रेशन - प्रारंभ 20 जनवरी, 2022 से
- OMR में 5वाँ विकल्प भरना अनिवार्य।
- अभ्यर्थी सत्यापन पत्रक (Candidate Verification Sheet) (वर्ष 2023 से)
- आवेदन प्रत्याहरण विकल्प (Application Withdrawal Option) (वर्ष 2023 से)
- विभिन्न PSCs को डीबार अभ्यर्थियों का पूर्ण विवरण साझा करना (वर्ष 2024 से)
- टोकन चुनाव आधारित साक्षात्कार बोर्ड आवंटन (वर्ष 2024 से)
- अभ्यर्थी लाइव फोटो कैप्चर (वर्ष 2024 से)
- अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया (वर्ष 2024 से)
- प्रवेश पत्र का उन्नत स्वरूप (Enhanced Appearance of Admit Card) वर्ष 2024 से)

राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.सं.	अध्यक्ष	कब से कब तक (कार्यकाल)
1.	डॉ. एस.के. घोष	22-12-1949 से 25-01-1950
2.	एस.सी. त्रिपाठी	28-07-1950 से 07-08 -1951
3.	डी.एस. तिवारी (सबसे लंबा कार्यकाल)	08-08-1951 से 17-01-1958
4.	एम.एम. वर्मा	18-01-1958 से 03-12-1958
5.	एल.एल. जोशी (कार्यवाहक)	04-12-1958 से 31-07-1960
6.	वी.वी. नार्लीकर	01-08-1960 से 31-07-1966
7.	बी.एल. रावत	01-08-1966 से 03-09-1966
8.	आर.सी. चौधरी	04-09-1966 से 08-10-1971
9.	बी.डी. माथुर	09-10-1971 से 23-06-1973
10.	आर.एस. कपूर	24-06-1973 से 10-06-1975

11.	मोहम्मद याकूब (प्रथम मुस्लिम)	27-06-1975 से 30-06-1979
12.	आर.एस. चौहान	01-07-1979 से 10-09-1980
13.	हरिदत्त गुप्ता	11-09-1980 से 09-06-1983
14.	एस. अद्वीयप्पा	10-06-1983 से 26-03-1985
15.	डी.डी. चह्माण	27-03-1985 से 07-11-1985
16.	जे.एम. खान	08-11-1985 से 27-11-1989
17.	एस.सी. सिंघारिया (कार्यवाहक)	28-11-1989 से 04-09-1990
18.	यतेंद्र सिंह	05-09-1990 से 06-10-1995
19.	हनुमान प्रसाद	06-10-1995 से 30-09-1997
20.	पी.एस. यादव	01-10-1997 से 06-11-1997
21.	देवेंद्र सिंह	06-11-1997 से 30-12-2000
22.	एन.के. बैरवा	31-12-2000 से 22-03-2004
23.	एस.एस. टांक (कार्यवाहक)	26-03-2004 से 15-07-2004
24.	गोविंद सिंह तौक	15-07-2004 से 04-07-2006
25.	एच.एन. मीना (कार्यवाहक)	04-07-2006 से 19-09-2006
26.	सी.आर. चौधरी	29-09-2006 से 28-02-2010
27.	एम.एल. कुमावत	28-02-2010 से 01-07-2011
28.	बी.एम. शर्मा	01-07-2011 से 31-08-2012
29.	हबीब खाँ गौरान	31-08-2012 से 22-09-2014
30.	आर.डी. सैनी (कार्यवाहक)	24-09-2014 से 10-08-2015
31.	ललित के पंवार	10-08-2015 से 10-07-2017
32.	श्याम सुंदर शर्मा	11-07-2017 से 28-09-2017
33.	राधेश्याम गर्ग	18-12-2017 से 01-05-2018
34.	दीपक उप्रेती	23-07-2018 से 14-10-2020
35.	श्री भूपेंद्र सिंह यादव	14-10-2020 से 01-12-2021
36.	डॉ शिव सिंह राठौड़ (कार्यवाहक)	2-12-2021 से 29-01-2022
37.	जसवंत सिंह राठी (कार्यवाहक)	01-02-2022 से 15-02-2022
38.	संजय श्रोत्रिय	15-02-2022 से 1 अगस्त 2024
39.	कैलाश चंद्र मीना (कार्यवाहक)	06-08-2024 से 10-06-2025
40.	उत्कल रंजन साहू	10-06-2025 से 19 जून, 2026
41.	ले. कर्नल केसरी सिंह राठौड़ (कार्यवाहक)	20 जून, 2026 से वर्तमान तक

राजस्थान लोकसेवा आयोग के वर्तमान सदस्य (03 अगस्त, 2026)

नाम	पद
• श्री बाबू लाल कटारा	- निर्लंबित सदस्य
• प्रो. (डॉ.) अय्यूब खान	- सदस्य
• डॉ. सुशील कुमार बिस्सू	- सदस्य

- श्री हेमंत प्रियदर्शी - सदस्य
- डॉ. दीपक कुमार शर्मा - सदस्य
- प्रो. (डॉ.) संतोष आनंद - सदस्य
- श्री आशुतोष गुप्ता, आईएएस - सचिव
(कार्यवाहक)
और मुख्य परीक्षा नियंत्रक

महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान लोक सेवा आयोग में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में - डी.एस. तिवाड़ी (1951-58 तक 6 वर्ष 5 माह) का था।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग में सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष-बी.एल. रावत (01-08-1966 से 03-09-1966 मात्र 34 दिवस)
- रघुकुल तिलक जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे और राजस्थान के राज्यपाल भी।
- कोई भी महिला अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी है।
- एन.के. बैरवा:- राज. लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर रहे।
- एस.सी. त्रिपाठी:- राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा संघ लोकसेवा आयोग के सदस्य रहे।
- धूलेश्वर मीणा - राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे जो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य भी रहे।
- सी.आर. चौधरी - राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे जो नागौर से लोकसभा सदस्य रहे व केन्द्र सरकार में मंत्री।
- एस.डी. उज्ज्वल - राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे।
- देवेन्द्रसिंह, भूपेन्द्र यादव एवं उत्कल रंजन साहू (DGP)- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक रहे।
- जी.पी. पिलानिया- राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो राजस्थान पुलिस महानिदेशक भी रहे।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जिन्होंने समय पूर्व अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दिया। -
 1. कांता कथूरिया
 2. शिवपाल सिंह
 3. दिव्या सिंह
 4. मंजू शर्मा
 5. संगीता आर्य
- हबीब खाँ गौराणः - राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया।

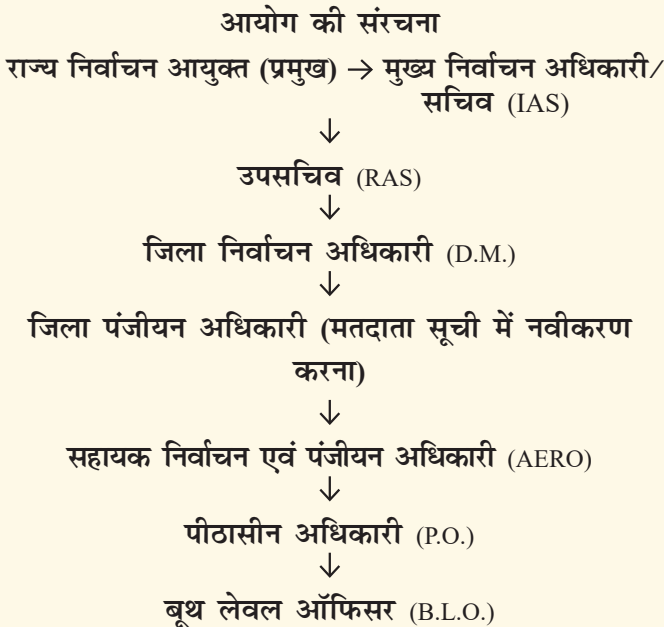
- वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे - के.एल. कमल
- वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे- एम.एल. कुमावत
- राजस्थान लोक सेवा आयोग की अब तक बनी महिला सदस्य - (7)

1. कांता कथूरिया
2. कमला भील
3. प्रकाशवती शर्मा
4. दिव्या सिंह
5. राजकुमारी गुर्जर
6. संगीता आर्य
7. मंजू शर्मा

- इनमें कांता कथूरिया एवं प्रकाशवती शर्मा संघ लोकसेवा आयोग की सदस्य भी रहीं।
- कमला भील राज्य सरकार में मंत्री भी रही।
- कांता कथूरिया राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष एवं विधायक रहीं।
- दिव्या सिंह लोकसभा सदस्य (भरतपुर) रहीं।
- राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा 1986 से राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा (RAS) का आयोजन किया गया।

राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission)

- राज्य में पंचायती राज और नगरीय स्वशासन संस्थाओं का चुनाव कराने और चुनावों की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने व नियंत्रण रखने के लिए भाग-9 अनुच्छेद 243 K(ट) और भाग-9क, के 243ZA(य.क) में क्रमशः पंचायतीराज संस्थाओं और नगर पालिका संस्थाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है।
- पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय स्वशासन संस्थाओं के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था क्रमशः 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा की गई।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 120 के अनुसार, निर्वाचन आयोग के कृत्यों का पालन किसी उप निर्वाचन आयुक्त या किसी राज्य निर्वाचन आयुक्त के सचिवों द्वारा भी किया जा सकेगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश 17 जून, 1994 को तथा कार्य 1 जुलाई, 1994 से शुरू, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय जयपुर में है।



- राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी - बी.सी. मोहंती
- राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। इसके मुखिया को राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं।
- **कार्यकाल**- पदग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक (जो भी पहले हो) राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना पदग्रहण कर सकता है। वह राज्यपाल को लिखित त्यागपत्र देकर कार्यकाल के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है।
- **योग्यता**-ऐसा व्यक्ति जिसने न्यूनतम 5 वर्ष तक राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन शासन सचिव या समान वेतन शृंखला के समकक्ष पद पर कार्य किया हो।
- **शपथ** - संविधान में प्रावधान नहीं।
- **नियुक्ति** - मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राज्यपाल द्वारा
- **सेवा शर्तें** :- निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तों, वेतन, भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। वेतन राज्य के मुख्य सचिव के समान, पदावधि के दौरान निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- **पद से हटाने की प्रक्रिया**:- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान।
- **वार्षिक रिपोर्ट**:- राज्य निर्वाचन आयुक्त रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं।
- **कार्य**
 - » पंचायतीराज एवं नगरीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न करवाना।

- » राज्य में पंचायती राज व नगरीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों हेतु मतदाता सूचियाँ तैयार करवाना।
- » चुनावों में निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखना।
- » स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा करना।
- » चुनाव चिह्नों का आवंटन व उससे संबंधित विवादों का निपटारा करना।
- » आदर्श आचार संहिता लागू करना।
- » परिसीमन व आरक्षण संबंधी कार्य।
- » स्थानीय निकायों में नवाचार व सुधार करना।
- वर्तमान में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन हैं।
- राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार द्वारा सुझाये पैनल में से की जाती है। इसका कार्य निर्वाचक नामावली तैयार करना, उसमें संशोधन करना व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करना।
- राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में हुआ। यह एक संवैधानिक पद है। इसके द्वारा नगरीय निकायों के चुनाव सर्वप्रथम 1994 में करवाए। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव सर्वप्रथम 1995 में करवाए गए।

राज्य निर्वाचन निम्नलिखित संस्थाओं के चुनाव करवाता है :

- **पंचायतीराज संस्थाएँ**-पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्।
- **नगरीय निकाय**-नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर निगम।

आयुक्त का नाम		कार्यकाल
1.	अमर सिंह राठौड़	01.07.1994 से 30.03.2000
2.	श्री नेकराम भसीन	01.07.2000 से 10.08.2002
3.	इंद्रजीत खन्ना	26.12.2002 से 26.12.2007
4.	अशोक कुमार पांडे	01.10.2008 से 30.09.2013
5.	राम लुभाया	01.10.2013 से 02.04.2017
6.	प्रेम सिंह मेहरा	03.07.2017 से 03.07.2022
7.	श्री मधुकर गुप्ता	14.08.2022 से 16.09.2025
8.	राजेश्वर सिंह	17.09.2025 से निरंतर

- सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त- अमरसिंह राठौड़ (6वर्ष)
- न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त - नेकराम भसीन
- इन्द्रजीत खन्ना राज्य के ऐसे निर्वाचन आयुक्त जो मुख्य सचिव भी रहे हैं।
- रामलुभाया ऐसे निर्वाचन आयुक्त जो गहलोत सरकार द्वारा नवीन जिलों के गठन के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष रहे।

लोकायुक्त (Lokayukt)

- लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगों और पाला (संरक्षक) से बना है। कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, अकुशलता, अपारदर्शिता आदि से नागरिक अधिकारों हेतु सर्वप्रथम स्वीडन ने 1809 में ओम्बुड्समैन कार्यालय की स्थापना की। ओम्बुड्समैन 'स्वीडिश भाषा' का शब्द है जिसका अर्थ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला है। स्वीडन के बाद क्रमशः फिनलैंड (1919), डेनमार्क (1954), नार्वे (1961), न्यूजीलैंड (1962), ब्रिटेन (1967) में ओम्बुड्समैन कार्यालय स्थापित हुए।
- भारत में 1960 ई. में लोकपाल शब्द की रचना एल.एम.सिंघवी ने की।
- 1963 हरिश्चन्द्र माथुर की अध्यक्षता में बनी राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकपाल व लोकायुक्त की आवश्यकता का सुझाव दिया।
- सम्पूर्ण विश्व में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जाँच एवं अन्वेषण हेतु उत्तरदायी संस्थान ओम्बुड्समैन के नाम से जानी जाती है। भारत में इसे लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। भारत में 1960 ई. में के.एम. मुंशी ने इस व्यवस्था की मांग उठाई।
- 5 जनवरी 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज' से संबंधित अपने प्रतिवेदन में केंद्र में लोकायुक्त और राज्यों में लोकपाल नामक सांविधिक संस्था की स्थापना पर बल दिया।
- सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। यद्यपि ओडिशा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ परंतु उसे 1983 में लागू किया गया।
- भारत में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आन्दोलन के परिणामस्वरूप लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 निर्मित हुआ।
- भारत में लोकायुक्त व लोकपाल विधेयक 1968 ई० से संसद में 9 बार लाया गया लेकिन पारित 10वीं बार में वर्ष 2011 में हुआ जिसे राज्यसभा में 17 दिसंबर, 2013 को तथा लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 को पारित किया इसके उपरांत 01 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी तथा 16 जनवरी, 2014 से यह विधेयक प्रभावी हुआ।

राजस्थान में लोकायुक्त

- लोकायुक्त संस्था का गठन जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोकसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जाँच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त

एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त और श्री के.पी.यू. मेनन को उपलोकायुक्त बनाया गया।

- गठन- 3 फरवरी, 1973 को मुख्यालय जयपुर, सांविधिक परामर्शकारी संस्था है।
- राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक लोक सेवक के संबंध में आरोप से अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरों को परेशान करने लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है।
- लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही न करना।
- लोक सेवक के किसी भी प्रतिज्ञान का तात्पर्य किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान या कठिनाई पैदा करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लोक-सेवक के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में अनुचित अर्थात् भ्रष्ट मंशा से कार्य किया गया हो।
- वह भ्रष्टाचार का दोषी है या इस तरह के सार्वजनिक रूप में अपनी क्षमता में ईमानदारी (निष्ठा) की कमी है।
- लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यपालन का व्यक्तिगत हित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया गया हो।

एक लोक सेवक के रूप में सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य

- मंत्री एवं सचिव के विषय में सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री होगा अर्थात् जाँच करने से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी।
- जबकि किसी भी सरकारी कर्मचारी के विषय में सक्षम कोई भी प्राधिकारी होगा जिसे नामित किया गया हो अर्थात् लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा।
- वर्तमान लोकायुक्त - प्रताप कृष्ण लोहरा (20-10-2022)

नियुक्ति (धारा-3)

- लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से की जाती है। (यदि विपक्ष का नेता नहीं तो विपक्षी सदस्यों द्वारा निर्मित ऐसी रीति जिसे विधानसभा अध्यक्ष निर्देशित करे)। उपलोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त के परामर्श राज्यपाल द्वारा की जाती है।

योग्यता -

- लोकायुक्त के लिए - उच्च-न्यायालय के सेवानिवृत्त/वर्तमान मुख्य न्यायाधीश/अन्य न्यायाधीश।

- **उपलोकायुक्त** - जो राज्य सतर्कता आयुक्त का पद धारण करने योग्य हो
- **शपथ :-** राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा
- **धारा 4-** लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।
- **धारा 5-** पदावधि (कार्यकाल) व सेवा शर्त

कार्यकाल (धारा 5)

- लोकायुक्त या उपलोकायुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले) तक की अवधि के लिये पद धारण करेगा, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं।
- **त्यागपत्र:-** लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं।
- **वेतन भत्ते:-** इनका निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है।
- लोकायुक्त का वेतन उच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश के समान (2.50 लाख रू. प्रतिमाह) और उपलोकायुक्त का वेतन अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान (2.25 लाख रुपये प्रतिमाह)
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- **धारा 6-** लोकायुक्त व उपलोकायुक्त को हटाया जाना:- संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है।
- **प्रक्रिया:-** उच्चतम न्यायालय की जाँच में दोष सिद्ध होने पर विधानमण्डल द्वारा विशेष बहुमत के प्रस्ताव पास करने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही हटाया जाता है।
- **नोट -** लोकायुक्त / उपलोकायुक्त का पद रिक्त होने पर राज्यपाल उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी अन्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार देता है।
- **धारा 7-** लोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले :- किसी को अनुचित हानि पहुँचाने/अनुग्रह/लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच, अकर्मण्यता/ पारदर्शिता की कमी का दोषी पाये जाने पर लोकायुक्त, लोकसेवकों व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आरोपों की जाँच कर सकता है।

लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार

- राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, लोकसेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करना।
- पंचायत समिति के प्रधान एवं उपप्रधान, नगर निगमों के महापौर एवं उपमहापौर नगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करना।

- स्थानीय प्राधिकरण, राजकीय कंपनियों के अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करना।
- जिला परिषद् के प्रमुख, उपप्रमुख के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करना।

अपवाद (जाँच के दायरे से बाहर) (धारा 8)

- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- किसी भी न्यायालय के अधिकारी अथवा कर्मचारी
- महालेखाकार
- सेवानिवृत्त लोकसेवक
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त
- राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी
- **नोट:-** लोकायुक्त 5 वर्ष से अधिक पुरानी शिकायत की जाँच नहीं कर सकता है।
- सरपंचों, पंचों व विधायकों के विरुद्ध भी शिकायतें की जाती हैं लेकिन उनके विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वे इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

शिकायत कैसे की जा सकती है :

- कोई भी नागरिक (लोकसेवक न हो) सम्बन्धित संस्थान के प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव को अपनी शिकायत निर्धारित प्रारूप में भेज सकता है।
- अपनी शिकायत वह स्वयं उपस्थित होकर या फैंक्स/ई मेल/ डाक द्वारा प्रेषित कर सकता है। यदि स्वयं शिकायत करने में असमर्थ हो तो उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व करने वाला या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।
- शिकायत के साथ शिकायतकर्ता का नाम, पता, आरोप पूर्ण विवरण के साथ संलग्न होना चाहिए।
- शिकायत के साथ 10 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र होना चाहिए।
- **नोट-** कोई व्यक्ति यदि लोकायुक्त द्वारा की जा रही जाँच में बाधा डाल रहा है तो दोषसिद्ध होने पर 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

जाँच एवं अन्वेषण करने की प्रक्रिया (धारा-10)

- शिकायत की जाँच-पड़ताल के संबंध में लोकायुक्त को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनके अनुसार वे शिकायत के संबंध में किसी भी ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, जो उनकी राय में जाँच संबंधी सूचना देने में समर्थ है, उसे बुला सकते हैं और उसके शपथ पर बयान भी ले सकते हैं। किसी दस्तावेज को पेश करवाना, शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी अभिलेख

को या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना, दस्तावेजों की जाँच के लिये कमीशन जारी करना आदि सभी अधिकार उन्हें प्राप्त हैं।

- लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 (अब BNS की धारा 229) के अंतर्गत एक न्यायिक कार्यवाही है। यह सचिवालय दोषी लोकसेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण के सिद्धांत का अनुसरण करता है, इसलिये यह संस्था लोकसेवकों के विरुद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गहन परीक्षा कर विषय की सच्चाई तक पहुँचने का प्रयास करती है। परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट नहीं हैं तो इसके संबंध में विस्तृत तथ्यों की मांग की जाती है अन्यथा संबंधित विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगाई जाती है। यदि मामला प्रथमदृष्टया ही प्रारंभिक जाँच किये जाने का प्रतीत हो तो उसमें प्रारंभिक जाँच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।
- तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को उसका निरीक्षण करके आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों का इस सचिवालय द्वारा परीक्षण किया जाता है। यदि आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाते हैं तो शिकायत को रद्द कर दिया जाता है एवं यदि आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो उनके संबंध में इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जाँच किये जाने या सीधे ही जाँच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।
- प्रारंभिक जाँच के दौरान परिवादी, उसके साक्षी एवं सुसंगत अभिलेख के परीक्षण करने के बाद यदि किसी भी लोकसेवक के खिलाफ आरोपित अभिकथन प्रथमदृष्टया प्रमाणित नहीं हो पाए तो प्रारंभिक जाँच को बंद कर प्रकरण को रद्द कर दिया जाता है जिसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है।
- यदि शुरूआती जाँच में आरोप प्रथमदृष्टया सही पाए जाते हैं तो संतुष्ट होने पर राज्य सरकार को सिफारिश की जाती है और जरूरत समझने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारंभ करने के आदेश प्रदान कर संबंधित लोकसेवक को नोटिस और जाँच के आधारों का विवरण, उसका जवाब, शपथ-पत्र एवं ऐसे दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये भेजा जाता है जिसे वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना सही समझे और उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।
- लोकसेवक को जाँच के दौरान अपना पक्ष रखने, व्यक्तिगत सुनवाई एवं साक्षियों से प्रतिपरीक्षण का मौका दिया जाता है। जाँच के पश्चात् यदि लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाते हैं तो जाँच को बंद कर प्रकरण को रद्द कर दिया जाता है एवं इसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है।

- यदि लगाए गए आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध पाए जाते हैं तो उनके संबंध में राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अंतर्गत जाँच रिपोर्ट उसके सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाता है। जिसमें यदि लोकसेवक द्वारा कोई दौड़िक अपराध किया गया हो तो दौड़िक मामला संस्थित करने अन्यथा उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिशों की जाती हैं।
- यदि किसी मामले में किसी भी लोकसेवक के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाए लेकिन यह प्रतीत हो कि प्रशासन की किसी भी प्रक्रिया से भ्रष्टाचार अथवा कदाचार का अवसर मिलता है, तो यह सचिवालय सुझाव देता है कि ऐसी प्रक्रिया में समुचित परिवर्तन कर दिया जाए या संबंधित नियमों को उपयुक्त रूप से ऐसे संशोधित कर दिया जाए। जिससे लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की संभावना समाप्त हो जाए तथा आम लोगों को अनुचित परेशानी एवं अनावश्यक कठिनाई न हो। यदि शिकायत पूर्णतया झूठी और आधारहीन हो तो लोकसेवक को शिकायतकर्ता को अभियोजित करने की अनुमति भी दी जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट

- प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही से राज्यपाल को अवगत करवाने के लिये लोकायुक्त प्रतिवर्ष उन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आवश्यक होने पर शिकायतकर्ता को सूचित कर विशेष रिपोर्ट भी भेजी जाती है। राज्यपाल लोकायुक्त से प्राप्त विशेष रिपोर्ट (धारा 12) और वार्षिक रिपोर्ट धारा-12(4) अपने ज्ञापन सहित राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाते हैं।
- इस प्रकार जनसाधारण की समस्याओं के निराकरण तथा स्वच्छ, ईमानदार एवं कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिये मंत्रियों, सचिवों और अधिकारियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने के लिये लोकायुक्त सचिवालय एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना विधायिका द्वारा कानून बनाकर की गई है।

लोकायुक्त संस्था सुधार हेतु गठित समितियाँ:-

- (1) 1997 हरिशंकर भाभड़ा समिति
- (2) 2000 बी.डी. कल्ला समिति
- (3) 2014 नरपतमल लोढ़ा समिति

- धारा-13 मिथ्या (झूठी) शिकायत के लिए अभियोजन-झूठी शिकायत पर 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

	नाम	कार्यकाल
1.	न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28-08-1973 - 27-08-1978
2.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक) पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राज. उच्च न्यायालय	28-08-1978 - 05-08-1979
3.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जोशी पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06-08-1979 - 07-08-1982
4.	न्यायमूर्ति श्री के.एस. सिद्धू (कार्यवाहक) न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04-04-1984 - 03-01-1985
5.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. श्रीमाल पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	04-01-1985 - 03-01-1990
6.	न्यायमूर्ति श्री पी.डी. कुदाल पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16-01-1990 - 06-03-1990
7.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा न्यायाधीश, राज. उच्च न्यायालय	10-08-1990 - 30-09-1993
8.	न्यायमूर्ति श्री वी.एस. दवे (कार्यवाहक) (न्यूनतम कार्यकाल) न्यायाधीश, राज. उच्च न्यायालय	21-01-1994 - 16-02-1994
9.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा पूर्व न्यायाधीश, राज. उच्च न्यायालय	06-07-1994 - 06-07-1999
10.	न्यायमूर्ति श्री मिलापचन्द जैन पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26-11-1999 - 26-11-2004
11.	न्यायमूर्ति श्री जी.एल. गुप्ता पूर्व न्यायाधीश, राज. उच्च न्यायालय	01-05-2007 - 30-04-2012
12.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी (सबसे लम्बा कार्यकाल) पूर्व न्यायाधीश, राज. उच्च न्यायालय	25-03-2013 - 07-03-2019
13.	न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा पूर्व न्यायाधीश, राज. उच्च न्यायालय	09-03-2021 -08-03-2026
	वर्तमान में पद रिक्त	

- **उपलोकायुक्त**- के.पी.यू. मेनन-05-06-1973 से 25-06-1974
- सज्जनसिंह कोठारी एकमात्र ऐसे लोकायुक्त जिनका कार्यकाल अध्यादेश द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया लेकिन इन्हें 2019 में पद से हटाकर लोकायुक्त का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया।
- एम.बी. शर्मा एकमात्र व्यक्ति जो दो बार लोकायुक्त बने।
- डी.वी. गुप्ता, मिलापचंद जैन राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे।

राज्य सूचना आयोग (State Information Commission)

- सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यंत प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। जिसे “सूचना अधिकार अधिनियम” द्वारा विधिक रूप देकर प्रभ. ावी बनाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा-15 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग एक सांविधिक निकाय है, जो पूर्णतया स्वायत्तशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- **गठन:-** राजपत्र में 13 अप्रैल, 2006 को अधिसूचित लेकिन प्रभावी 18 अप्रैल, 2006 से
- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 में बना।
- **मुख्यालय** - जयपुर

संरचना (धारा 15)

- बहुसदस्यीय निकाय है, इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- इसके अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये। (धारा 15)
- उनको संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिये। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी लाभ के पद पर नहीं हों।
- **नियुक्ति (धारा 15)-** राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, जो एक समिति की सिफारिश पर करेंगे। इस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। इस समिति के अन्य सदस्य- विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होंगे।

- **पदावधि (धारा 16)**- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- 2019 में संशोधन से पूर्व 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु थी जो अब 3 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो, की गई है।
- **शपथ ग्रहण**- राज्यपाल या उनके द्वारा इस हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण की जाएगी। (धारा 16)
- **त्यागपत्र (धारा 16)**- राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा।
- **वेतन (धारा 16)** - राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगी।
- **पद से हटाया जाना (धारा 17)**- मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकेगा।

राज्यपाल निम्न आधारों पर भी हटा सकता है।

1. यदि उन्हें दिवालिया घोषित किया जाए,
2. कार्यकाल के दौरान कहीं सवैतनिक नौकरी में संलग्न होने पर
3. यदि वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए जिससे उसके पदीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
4. यदि राज्यपाल की दृष्टि में वह मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है।
5. वार्षिक रिपोर्ट (धारा 25) राज्य सरकार को सौंपते हैं। राज्य सरकार इसे विधानसभा के समक्ष रखती है।

राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ (धारा 18, 19, 20 एवं 25 में) :-

राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

- **परिवाद संबंधी- आयोग के समक्ष नागरिक निम्न बिंदुओं पर परिवाद दायर कर सकता है। ये हैं-**
 1. जन-सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो।
 2. यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी फीस सही नहीं है। उसके द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न हो पायी हो।
 3. यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गयी सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है, तथा उसे जानकारी देने से मना कर दिया गया हो।
 4. सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला।
- **परिवाद की जांच करते समय आयोग को परिवाद की दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और राजस्थान सूचना आयोग सुनवाई के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है-**
 1. वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने का दबाव डालने के लिये सम्मन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।
 2. किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना।
 3. एफिडेविट (शपथ पत्र) के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना।
 4. किसी दस्तावेज की मांग एवं उसकी जांच करना।
 5. किसी गवाह या दस्तावेज को प्रस्तुत करने या होने के लिये सम्मन जारी करना, तथा कोई अन्य मामला जिस पर विचार करना आवश्यक हो।
 6. जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
 7. यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है।
 8. अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना (अधिनियम की धारा 9(8))
- **अपीलीय शक्तियाँ :-** प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा दिए गये निर्णय (धारा 19(1) के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकारी (धारा 19(3) के अंतर्गत अपीलीय शक्तियाँ हैं जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग में निहित हैं।
- प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील 90 दिवस के अंदर की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताए विलम्ब के कारणों से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज की जा सकती है। धारा 19(7) के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।
- **शास्ति अधिरोपण की शक्तियाँ -** परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिए निर्णय के अंतर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयुक्त की यह धारणा बनती है कि लोकसूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण के -
 1. सूचना के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया हो।
 2. सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध न करवाई हो।
 3. जानबूझकर अशुद्ध/भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई हो।
 4. सूचना के आवेदन की विषयवस्तु को नष्ट कर दिया हो।

5. सूचना उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार का अवरो पैदा किया गया है तो वह आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तब 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जो अधिकतम 25000 रुपये हो शास्ति अधिरोपित कर सकता है। यद्यपि शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व आयोग लोकसूचना अधिकारी को सुनवाई का यु.ि. क्तयुक्त अवसर प्रदान करेगा।

- अधिनियम की धारा 25 (1) के अंतर्गत आयोग को अधि नियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार है। सूचना आयोग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है जिसे राज्य सरकार विधानसभा में रखती है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न सूचनाएं होती हैं।

- (1) प्राप्त आवेदन
- (2) निरस्त आवेदन
- (3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम
- (4) एकत्र शुल्क
- (5) अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयत्न
- (6) सुधार के लिए सुझाव ।

राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त:-

1.	एम.डी.कोरानी	18 अप्रैल, 2006 से 17 अप्रैल, 2011 तक (सर्वाधिक लंबा कार्यकाल)
2.	टी.श्रीनिवासन	5 सितम्बर, 2011 से 13 अगस्त, 2015 तक
3.	सुरेश कुमार चौधरी	06 नवम्बर, 2015 से 25 दिसम्बर, 2018 तक
4.	डी.बी.गुप्ता	11 दिस. 2020 से 10 दिसं., 2023 (न्यूनतम कार्यकाल)
5.	एम. एल. लाठर	9 जुलाई, 2024 से वर्तमान तक

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पूर्व सदस्य :-

- (1) टी. श्रीनिवासन (न्यूनतम कार्यकाल)
- (2) पी. एल. अग्रवाल
- (3) चद्रमोहन मीणा
- (4) आशुतोष शर्मा (सर्वाधिक कार्यकाल)
- (5) नारायण बारेठ
- (6) शीतल धनकड़ (प्रथम महिला सदस्य)
- (7) राजेन्द्र प्रसाद बरवार
- (8) लक्ष्मण सिंह राठौड़
- (9) मोहनलाल लाठर
- (10) महेन्द्र कुमार पारख
- (11) सुरेश चद्र गुप्ता

(12) टीकाराम शर्मा

- टी. श्रीनिवासन तथा मोहनलाल लाठर मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त दोनों पदों पर रहे।
- डी.बी. गुप्ता राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर भी रहे।
- मोहनलाल लाठर राजस्थान के पूर्व महानिदेशक पुलिस (DGP) रह चुके हैं।

राजस्थान राज्य महिला आयोग

- यह एक गैर-संवैधानिक/ सांविधिक निकाय है। जो जांच तो कर सकता है लेकिन किसी को सजा नहीं दे सकता है, अर्थात् यह एक परामर्शकारी संस्था है। यह अधिनियम राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार गठित ।
- गठन : अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 15 मई 1999 को किया गया। जिसका मुख्यालय जयपुर में बनाया गया है।

धारा 3 - राज्य महिला आयोग की संरचना :

- इसमें 1 अध्यक्ष और सदस्य, सचिव सहित चार से अनधिक सदस्य होंगे और चार सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ा जाति की महिला होगी।
- अध्यक्ष महिलाओं की समस्याओं को निपटाने का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाली, महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध विख्यात महिला होगी। अध्यक्ष और सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम आयु सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है।

2007 में हुए संशोधन के बाद जुड़े प्रावधान :

1. आयोग की साधारण बैठक दो मास में कम से कम एक बार आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियत दिन और समय पर आयोजित की जायेगी।
 2. सदस्य सचिव साधारण बैठक के नोटिस और कार्यसूची को ऐसी रीति से परिचालित करेगा जिससे वह बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यों को प्राप्त हो जाये, परन्तु अध्यक्ष स्वयं या कम से कम तीन सदस्यों द्वारा उसको किये गये लिखित अनुरोध पर आसन्न प्रकृति के किसी विशेष मुद्दे पर विचार करने के लिए आयोग की विशेष बैठक बुला सकेगा।
- A- किसी अनुरोध के प्राप्त होने पर अध्यक्ष, सदस्य सचिव के परामर्श से, विशेष बैठक के लिए तारीख और समय नियत करेगी। ऐसी तारीख अनुरोध के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के पश्चात् की नहीं होगी।
- B- जैसे ही विशेष बैठक की तारीख और समय विनिश्चित किया जाता है, विशेष बैठक का नोटिस और उसकी कार्यसूची ऐसी बैठक के लिए नियत समय से कम से

- कम चौबीस घण्टे पूर्व समस्त सदस्यों को भेजा जाएगा।
- C- आयोग की समस्त बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और यदि अध्यक्ष आयोग की किसी बैठक में उपस्थित होने में समर्थ नहो तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य का ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चयन करेंगे। परंतु -
- D- आयोग की प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए तीन होगी।
- E- समस्त प्रश्न उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतों के समान होने की दशा में अध्यक्ष यथास्थिति अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा।

धारा 4 सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें:

- धारा 3 के उपबंधों के अध्यक्ष रहते हुए अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे।
- वेतन एवं सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगे।
- **धारा 5 गणपूर्ति :** आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित तीन होगी।
- **धारा 6 काम काज का निपटारा :** आयोग की बैठकों की व्यवस्था आयोग के अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उस प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- आयोग की बैठकों में निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे एवं बराबर की स्थिति में निर्णायक मत अध्यक्ष को होगा।
- **धारा 7 किसी कमी या रिक्ति इत्यादि के कारण आयोग का आदेश अविधिमान्य नहीं होगा।**
- **धारा 8 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाना :** राज्य सरकार के किसी आदेश से हटाया जा सकता है यदि -
 - दिवालिया घोषित हो जाए
 - किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो।
 - विकृतचित्त हो जाने पर
 - कार्य करने में असमर्थ हो।
 - बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रही हो
 - पद का दुरुपयोग किया गया हो और उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो।
- परन्तु कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस विषय की सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर नहीं दे दिया गया हो।
- **धारा 9 : आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी :** राज्य सरकार आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।
- **धारा 10 :** हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश कराने

की आयोग की शक्तियाँ: आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अर्थात्

- (अ) किसी भी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और उसकी परीक्षा करना।
- (ब) किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना।
- (स) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना।
- (द) किसी भी लोक कार्यालय से किसी भी लोक दस्तावेज या उसकीप्रति की अपेक्षा करना।
- (ध) गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आयोग द्वारा समन आदेश जारी करना।

धारा 11 आयोग के कार्य:

- (1) किसी भी अनुचित व्यवहार की जाँच करना उस पर विनिश्चयकरना और उस मामले में की जाने वाली कार्रवाईयों की सरकारको सिफारिश करना। (राज्य सरकार तीन माह में इसकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है बताती है।)
- (2) महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विवादों को या अनुचित व्यवहारों से संबंधित विवादों को /का अन्वेषण करना या अन्वेषण करवाना और उनके बारे में किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सरकार को रिपोर्ट करना।
- (3) निम्नलिखित के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट या रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
 - (a) प्रवृत्त विधियों में की ऐसी कमियाँ अपर्याप्तताएं या खामियाँ जो महिलाओं के समता के संवैधानिक अधिकार और उनके प्रति उचित व्यवहार को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपचारी विधायी उपाय।
 - (b) महिलाओं के संबंध में प्रवृत्त विधियों के कार्यकरण को इस दृष्टि से मोनीटर करना ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें विधियों का प्रवर्तन पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है या दोष रहित नहीं किया जा रहा है और उनमें सुधार लाने के लिए किये जाने वाले कार्यपालक या विधायी उपायों की सिफारिश करना।
 - (c) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में की गयी भर्तियों को मोनीटर करना और ऐसी भर्तियों के मामले में महिलाओं को समान अवसर देने हेतु अपेक्षित कार्यवाही यदि कोई होए करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करने की दृष्टि से ऐसी भर्तियों को शासित करनेवाले नियमों और विनियमों की संवीक्षा करना।
- (4) किसी भी कारागार, पुलिस थाने, हवालातों, उप-जेलों, उद्धार गृहों या अभिरक्षा के ऐसे अन्य स्थानों जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है या राज्य सरकार या उसके किन्हीं भी अभिकरणों जिनमें महिलाओं के उद्धार

या आश्रय के प्रयोजन के लिए सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरण सम्मिलित हैं द्वारा चालित महिलाओं के आश्रय स्थल या अन्य इसी प्रकार के स्थानों या किसी भी व्यक्ति द्वारा चालित महिलाओं या लड़कियों के लिए आश्रित होस्टलों का और सभी ऐसे अन्य स्थानों का जिनमें महिलाओं के विरुद्ध किये गये अनुचित व्यवहार का परिवाद किया जाता है निरीक्षण करना या करवाना और ऐसे स्थानों में महिलाओं और लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसके बारे में और जाँच करवाना और उपचारी कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिपोर्ट करना।

धारा 12 अनुचित व्यवहार की जांच करना:

- (1) किसी भी महिला से यह अभिकथित करते हुए कि उसके साथकोई अनुचित व्यवहार किया गया है कोई लिखित परिवाद याकिसी भी रजिस्ट्रीकृत महिला संगठन से वैसा ही परिवाद प्राप्त होने पर।
- (2) अपनी स्वयं की जानकारी या सूचना पर।
- (3) सरकार से किसी भी निवेदन पर।
- (4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अनुचित व्यवहार की व्यक्तिगत जानकारी हो, किये गये परिवाद पर। किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच कर सकेगा।

धारा 13 अभियोजना का प्रारंभ:

- यदि धारा 12 के अधीन किसी परिवाद के अन्वेषण के पश्चात् आयोग को यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई दाण्डिक अपराध किया है तो वह इस आशय का आदेश पारित करसकेगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा यदि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो और यदि ऐसे अभियोजन के लिए किसी प्राधिकारीगण की पूर्व मंजूरी अपेक्षित हो तो उस प्राधिकारी से ऐसी मंजूरी प्राप्त की जायेगी ।

धारा 14 आयोग की वार्षिक और विशेष

- (1) आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (2) राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को आयोग की सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों यदि कोई हों के ज्ञापन सहित राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी ।

धारा 15 आयोग की बैठकें:

- (1) आयोग की बैठकों का स्थान जयपुर होगाकिन्तु वह किन्हीं अनुचित व्यवहारों की जांच के प्रयोजन हेतु बैठकें राज्य केभीतर किसी भी स्थान पर आयोजित कर सकेगा ।
- (2) आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपनी प्रक्रिया कोविनियमित करने और अपने कामकाज के निपटारे के

लिए विनियम बनायेगा और विनियमों को उनके बनाये जाने के पश्चात् राज-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

- **धारा 16** राज्य सरकार का आयोग से परामर्श किया जाना: राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय-समय पर परामर्श करेगी।
- **धारा 17** आयोग के सदस्यों अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना: आयोग के सभी सदस्य अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तत्परित हों लोक सेवक समझे जायेंगे।
- **धारा 18** राज्य सरकार द्वारा अनुदान- राज्य सरकार विधान-मण्डल द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।
- **धारा 19** आयोग को दान अभिदाय आदि
- **धारा 20** लेखे और संपरीक्षा
- **धारा 21** कतिपय मामलों में अधिनियम का लागू न होना. यह अधिनियम-
 - (1) केन्द्र सरकार या
 - (2) केन्द्र सरकार के किसी भी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केन्द्र सरकार के प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित या वित्त-पोषित किसी अन्य संस्था परलागू नहीं होगा ।
- **धारा 22 नियम बनाने की शक्ति** - राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्षों की सूची

अध्यक्ष का नाम		कार्यकाल
1.	कांता कथुरिया	25 मई 1999 से 24 मई 2002
2.	पवन सुराणा	28 जनवरी 2003 से 27 जनवरी 2006
3.	तारा भण्डारी	15 अप्रैल 2006 से 14 अप्रैल 2009
4.	मीरा महर्षि (कार्यवाहक अध्यक्ष)	17 अक्टूबर 2009 से 18 अगस्त 2010
5.	सरिता सिंह (कार्यवाहक अध्यक्ष)	24 मार्च 2011 से 23 नवंबर 2011
6.	लाडकुमारी जैन	24 नवंबर 2011 से 23 नवंबर 2014
7.	सुमन शर्मा	20 अक्टूबर 2015 से 19 अक्टूबर 2018
9.	रेहाना रियाज चिश्ती	11 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2025
वर्तमान में पद रिक्त		

राजस्व मण्डल (Revenue Board)

- राजस्व मंडल राज्य सरकार के राजस्व विभाग का शीर्षस्थ नियामक, नियंत्रण तथा अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है। यह संस्था भू-अभिलेख, राजस्व वादों, अपीलों और संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए राजस्थान के भू-राजस्व प्रशासन का एक प्रमुख स्तंभ है।
- राजस्थान की अलग-अलग रियासतों में भू-राजस्व निकायों की एकीकृत व्यवस्था की कमी को दूर करने के लिए 07 अप्रैल 1949 को राजप्रमुख द्वारा राजस्व मंडल की स्थापना की घोषणा की गई, जो 1 नवंबर 1949 से प्रभावी हुई। बाद में पुनर्गठन राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत हुआ।
- इस मंडल में एक अध्यक्ष एवं कम से कम 3 एवं अधिक से अधिक 20 सदस्य (संशोधित) अन्य सदस्य होंगे।
- भूराजस्व मण्डल का प्रथम अध्यक्ष श्री ब्रजचन्द्र शर्मा को बनाया गया। जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजिताभ शर्मा हैं।
- बोर्ड के समस्त सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है एवं आवश्यकतानुसार सर्किट बेंचें भी स्थापित की जा सकती हैं। जयपुर में सर्किट बेंच कार्यरत है।
- राजस्व मंडल को राजस्थान राज्य का उच्चतम राजस्व न्यायालय घोषित करता है। मंडल को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अपील निगरानी एवं निर्देश की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राजस्व बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य:-

1. राजस्व के मामलों में अपील एवं निर्णय पर अंतिम सुनवाई करना (राज्य का उच्चतम राजस्व न्यायालय)।
2. राजस्व संबंधी मामलों पर सलाह देना।
3. बोर्ड की क्रियाविधि निर्धारित करना।
4. राजस्व मामलों पर न्यायालय का विचार लेने की शक्ति।
5. राजस्व दर को निर्धारित करने एवं वसूलने का कार्य।
6. अपने अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकारियों की नियुक्ति करना।
7. अन्य कार्य व शक्तियाँ जो राज्य द्वारा निर्धारित किये गये हों।
8. राजस्व मंडल अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग, पदोन्नति इत्यादि का निर्णय करना।

इस अधिनियम की धारा 17 से 22 तक निम्नलिखित राजस्व अधिकारियों एवं न्यायालयों का उल्लेख किया गया है-

1. आयुक्त
2. उपआयुक्त
3. सहआयुक्त
4. बंदोबस्त आयुक्त
5. भू अभिलेख निर्देशक
6. अपर भू अभिलेख निर्देशक
7. तहसीलदार
8. नायब तहसीलदार
9. राजस्व अपीलीय प्राधिकरण
10. राजस्व बोर्ड

राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

- संविधान के अनुच्छेद 243I (243I) में राज्य के लिये वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिये वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है, लेकिन आयोग की संरचना आदि के संबंध में राज्य विधानमंडलों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। राज्य वित्त आयोग से जुड़े अधिकांश प्रावधान अपनी प्रकृति में वैसे ही हैं, जैसे- अनुच्छेद 280 व 281 में भारत के वित्त आयोग से जुड़े प्रावधान हैं।

राज्य वित्त आयोग	अध्यक्ष	गठन	कार्यकाल
पहला	कृष्ण कुमार गोयल	24 अप्रैल, 1994	1 अप्रैल 1995 - 31 मार्च, 2000
दूसरा	हीरालाल देवपुरा	7 मई, 1999	1 अप्रैल, 2000 - 31 मार्च, 2005
तीसरा	माणिकचन्द सुराणा	मई, 2004	1 अप्रैल, 2005 - 31 मार्च, 2010
चौथा	डॉ. बी.डी.कल्ला	13 अप्रैल, 2011	1 अप्रैल, 2010 - 31 मार्च, 2015
पांचवा	डॉ. ज्योति किरण	जुलाई, 2014	1 अप्रैल, 2015 - 31 मार्च, 2020
छठा	प्रद्युम्न सिंह	12 अप्रैल, 2021	1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2025
सातवाँ	अरूण चतुर्वेदी	नियुक्ति अगस्त, 2025	(कार्यकाल 1½ वर्ष रहेगा)

राज्य वित्त आयोग से जुड़े प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं-

- कर राजस्व का जो हिस्सा पंचायतों को दिया जाना है, वह विभिन्न पंचायतों के मध्य किस प्रकार से बाँटा जाना चाहिये।
- आयोग के पास अधिकार होगा कि वह अपनी सभी कार्य-प्रक्रिया स्वयं निर्धारण कर सके।
- राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगा कि वित्त आयोग की संरचना क्या होगी, इसके सदस्यों की योग्यताएँ क्या होंगी व उनका चयन किस प्रकार से किया जाएगा, आयोग को अपने कृत्यों के पालन हेतु कौन सी शक्तियाँ दी जाएंगी आदि।
- आयोग का मूल कार्य यह होगा कि वह राज्य की पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे तथा निम्नलिखित मामलों में राज्यपाल को उपयुक्त सिफारिशें दे-
 - वे कौन से कर, फीस या शुल्क हो सकते हैं, जिनके अधिरोपण के लिये पंचायतों को अधिकृत किया जा सके या उनकी प्राप्तियाँ पंचायतों को सौंपी जा सकें।
 - प्रत्येक राज्य का राज्यपाल '73वें संविधान संशोधन, 1992' के आरंभ के एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा।
 - राज्य के कर राजस्व के शुद्ध आगमों को राज्य तथा पंचायतों के मध्य किस प्रकार से बाँटा जाना चाहिये।
 - वे सभी जरूरी उपाय जिनकी मदद से पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारी जा सकती है।
 - यदि राज्यपाल ने पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में वित्त आयोग को कोई विषय निर्दिष्ट किया हो तो उसके संबंध में भी आयोग अपनी सिफारिश देगा।
 - कौन-से नियमों के अनुसार राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिये।

राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission)

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय-5 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है।
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग सांविधिक/वैधानिक निकाय है।
- **राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन:-** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा-21 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 18 जनवरी, 1999 को किया गया। जिसमें 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गये। जिसने कार्य 23 मार्च, 2000 से शुरू किया। इसका मुख्यालय जयपुर में है।
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार विनियम 2001 का क्रियान्वयन 19

जनवरी, 2001 को हुआ। राज्य मानवाधिकार संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया।

- मानवाधिकारों का दायरा बहुत ही व्यापक है। इसमें उन अधिकारों को शामिल किया जाता है, जो मनुष्य होने के नाते मनुष्य को प्राप्त हैं। अर्थात् मनुष्य को स्वतंत्र, समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार मिलने चाहिए, वे मानवाधिकारों के अंतर्गत आते हैं।

क्षेत्राधिकार -

- राज्य मानवाधिकार आयोग का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान है। मानवाधिकारों के अतिरिक्त इसके क्षेत्राधिकार में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक अधिकार आते हैं।
- आयोग भारतीय संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले मानवाधिकार मामलों की जाँच कर सकता है। लेकिन किसी मामले की जाँच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहले से ही कर रहा है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग इन मामलों की जाँच नहीं कर सकता।

आयोग की संरचना

- बहुसदस्यीय निकाय है (धारा 21), वर्तमान में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं।
- वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री गंगाराम मूलचन्दानी तथा सदस्य रामचंद्र सिंह झाला व अशोक कुमार गुप्ता हैं।
- **आयोग का अध्यक्ष-** उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में हुए 2019 के संशोधन उपरांत)
- **सदस्य -** उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। इनमें से एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए।

नियुक्ति समिति -

- राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :-
 - अध्यक्ष - राज्य का मुख्यमंत्री
 - सदस्य - विधानसभा अध्यक्ष
 - सदस्य - राज्य का गृहमंत्री
 - सदस्य - विधानसभा में विपक्ष का नेता
- (विधानपरिषद् होने की स्थिति में विधान परिषद् का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे।)
- **शपथ** - राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति
- **त्यागपत्र** - (धारा 23) - राज्यपाल को।
- **हटाने की प्रक्रिया** (धारा 23) - सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति द्वारा (राज्यपाल द्वारा नहीं)

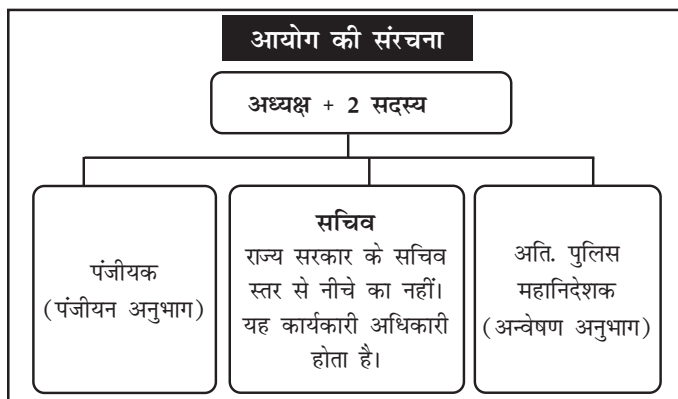
- राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटा सकता है :-
 - अगर वह दिवालिया हो जाता है।
 - अपने कार्य अवधि में ही अपने लाभ का कोई सरकारी पद ग्रहण कर लिया हो।
 - वह शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो।
 - वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो तथा इस दृष्टि से न्यायालय ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया हो।
 - वह किसी अपराध में दोषी हो तथा कारावास की सजा पायी हो।
 - कदाचार या अक्षमता के आधार पर (उच्चतम न्यायालय के परामर्श पर ही)

कार्यकाल

- 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। यह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र है। (2019 के संशोधन के बाद)
- अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे (2019 के संशोधन के बाद)
- आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार और केन्द्र सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते।

राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Right Commission)

- धारा-21 - राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन।
- धारा-22-राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति।
- धारा-23 - राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना।
- धारा-24- राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।
- धारा-25- कार्यवाहक अध्यक्ष
- धारा 26 - सेवा शर्तें, वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है लेकिन कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान तथा सदस्यों का वेतन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान वेतन मिलता है।
- धारा 27- राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी



- धारा 28 - राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट
- रिपोर्ट (प्रतिवेदन) धारा 28(1)-वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को
- धारा 28(2)-राज्य सरकार रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाएगी।
- धारा 29 - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ प्रावधानों को राज्य आयोग पर लागू करना।
- धारा 33 - राज्य आयोग की वित्तीय स्वायत्तता।

आयोग के कार्य

- स्वप्रेरणा या स्वयं पीड़ित या उसकी और किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर (राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों पर)
- यदि किसी लोकसेवक द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना की अवहेलना की जाती है तो स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से उसकी जाँच करना।
- ऐसे मामले जो मानवाधिकार से सम्बन्धित हैं और न्यायालय में लंबित हैं, न्यायालय की अनुमति से कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
- जेलों का निरीक्षण और मानवाधिकार सम्बन्धी मामलों की सिफारिश करना।
- विधिक और संवैधानिक उपबंध जो मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए हैं, की समीक्षा करके आवश्यक सिफारिशें करना।
- मानव अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना तथा लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना।
- आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना।
- मानवाधिकार उल्लंघन के कारणों की समीक्षा और बचाव हेतु उपायों की अनुशंसा करना।
- मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- मानवाधिकार से सम्बन्धित क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना।

नोट - अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन करता है, तो इसमें मानवाधिकार आयोग किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता। आयोग निजी व्यक्ति के मामले में तभी कार्यवाही कर सकता है, जब मानवाधिकारों के उल्लंघन में लोक सेवक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:-

- परिवादों को किसी भी माध्यम जैसे स्वयं उपस्थित होकर, पत्र/फैक्स/मेल आदि से प्रेषित किया जा सकता है। समाचार पत्रों में छपी खबरों पर भी आयोग संज्ञान ले सकता है। परिवाद हिंदी अंग्रेजी या संविधान की 8 वीं अनुसूची में वर्णित विषयों में से किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवाद के साथ कोई फीस देय नहीं।

ग्रहण न किए जाने वाले परिवाद

- अस्पष्ट/अनाम/अपठनीय किसी को परेशान करने वाले हों।
- 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले।
- सिविल विवाद/औद्योगिक विवाद/अन्य प्रयोग के समक्ष मामला लंबित हो।
- मानवाधिकारों के अतिक्रमण का मामला न हो।
- मामला किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो।
- मामला आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हो।

आयोग की कार्यप्रणाली :

- आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयोग केवल उन्ही मामलों की सुनवाई कर सकता है जो एक वर्ष से अधिक पुराने न हों। मानवाधिकारों के हनन की शिकायत मिलने पर या स्वप्रेरणा से आयोग निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है।
- यह पीड़ित व्यक्ति को नुकसान के भुगतान के लिए सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण को शिकायत कर सकता है।
- यह सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण की पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है।
- आयोग लोक सेवक के खिलाफ बंदीकरण की कार्यवाही करने के लिए सम्बंधित सरकार या एजेन्सी को सिफारिश कर सकता है।
- पीड़ित की तत्काल सहायता हेतु सम्बंधित सरकार या एजेन्सी को सिफारिश कर सकता है।

आयोग का स्वरूप

- राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य परामर्शीय प्रकृति का है।
- आयोग स्वयं मानवाधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। आयोग स्वयं अपनी ओर से पीड़ित को किसी प्रकार की कोई सहायता या मुआवजा राशि नहीं दे सकता।
- सरकार आयोग की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होती। परन्तु आयोग की सलाह के बारे में सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की इसका विवरण 1 माह के भीतर देना अनिवार्य है। आयोग राज्य सरकार के समक्ष वार्षिक रूप से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
- **राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ:-** शिकायतों की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। जो निम्न हैं -
 1. साक्षियों को सम्मन कर हाजिर कराना तथा शपथ पत्र पर उनकी परीक्षा करना।
 2. दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना
 3. शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना
 4. किसी न्यायालय का कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।
 5. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा लिए कमीशन निकालना
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा त्रैमासिक पत्रिका "मानवाधिकार संदेश" निकाली जाती है।

मानवाधिकार न्यायालय

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) के तहत प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान है। इसकी स्थापना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार मानवाधिकार न्यायालय में एक विशेष अभियोजक की नियुक्ति करती है।

	अध्यक्ष	कार्यकाल
1.	जस्टिस कांता भटनागर (प्रथम महिला अध्यक्ष) (न्यूनतम कार्यकाल)	23 मार्च, 2000 से 11 अगस्त, 2000
2.	जस्टिस सैयद सगीर अहमद (प्रथम अल्पसंख्यक)	16 फरवरी, 2001 से 3 जून, 2004
3.	जस्टिस नगेन्द्र कुमार जैन (सर्वाधिक कार्यकाल)	16 जुलाई, 2005 से 15 जुलाई, 2010
4.	जस्टिस प्रकाश टाटिया	11 मार्च, 2016 से 25 नवम्बर, 2019
5.	जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास	25 जनवरी, 2021 से 24 जनवरी, 2024
6.	गंगाराम मूलचंदानी	28 जून 2024 से निरंतर

अब तक राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष (06) रहे- (1) अमरसिंह गोदारा (प्रथम)

- (2) जगतसिंह
- (3) पुखराज सिंघवी
- (4) एच.आर. कुडी
- (5) महेशचंद्र शर्मा
- (6) रामचंद्रसिंह झाला

महत्वपूर्ण तथ्य

- **सगीर अहमद:-** ऐसे अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे तथा जम्मू-कश्मीर व आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे।
- **नगेन्द्र कुमार जैन:-** राज्य मानवाधिकार आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष रहे। ये पूर्व में राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष, हिमाचल के लोकायुक्त, हिमाचल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे।
- **प्रकाश टाटिया:-** दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जबकि राजस्थान व झारखण्ड उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे।
- **गोपालकृष्ण व्यास:-** दूसरे अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। गोपालकृष्ण व्यास राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे।
- वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं।

राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य

क्र.	नाम	कार्यकाल
1.	प्रो० आलमशाह खान (पद पर रहते निधन)	24 मार्च 2000-16 मई 2003
2.	बी.एल. जोशी	25 मार्च 2000-31 मार्च 2004
3.	आर. के. आकोदिया	25 मार्च 2000-24 मार्च 2005
4.	अमर सिंह गोदारा	7 जुलाई 2000-06 जुलाई 2005
5.	नमोनारायण मीणा (न्यूनतम कार्यकाल)	11 सितम्बर 2003-23 मार्च 2004
6.	धर्मसिंह मीणा	7 जुलाई 2005-6 जुलाई 2010
7.	जगतसिंह	10 अक्टूबर 2005-9 अक्टूबर 2010
8.	पुखराज सीरवी (सर्वाधिक कार्यकाल)	
9.	एच. आर. कुडी	1 सितंबर 2011-31 अगस्त 2016
10.	एम.के. देवराजन	1 सितंबर 2011-31 अगस्त 2016
11.	महेशचंद्र शर्मा (पद पर रहते निधन)	3 अक्टूबर 2018-29 अप्रैल 2021
12.	महेश गोयल	3 अक्टूबर 2018-29 अप्रैल 2021
13.	रामचंद्रसिंह झाला	16 जनवरी 2023-वर्तमान तक
14.	अशोक कुमार गुप्ता	28 जून 2024 से वर्तमान तक

- **बी.एल. जोशी**- उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश व मेघालय के भी राज्यपाल रहे।



राजस्थान की विभिन्न आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष मॉडल पेपर

Maximum Marks- 200

Number of Question- 100 Time- 2 Hourrs

- “सिवाय हरी घास के मेरी कब्र को किसी चीज से न ढका जाए, क्योंकि केवल घास ही दीन की कब्र ढकने के लिए काफी हैं।” यह मर्मस्पर्शी लेख किसकी कब्र पर खुदा हुआ है-
 - दारा शिकोह की कब्र
 - जहाँआरा की कब्र
 - मुमताज महल की कब्र
 - नूरजहाँ की कब्र
 - अनुत्तरित प्रश्न
- निम्नलिखित कृतियों में से कौनसी कृतियों से राजा राम मोहन का संबंध था-
 - प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एण्ड हैप्पीनेस
 - अपील्स टू द क्रिश्चियन पब्लिक
 - संवाद कौमुदी
 कूट:
 - 1 और 2 सही है मगर 3 गलत है।
 - 1 और 3 सही है मगर 2 गलत है।
 - 2 और 3 सही है मगर 1 गलत है।
 - 1, 2 और 3 सही है।
 - अनुत्तरित प्रश्न
- देवबंद आन्दोलन के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है-
 - ये अलीगढ़ आन्दोलन के प्रबल समर्थक थे।
 - यह स्कूल परंपरागत इस्लाम में विश्वास रखता था।
 - इस आन्दोलन ने 1885 ई. में कांग्रेस के निर्माण का विरोध किया था।
 - यह आन्दोलन मुहम्मद कासिम सियाशेख तथा रसीद अहमद सिराज द्वारा शुरू किया गया था।
 - अनुत्तरित प्रश्न
- नक्शबंदी सिलसिले की भारत में (उच्छ में) स्थापना किसने की थी-

(a) बहाउद्दीन नक्शबंदी	(b) मीर मासूम
(c) बाकी बिल्लाह	(d) अहमद सरहिन्दी
(e) अनुत्तरित प्रश्न	
- निम्नलिखित में से किस वंश या साम्राज्य के शासनकाल में नटराज की मूर्ति अपने स्थापत्य में चरम पर पहुँची थी-

(a) चोल साम्राज्य	(b) चेर साम्राज्य
(c) पांड्या साम्राज्य	(d) चालुक्य साम्राज्य
(e) अनुत्तरित प्रश्न	
- राजस्थान में 1857 की घटनाओं के सन्दर्भ में सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
 - महाराजा बन्नेसिंह ने अंग्रेजों की सहायतार्थ आगरा सेना भेजी थी।
 - बांसवाड़ा के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सहयोग किया था।
 - बीकानेर महाराज सरदारसिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने बीकानेर को टी.बी. परगने के 41 गांव दिए थे।
 कूट:

(a) केवल 1 और 2	(b) केवल 2
(c) केवल 3	(d) 1, 2 और 3
(e) अनुत्तरित प्रश्न	
- सूची-I (गीत) को सूची-II (रचनाकार) से सुमेलित कीजिए और सत्य कूट की पहचान कीजिए-

सूची-I (गीत)	सूची-II (रचनाकार)
A. डंके री चोट	1. जयनारायण व्यास
B. काला बादल	2. भैरवलाल
C. खूनियां रौ राज	3. अर्जुनलाल सेठी
D. सपनो आयो	4. हीरालाल शास्त्री

 कूट:-

A	B	C	D
(a) 3	2	1	4
(b) 1	2	4	3
(c) 1	2	3	4
(d) 3	2	4	1
(e) अनुत्तरित प्रश्न			
- सारनाथ के अशोक चिह्न के गोलाकार आधार पर कौन-कौनसे पर चार मुख्य पशुओं को अंकित किया गया है:

1. साँड़	2. घोड़ा
3. हाथी	4. शेर

 कूट:

(a) केवल 1 और 4	(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 4	(d) 1, 2, 3 और 4
(e) अनुत्तरित प्रश्न	
- महाराणा कुंभा व उसके शासनकाल के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
 - कुम्भा ने वर्ष 1455 में मारवाड़ से मण्डोर छीन लिया था।
 - चित्तौड़ में कुंभस्वामी तथा श्रृंगारचवरी का मंदिर निर्माण कुम्भा ने करवाया था।
 - कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त किया था।

4. मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कतुबुद्दीन ने कुम्भा के खिलाफ चम्पानेर की संधि की थी।
कूट:
कूट:
(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
(e) अनुत्तरित प्रश्न
10. निम्नलिखित में से कौनसे आभूषण महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाते हैं-
(a) नथ, बेसर, छड़ा, भोगली, कांटा, चूनी, चोप, भँवरकड़ी
(b) टोटी, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चोप, भँवरकड़ी
(c) नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चोप, भँवरकड़ी
(d) नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, नेवरी, चोप, भँवरकड़ी
(e) अनुत्तरित प्रश्न
11. निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
1. अंजना देवी चौधरी रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थीं।
2. रतन शास्त्री ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की थी।
3. जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामण्डल के 1943 ई के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गईं।
कूट:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
(e) अनुत्तरित प्रश्न
12. “सर्वगी सम्प्रदाय” के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
1. इस सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र सांगलिया धूणी है।
2. इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का मुख्य अभिवादन ‘जय साहेब’ है।
3. इस सम्प्रदाय की स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1659 ई. में की गई थी।
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
(e) अनुत्तरित प्रश्न
13. चारबैंत के सन्दर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए-
1. चारबैंत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है।
2. यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है।
3. इसका प्रारम्भ टोंक में करीम खाँ निहंग द्वारा किया गया।
4. इस लोक नाट्य में गायक मंजीरा बजाता है।
कूट-
(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
(e) अनुत्तरित प्रश्न
14. जलवायु परिवर्तन शमन के सन्दर्भ में प्रतिपादित ‘पंचामृत’ संकल्प में सम्मिलित संकल्प है-
1. वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना।
2. वर्ष 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 184 गीगावाट करना।
3. वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करना।
4. वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करना।
5. वर्ष 2047 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरी करना।
कूट:
(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 1 और 5 (d) उपरोक्त सभी
(e) अनुत्तरित प्रश्न
15. मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
1. बॉन चैलेंज का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना है।
2. सतत विकास लक्ष्यों, 2030 का लक्ष्य 14 मरुस्थलीकरण के शमन के सन्दर्भ में कदम उठाने का आह्वान करता है।
3. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन-यूएनसीसीडी की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी।
कूट:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
(e) अनुत्तरित प्रश्न
16. निम्नलिखित शहरों में से कौनसे शहर को ‘कनाडा का डेट्रॉयट’ के रूप में जाना जाता है-
(a) ओटावा शहर (b) कार्लटन शहर
(c) विंडसर शहर (d) ओशावा शहर
(e) अनुत्तरित प्रश्न
17. “यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र है, जिससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग विकसित हुआ था तथा यहाँ दुनिया का पहला यांत्रिक तेल कुआँ खोदा गया था।” निम्न कथन किस शहर को संदर्भित करता है-
(a) बाकू (b) निहोलो
(c) गिटालर्न (d) नूमियो
(e) अनुत्तरित प्रश्न
18. भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र और संबंधित राज्य को दर्शाने वाले सही सुमेलित युग्म है-
कोयला उत्पादक क्षेत्र - राज्य
1. सिंगरौली - मध्यप्रदेश

2. करनपुरा – झारखण्ड
3. बिसरामपुर – तेलंगाना
4. अन्तरगांव – छत्तीसगढ़
- कूटः
(a) केवल एक युग्म सुमेलित है।
(b) केवल दो युग्म सुमेलित है।
(c) केवल तीन युग्म सुमेलित है।
(d) सभी युग्म सुमेलित है।
(e) अनुत्तरित प्रश्न
19. 'हिमाद्रि श्रृंखला' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
1. हिमाद्रि पर्वत श्रेणी वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है।
2. इस श्रेणी के पश्चिमी छोर पर नंगापर्वत शिखर तथा पूर्वी छोर पर मकालू शिखर है।
3. इस श्रेणी की क्रोड ग्रेनाइट शैलों से बनी है तथा इसके आस-पास कायान्तरित और अवसादी शैलें भी मिलती हैं।
- कूटः
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
(e) अनुत्तरित प्रश्न
20. लघु औद्योगिक प्रदेश समूह को दर्शाने वाले सही समूह का चयन कीजिए
(a) अंबाला-अमृतसर औद्योगिक प्रदेश, इलाहाबाद-वाराणसी-मिर्जापुर औद्योगिक प्रदेश, बिलासपुर-कोरबा औद्योगिक प्रदेश, कोलम-थिरुवनंथपुरम औद्योगिक प्रदेश
(b) अंबाला-अमृतसर औद्योगिक प्रदेश, इलाहाबाद-वाराणसी-मिर्जापुर औद्योगिक प्रदेश, गुरुग्राम-दिल्ली-मेरठ औद्योगिक प्रदेश, इंदौर-देवास-उज्जैन औद्योगिक प्रदेश
(c) अंबाला-अमृतसर औद्योगिक प्रदेश, इलाहाबाद-वाराणसी-मिर्जापुर औद्योगिक प्रदेश, बिलासपुर-कोरबा औद्योगिक प्रदेश, इंदौर-देवास-उज्जैन औद्योगिक प्रदेश
(d) छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश, इलाहाबाद-वाराणसी-मिर्जापुर औद्योगिक प्रदेश, बिलासपुर-कोरबा औद्योगिक प्रदेश, इंदौर-देवास-उज्जैन औद्योगिक प्रदेश
(e) अनुत्तरित प्रश्न
21. भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ियों/पर्वतों का विस्तार पाया जाता है-
(a) लगभग 29.3 प्रतिशत (b) लगभग 27.7 प्रतिशत
(c) लगभग 43 प्रतिशत (d) लगभग 33.4 प्रतिशत
(e) अनुत्तरित प्रश्न
22. निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन की पहचान कीजिए।
(a) मुकुन्दरा की पर्वत श्रेणी का चंदवाड़ी क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर है।
(b) बूंदी की पर्वत-श्रेणी दोहरी पर्वतमाला है, जिसकी लम्बाई लगभग 116 कि.मी. है।
(c) शाहबाद का उच्च क्षेत्र बारां जिले के पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है।
(d) डग-गंगधर की उच्च भूमि में छोटी-छोटी पहाड़ियाँ यत्र-तत्र विस्तारित हैं।
(e) अनुत्तरित प्रश्न
23. राजस्थान की नदियों के सन्दर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
1. बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है।
2. बेड़च नदी का उद्गम गोगुन्दा की पहाड़ियाँ है।
3. कोठारी नदी भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है।
4. खारी नदी का उद्गम उदयपुर जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ी है।
- कूटः
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 4
(e) अनुत्तरित प्रश्न
24. सूची-I (सिंचाई परियोजना) को सूची-II (जिला) से सुमेलित कीजिए और सत्य कूट की पहचान कीजिए-
- | सूची-I (सिंचाई परियोजना) | सूची-II (जिला) |
|--------------------------------|-----------------|
| A. भीम सागर सिंचाई परियोजना | 1. कोटा |
| B. पांचना सिंचाई परियोजना | 2. सवाई माधोपुर |
| C. हरिश्चन्द्र सिंचाई परियोजना | 3. झालावाड़ |
| D. सोम-कागदर सिंचाई परियोजना | 4. उदयपुर |
- कूट:-
- | | A | B | C | D |
|-------|---|---|---|---|
| (a) 1 | 2 | 3 | 4 | |
| (b) 1 | 2 | 4 | 3 | |
| (c) 3 | 2 | 1 | 4 | |
| (d) 3 | 2 | 4 | 1 | |
- (e) अनुत्तरित प्रश्न
25. निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके स्पष्टीकरण के रूप में दिए गये कारण पर विचार करते हुए सही युग्म का चयन कीजिए।
कथन- राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से कम वर्षा प्राप्त होती है।
कारण- अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व होती है और राजस्थान में इनको कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं मिलता है।
- कूट/युग्म
(a) कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है।
(b) कथन और कारण दोनों सही है, मगर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है।
(c) कथन सही है मगर कारण गलत है।
(d) कथन गलत है मगर कारण सही है।
(e) अनुत्तरित प्रश्न

26. राजस्थान में पाई जाने वाली “मध्यम प्रकार की काली मृदा” के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।

1. इस मृदा में कच्छारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है।
2. यह हाड़ौती पठार अर्थात् कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में विस्तारित है।
3. इस मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम होता है, किन्तु कैल्शियम और पोटैश पर्याप्त मात्रा में होता है।

कूट:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
(e) अनुत्तरित प्रश्न

27. भारत की जनगणना-2011 के अनुसार राजस्थान की क्रमशः न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों का युग्म है-

- (a) जालौर, सिरोही, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़
(b) जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा
(c) जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, बाँसवाड़ा
(d) जालौर, सिरोही, बाँसवाड़ा, बाड़मेर
(e) अनुत्तरित प्रश्न

28. सूची -I (घीया पत्थर उत्पादन के क्षेत्र) को सूची-II (जिला) से सुमेलित कीजिए और सत्य कूट की पहचान कीजिए-

- | सूची-I (घीया पत्थर उत्पादन के क्षेत्र) | सूची-II (जिला) |
|--|----------------|
| A. ओडन क्षेत्र | 1. राजसमंद |
| B. चूखिया क्षेत्र | 2. बाँसवाड़ा |
| C. देगोटा क्षेत्र | 3. दौसा |
| D. बैजावास क्षेत्र | 4. अलवर |

कूट:-

- | A | B | C | D |
|-------|---|---|---|
| (a) 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) 1 | 2 | 4 | 3 |
| (c) 3 | 2 | 1 | 4 |
| (d) 3 | 2 | 4 | 1 |
- (e) अनुत्तरित प्रश्न

29. निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके स्पष्टीकरण के रूप में दिए गये कारण पर विचार करते हुए सही युग्म का चयन कीजिए।

कथन- उद्देशिका संविधान के उन प्रावधानों की व्याख्या करने में सहायक है जहाँ भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट होती है।

कारण- उद्देशिका को ‘संविधान की कुंजी’ कहा जाता है क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक विचारों और उद्देश्यों को प्रकट करती है।

कूट/युग्म

- (a) कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन का सही

स्पष्टीकरण करता है।

- (b) कथन और कारण दोनों सही हैं, मगर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है।
(c) कथन सही है मगर कारण गलत है।
(d) कथन गलत है मगर कारण सही है।
(e) अनुत्तरित प्रश्न

30. सूची-I (अनुच्छेद) को सूची-II (प्रावधान) से सुमेलित कीजिए-
सूची-I (अनुच्छेद) सूची-II (प्रावधान)

- | | |
|-----------------|---|
| A. अनुच्छेद-38 | 1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि |
| B. अनुच्छेद-43क | 2. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना |
| C. अनुच्छेद-45 | 3. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा |
| D. अनुच्छेद-46 | 4. छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध |

कूट:-

- | A | B | C | D |
|-------|---|---|---|
| (a) 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) 1 | 2 | 4 | 3 |
| (c) 3 | 2 | 1 | 4 |
| (d) 3 | 2 | 4 | 1 |
- (e) अनुत्तरित प्रश्न

31. निम्नलिखित में से कौनसे अधिकार एवं विशेषाधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं-

1. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
2. महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता नियुक्त होने का अधिकार
3. लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार

कूट:

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3
(e) अनुत्तरित प्रश्न

32. भारत के संविधान में उल्लेखित ‘मूल कर्तव्य’ में कौनसे घटकों/तत्वों का आदर किये जाने की अपेक्षा की गयी है-

- (a) संविधान के आदर्श, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत
(b) केवल संविधान के आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज
(c) संविधान के आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत
(d) संविधान के आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान
(e) अनुत्तरित प्रश्न

33. संविधान के अनुच्छेद और उसके प्रावधान को दर्शाने वाले सही सुमेलित युग्म है-
- | | | |
|---------|---|---------------------------------|
| संविधान | - | प्रावधान |
| 1. 243च | - | सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 2. 243ज | - | पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा |
| 3. 243ट | - | पंचायतों के लिए निर्वाचन |
- कूट:
- (a) केवल एक युग्म सुमेलित है।
 (b) केवल दो युग्म सुमेलित हैं।
 (c) सभी युग्म सुमेलित हैं।
 (d) सभी युग्म सुमेलित नहीं हैं।
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
34. केन्द्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाने वाले चुनावों के दौरान होने वाले व्यय के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए।
- यदि केवल संसद के चुनाव हो रहे हैं, तो व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
 - यदि केवल राज्य विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो व्यय पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
 - संसद और राज्य विधानसभा के एक साथ चुनाव होने की स्थिति में, व्यय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है।
 - चुनाव में पूंजीगत उपकरणों, मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित व्यय और मतदाता पहचान पत्र योजना पर होने वाला व्यय केवल केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- कूट:
- (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 3
 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 4
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
35. उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश-
- राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी लेता है।
 - नियुक्त होने वाले न्यायाधीश से परामर्श करता है।
 - संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है।
- कूट:
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
36. राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना से पूर्व राजस्थान के कौन-कौनसे प्रान्तों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे-
- जयपुर प्रांत
 - कोटा प्रांत
 - जोधपुर प्रांत
 - उदयपुर प्रांत
 - बीकानेर प्रांत
- कूट:
- (a) केवल 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 1, 3 और 5
 (c) केवल 1, 3, 4 और 5 (d) 1, 2, 3 और 5
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
37. यदि किसी पंचायत समिति में जनसंख्या एक लाख से अधिक हो जाती है तो प्रत्येक 15000 या उसके अतिरिक्त भाग के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी संख्या बढ़ जाती है-
- (a) एक निर्वाचन क्षेत्र (b) दो निर्वाचन क्षेत्र
 (c) तीन निर्वाचन क्षेत्र (d) पाँच निर्वाचन क्षेत्र
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
38. भारत में नागरिक चार्टर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
- भारत में नागरिक चार्टर तैयार करने का समन्वय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जाता है।
 - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिक चार्टर को परिणाम-उन्मुख बनाये जाने की सिफारिश की थी।
 - भारत में नागरिक चार्टर की असफलता का कारण सेवा के मानकों का वस्तुनिष्ठ और स्पष्ट होना है।
- उपर्युक्त में से उन कथनों का चयन कीजिए जो असत्य नहीं हैं/हैं-
- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1
 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
39. लोकनीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
- लोकनीति का कार्यान्वयन 'ऊपर से नीचे' और 'नीचे से ऊपर' दोनों दृष्टिकोणों से किया जा सकता है।
 - लोकनीति मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य केवल यह देखना है कि बजट का सही उपयोग हुआ है या नहीं।
 - भारत में नीति आयोग नीतियों के निर्माण और उनके मूल्यांकन के लिए एक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है।
- निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए-
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) केवल 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
40. उच्चतम न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी भी मामले या वाद में पारित या किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है-
- (a) अनुच्छेद-131 (b) अनुच्छेद-133
 (c) अनुच्छेद-136 (d) अनुच्छेद-141
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
41. राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया के सन्दर्भ में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए।
- इन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी।
 - यह राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे।
 - यह बिहार, उत्तरप्रदेश तथा हरियाणा के राज्यपाल रहे थे।
 - इनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया तब यह राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे।
- (e) अनुत्तरित प्रश्न

42. निम्न में से उन मुख्यमंत्रियों का चयन कीजिए जो राज्यपाल भी रहे हो-

- हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरोसिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया
- मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया
- मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, जयनारायण व्यास
- मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया
- अनुत्तरित प्रश्न

43. नए राज्य के गठन से पहले राजधानी और उच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए गठित गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी-

- 23 मार्च, 1949 को
- 21 मार्च, 1949 को
- 27 मार्च, 1949 को
- 17 मार्च, 1949 को
- अनुत्तरित प्रश्न

44. राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट-2026-27 में 'थार सांस्कृतिक सर्किट' की गयी घोषणाएँ की गयी है, इस सांस्कृतिक सर्किट में कौन-कौनसे जिले सम्मिलित होंगे-

- जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर और चूरू
- जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर
- जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर
- केवल जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर
- अनुत्तरित प्रश्न

45. राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट-2026-27 के अनुसार सूची-I (जिला) को सूची-II (केंद्र) से सुमेलित कीजिए और सत्य कूट की पहचान कीजिए-

सूची-I (जिला)	सूची-II (केंद्र)
A. अलवर	1. Centre of Excellence for Onion and Vegetables
B. श्रीगंगानगर	2. Centre of Excellence for Kinnow
C. बांसवाड़ा	3. Centre of Excellence for Mango
D. जोधपुर, कोटा व उदयपुर	4. Organic Food Market

कूट:-

A	B	C	D
(a) 1	2	3	4
(b) 1	2	4	3
(c)	2	1	4
(d) 3	2	4	1

(e) अनुत्तरित प्रश्न

46. राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रचालित जोत धारक के संदर्भ में असत्य कथन है-

- कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की

संख्या 76.55 लाख है।

- वर्ष 2010-11 की तुलना में कृषि गणना 2015-16 में भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर है।
- वर्ष 2010-11 की तुलना में कृषि गणना 2015-16 में प्रचालित भूमि जोतों के औसत आकार 13.07 प्रतिशत की कमी आयी है।

कूट:

- केवल 1
- केवल 2
- केवल 3
- केवल 4
- अनुत्तरित प्रश्न

47. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के लक्ष्य से लायी गयी राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 किस तारीख तक प्रभावी रहेगी-

- 31 मार्च, 2031
- 31 दिसम्बर, 2029
- 31 मार्च, 2029
- 31 दिसम्बर, 2031
- अनुत्तरित प्रश्न

48. राजस्थान में कृषि भंडारण अवसंरचना के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए।

- राजस्थान राज्य में 41 जिलों में कृषि भंडारण के लिए 9 गोदाम है।
- राजस्थान में कुल भंडारण क्षमता 17.25 लाख मैट्रिक टन है।
- राजस्थान में कृषि भंडारण अवसंरचना के लिए 'राजस्थान राज्य भण्डारण निगम' नोडल एजेंसी है।

कूट:

- केवल 1
- केवल 2
- केवल 3
- उपरोक्त में से कोई नहीं
- अनुत्तरित प्रश्न

49. राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम का निर्धारण, संस्कृत शिक्षण गुणवत्ता में सुधार आदि के लिए "राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान" कहा संचालित है-

- जयपुर में
- सिरोही में
- अलवर में
- टोंक में
- अनुत्तरित प्रश्न

50. भारत सरकार द्वारा लाँच 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत राजस्थान में कितने घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है-

- 10 लाख घरों में
- 5 लाख घरों में
- 3 लाख घरों में
- 15 लाख घरों में
- अनुत्तरित प्रश्न

51. राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति 2025 के सन्दर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए-

- इस नीति को राजस्थान सरकार ने 7 दिसम्बर, 2025 से लागू किया है।
- इस नीति में नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों की स्थापना के लिए ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- इस नीति में बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति सूक्ष्म श्रेणी के खुदरा व्यापारियों के लिए प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
- उपरोक्त में से कोई नहीं
- अनुत्तरित प्रश्न

52. “केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने के लिए अत्यधिक उधारी से बाजार में तरलता की कमी हो जाती है और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। इससे निजी क्षेत्र के लिए धन की उपलब्धता कम होती है। इसलिए निवेश में गिरावट आती है और संवृद्धि मंद पड़ जाती है। यदि सरकार उधार ली गयी धनराशि लोकलुभावन योजनाओं के लिए राजस्व व्यय के रूप में खर्च करती है, तो इससे एक स्थिति उत्पन्न होती है।” इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है-

- राजकोषीय फाँस स्थिति
 - हासमान प्रभाव स्थिति
 - राजकोषीय खिंचाव स्थिति
 - राजकोषीय अहित स्थिति
 - अनुत्तरित प्रश्न
- 53. देश में उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर भूमि के स्वास्थ्य को बचाने के लिए पीएम-प्रणाम योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था-**
- वर्ष 2022 में
 - वर्ष 2023 में
 - वर्ष 2024 में
 - वर्ष 2025 में
 - अनुत्तरित प्रश्न

54. केन्द्रीय बजट-2026-27 के अनुसार सरकार को अधिकतम रुपया प्राप्ति का स्रोत है-

- Borrowings and Liabilities
- Income Tax
- Corporation Tax
- GST and Other Tax
- अनुत्तरित प्रश्न

55. 16वें वित्त आयोग द्वारा सहायतानुदान के सन्दर्भ में प्रदत्त सिफारिशों के सन्दर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए-

- आयोग ने पांच वर्षों की अवधि में 9.47 लाख करोड़ रुपए के अनुदानों का सुझाव दिया है।

- आयोग ने 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए अन्य दो सहायतानुदानों को बंद करने की सिफारिश की है।
- आयोग ने शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय, और आपदा प्रबंधन के सन्दर्भ में सहायतानुदान का उल्लेख किया है।

कूट:

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3
- अनुत्तरित प्रश्न

56. “जब वयस्क आबादी की आयु में वृद्धि होती है। इसके चलते व्यक्ति बुढ़ापे के लिए अधिक बचत करने लगता है। बचत में यह वृद्धि पूंजी संचय और आर्थिक संवृद्धि में योगदान कर सकती है।” यह लाभांश की स्थिति है-

- प्रथम जनसांख्यिकीय लाभांश
- द्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश
- तृतीय जनसांख्यिकीय लाभांश
- चतुर्थ जनसांख्यिकीय लाभांश
- अनुत्तरित प्रश्न

57. कृषि शासन में राज्य स्तरीय नवाचार के सन्दर्भ में सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।

- कर्नाटक के फ्रूट्स प्लेटफॉर्म ने एकीकृत किसान डेटाबेस तैयार किया है।
- असम राज्य सिंचाई योजना का उद्देश्य नई योजनाओं और सौर पंपों के माध्यम से सिंचाई कवरेज का विस्तार करना है।
- आंध्र प्रदेश ने ड्रोन, कंटीन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन तथा जीआईएस का उपयोग करते हुए आंध्र प्रदेश पुनः सर्वेक्षण परियोजना लागू की है।
- मध्य प्रदेश की सौदा पत्रक पहल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों से सीधे एमएसपी-आधारित खरीद को सक्षम बनाया है।

कूट:

- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- केवल 1, 3 और 4
- 1, 2, 3 और 4
- अनुत्तरित प्रश्न

58. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ‘5-R’ सिद्धांत का सही क्रम/समूह क्या है?

- Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle
- Remove, Reduce, Reuse, Restore, Reform
- Refuse, Remake, Reuse, Recover, Recycle
- उपरोक्त में से कोई नहीं
- अनुत्तरित प्रश्न

59. निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके स्पष्टीकरण के रूप में दिए गये कारण पर विचार करते हुए सही युग्म का चयन कीजिए।

कथन- एक छोटे लोहे के टुकड़े (कील) की तुलना में पानी का जहाज पानी पर आसानी से तैरता है।

कारण- जहाज द्वारा विस्थापित किए गए पानी का भार जहाज के कुल भार से कम होता है।

कूट:

- (A) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
 (B) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
 (C) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
 (D) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

60. एक बंद कमरे में यदि पंखा चलाया जाए, तो कमरे की हवा का तापमान-

- (A) कम हो जाता है। (B) बढ़ जाता है।
 (C) स्थिर रहता है। (D) पहले बढ़ता है फिर कम होता है।
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

61. एस्पिरिन का प्रयोग दिल के दौरों को रोकने में होता है क्योंकि इसमें-

- (A) रक्त स्कंदन रोधी गुण होते हैं।
 (B) दर्द निवारक गुण होते हैं।
 (C) व्यसनकारी गुण होते हैं।
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं।
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

62. निम्न में से कौनसे घटक खाद्य परिरक्षकों के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं-

- I. सोडियम बेंजोएट
 II. प्रोपियोनिक अम्ल के लवण
 III. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड

कूट:

- (A) केवल I और II (B) केवल II और III
 (C) केवल I और III (D) I, II और III
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

63. सूची-I (सिद्धांत/घटना) को सूची-II (प्रभाव/विशेषता) से सुमेलित कीजिए-

सूची-I (सिद्धांत/घटना)	सूची-II (प्रभाव/विशेषता)
A. जैव संचयन	1. खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर विषाक्तता बढ़ना
B. जैव आवर्धन	2. एक ही जीव के ऊतकों में प्रदूषक का जमा होना
C. सिनर्जिज्म	3. प्रजाति का पूरी तरह समाप्त होना
D. विलोपन	4. दो प्रदूषकों का संयुक्त प्रभाव उनके अलग-अलग प्रभाव से अधिक होना

कूट:

- (A) A-2, B-1, C-4, D-3
 (B) A-1, B-2, C-4, D-3
 (C) A-2, B-3, C-4, D-1
 (D) A-1, B-2, C-3, D-4
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

64. भारत में नैनो-कप तकनीक से कैंसर उपचार का तकनीक का विकास किया गया है, इस तकनीक के विकास में संलग्न संस्थान थी-

- The Institute of Nano Science and Technology-Mohali
- The Indian Institute of Technology-Bombay
- The Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer (ACTREC)

कूट-

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

65. ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सबसे बड़े संयंत्र के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

- यह लखनऊ में विकसित किया गया/जा रहा है।
- इसकी उत्पादन क्षमता 80-100 ब्रह्मोस मिसाइल/वर्ष है।
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक, बहु-प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता वाली मिसाइल है।

सत्य कथनों का चयन करे-

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

66. भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान पोत के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

- इसका विकास गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग द्वारा किया जायेगा।
- यह पोत भारत के अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्रों और आर्कटिक में स्थित हिमाद्रि को मजबूत करेगा।

सत्य कथनों का चयन करे-

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न 2
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

67. GRAIL मिशन के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

- यह जाक्सा तथा नासा का संयुक्त मिशन है।
- इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की आंतरिक संरचना, थर्मल विकास और ज्वालामुखीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करना है।
- इस मिशन में दो यान शामिल थे।

- असत्य कथनों का चयन करे-**
- (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) केवल 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं (e) अनुत्तरित प्रश्न
68. 'बियॉन्ड स्क्रीन्स' के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए-
1. यह भारत की पहली उद्योग-संचालित डिजिटल डिटॉक्स पहल है।
 2. यह राजस्थान सरकार, अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ व कहमाइंड हेल्थकेयर प्रा. लि. द्वारा शुरू की गयी है।
 3. इसका उद्देश्य डिजिटल लत से बचाव व संतुलित तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना है।
- कूट:**
- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 (e) अनुत्तरित प्रश्न
69. 'आयरनबुड' के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह सातवीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है।
 2. इसका निर्माण या विकास एनवीडीया द्वारा किया गया है।
 3. यह ASIC चिप्स हैं जो विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन की गयी है।
- सत्य कथनों का चयन करे-**
- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 (e) अनुत्तरित प्रश्न
70. DRR Rice 100 (कमला) के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह जीनोम-संपादित चावल किस्म है।
 2. इसके विकास के लिए क्रिस्पर कैस आधारित एसडीएन-प्रथम व द्वितीय तकनीक का प्रयोग किया गया है।
 3. इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा किया गया है।
- सत्य कथनों का चयन करे-**
- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 (e) अनुत्तरित प्रश्न
71. एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के सन्दर्भ में सत्य विकल्प का चयन कीजिए।
1. वित्तीय निवेश - ₹79,459 करोड़
 2. पेट्रोकेमिकल क्षमता - 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष एकीकृत उत्पादन क्षमता
 3. हिस्सेदारी - एचपीसीएल (74 प्रतिशत) और राजस्थान सरकार (26 प्रतिशत)
- कूट:**
- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 (e) अनुत्तरित प्रश्न
72. "यह राजस्थान के जाने-माने संगीतकार और वीणा कैसेट्स के संस्थापक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म वर्ष 1946 में सुजानगढ़ (चूरू) में हुआ था। इन्होंने राजस्थानी लोक संगीत-संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।" यह है-
- (a) नन्द मिश्रा (b) केसरी चंद मालू (c) नारायण मालू (d) कोशोर मालू (e) अनुत्तरित प्रश्न
73. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा योजना) की आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेशवासियों देश में कौन-कौनसे राज्यों में सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं-
1. तमिलनाडू 2. कर्नाटक 3. पंजाब
- कूट:**
- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 (e) अनुत्तरित प्रश्न
74. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस, मीडिया एंड वोटर एजुकेशन: स्ट्रेथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू इन्फॉर्मड पार्टिसिपेशन का आयोजन कहाँ किया गया-
- (a) जयपुर (b) नई दिल्ली (c) नागपुर (d) नासिक (e) अनुत्तरित प्रश्न
75. हाल ही में 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह (विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाद) बना है-
- (a) कामराजार (b) पारादीप (c) मुंद्रा (d) कोच्ची (e) अनुत्तरित प्रश्न
76. हाल ही में भारत सरकार ने औषधि नियम, 1945 के तहत कहां के हवाई अड्डे को औषधियों के आयात द्वार के रूप में अधिसूचित किया है-
- (a) जोधपुर (b) नवी मुंबई (c) कोच्ची (d) ओडिशा (e) अनुत्तरित प्रश्न
77. राजस्थान में शहरी अवसंरचना विकास और अर्बन चैलेंज फंड के तहत राज्य में कितनी राशि की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं-
- (a) लगभग ₹15,700 करोड़ (b) लगभग ₹15,600 करोड़ (c) लगभग ₹15,800 करोड़ (d) लगभग ₹15,100 करोड़ (e) अनुत्तरित प्रश्न

78. भीम एवं भोपालसागर बांध आधुनिकीकरण परियोजना का कार्य किस तिथि तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है-
 (a) 21 अप्रैल, 2027 (b) 28 अप्रैल, 2027
 (c) 14 अप्रैल, 2027 (d) 24 अप्रैल, 2027
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
79. हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा चुनाव-2026 के लिए प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया है, यह है-
 1. डॉ. सुमित्रा सिंह 2. डॉ. सतीश पूनिया
 3. श्री नीरज डांगी
 कूट:
 (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
80. हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16 जून, 2026 को कितने जिलों में 'नागरिक सुरक्षा कोर' का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की-
 (a) 8 जिलों में (b) 9 जिलों में
 (c) 23 जिलों में (d) 5 जिलों में
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
81. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) बाधा रहित/बैरियर-लेस टोलिंग प्रणाली के शुभारंभ की घोषणा की है-
 (a) महाराष्ट्र में (b) राजस्थान में
 (c) गुजरात में (d) हरियाणा में
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
82. केंद्रीय कैबिनेट ने किस तिथि को संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी-
 (a) 3 मई, 2026 को (b) 6 मई, 2026 को
 (c) 9 मई, 2026 को (d) 5 मई, 2026 को
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
83. संसद रत्न अवॉर्ड-2026 के लिए कितनी संसदीय स्थायी समितियों को चुना गया है-
 (a) 2 संसदीय स्थायी समितियों को
 (b) 4 संसदीय स्थायी समितियों को
 (c) 3 संसदीय स्थायी समितियों को
 (d) 6 संसदीय स्थायी समितियों को
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
84. हाल ही में सुर्खियों में रही 'सरमत मिसाइल' किस देश द्वारा निर्मित की गयी है-
 (a) चीन (b) भारत
 (c) रूस (d) इजरायल
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
85. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
 1. यह इंडेक्स मार्च 2026 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया।
 2. इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बताया गया है।
 3. भारत 6.428 स्कोर के साथ 18वें स्थान पर रहा।
 कूट:
 (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
86. रायसीना डायलॉग 2026 के सन्दर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
 (a) रायसीना डायलॉग का 11वां संस्करण 5-7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
 (b) इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टेब मुख्य अतिथि रहे।
 (c) इसका थीम "Saṁskāra – Assertion, Accommodation, Advancement" था।
 (d) यह सम्मेलन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया।
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
87. हाल ही में "राजस्थान मंडपम्" के रूप में देश का सबसे बड़ा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा-
 (a) दिल्ली में (b) जयपुर में
 (c) जोधपुर में (d) अलवर में
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
88. कथन: "विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने EV खरीदारों के लिए रोड टैक्स घटा दिया।" निहित पूर्वधारणा कौन-सी है?
 (a) लोग केवल रोड टैक्स की वजह से EV नहीं खरीदते।
 (b) रोड टैक्स घटाने से लोग EV खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
 (c) सभी लोग EV खरीदना चाहते हैं।
 (d) EV, ईंधन वाहनों से सस्ते हैं।
 (e) अनुत्तरित प्रश्न
89. कथन: "परीक्षाएँ केवल ऑनलाइन ही आयोजित की जानी चाहिए।" मजबूत तर्क कौन-सा है?
 (a) हाँ, क्योंकि इससे कागज की बचत होती है और यह पर्यावरण के अनुकूल है।
 (b) हाँ, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा हमेशा निष्पक्ष होती है।
 (c) नहीं, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
 (d) A और C दोनों।
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

90. कथन :

I. कोई अभियंता डॉक्टर नहीं है।

II. कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं।

निष्कर्ष :

I. कुछ शिक्षक अभियंता हैं।

II. कोई अभियंता डॉक्टर नहीं है।

विकल्प:

- (a) केवल I अनुसरण करता है।
 (b) केवल II अनुसरण करता है।
 (c) I और II दोनों अनुसरण करते हैं।
 (d) न तो I न ही II अनुसरण करता है।
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

91. एक निश्चित राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर 52 रु. है, तो राशि है-

- (a) 10,508 रु. (b) 5,200 रु.
 (c) 3,980 रु. (d) 2,680 रु.
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

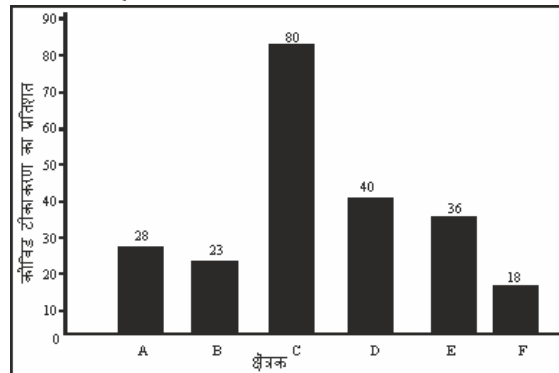
92. 64, 125, 216, 343, 512, 729 में से असमान संख्या चुनिए-

- (a) 64 (b) 125
 (c) 216 (d) 727
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

93. यदि किसी कोड में : CAT → DBU तथा PEN → QFO, तो DOG → ?

- (a) EPH (b) EPG
 (c) FPH (d) DPG
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

94. बार ग्राफ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि क्षेत्रक D की जनसंख्या 250000 है। तो क्षेत्रक D के कितने लोगों को टीका लगाया जाना अभी तक बाकी है ?

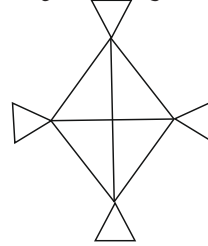


- (a) 160000 (b) 170000
 (c) 150000 (d) 100000
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

95. एक गाँव में, कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं तथा शेष अशिक्षित हैं। यदि अशिक्षित लोगों की संख्या 360 है, तो गाँव की कुल जनसंख्या क्या है?

- (a) 600 (b) 500
 (c) 400 (d) 300
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

96. आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए।



- (a) 10 (b) 12 (c) 13 (d) 11
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

97. रानी ने मागरिट से कहा, समुद्रतट पर मिली वह मेरे कल जिस लड़की से मैं मित्र की माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री थी। लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है?

- (a) पुत्री (b) भतीजी / भांजी
 (c) सहेली/ दोस्त (d) चचेरी / ममेरी / मौसेरी बहन
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

98. एक धनराशि को P, Q, R, S के बीच 3 : 5 : 4 : 2 के अनुपात में बाँटा जाना है। यदि Q को S से 1500 रुपये अधिक प्राप्त हुए, R का हिस्सा कितना है?

- (a) ₹2200 (b) ₹2000
 (c) ₹1800 (d) ₹1000
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

99. किसी परीक्षा में 20 प्रतिशत छात्र गणित में फेल हुए और 15 प्रतिशत छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10 प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए और दोनों विषयों में 300 छात्र पास हुए तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे?

- (a) 350 (b) 400
 (c) 450 (d) 500
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

100. यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाए, तो बताइए ब्याज की दर कितनी होगी?

- (a) $5\frac{1}{2}\%$ प्रति वर्ष (b) 6% प्रति वर्ष
 (c) $6\frac{2}{3}\%$ प्रति वर्ष (d) 25% प्रति वर्ष
 (e) अनुत्तरित प्रश्न

Answer Key

1. Answer- (b)

Exp- जहाँआरा की कब्र -

- यह कब्र शेख निजामुद्दीन औलियाके मकबरे के दक्षिण में जालीदार संगमरमर के परदों सहित एक बिना छत का घेरा है।
- इसके खोखले ऊपरी भाग पर घास रहती है।
- इस मकबरे पर एक मर्मस्पर्शी लेख खुदा है जिसका अर्थ है "सिवाय हरी घास के मेरी कब्र को किसी चीज से न ढका जाए, क्योंकि केवल घास ही दीन की कब्र ढकने के लिए काफी हैं।"

2. Answer- (d)

Exp- राजा राम मोहन राय की कृतियाँ-

1. प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एण्ड हैप्पीनेस (1820 ई.)
2. संवाद कौमुदी- 1821 ई. (बंगला भाषा-पहला साप्ताहिक सामाचार पत्र) (भारतीय भाषा में संपादित संचालित व प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र)
3. मिरातुल अखबार- 1822 ई. (फारसी भाषा में)
4. Gift to Monothiest (1804, फारसी में)
5. अपीलस टू द क्रिश्चियन पब्लिक- तीन पत्रों का प्रकाशन- 1820-23 ई. (श्रीरामपुर के ईसाई पादरियों से उनके गम्भीर विवाद के उपरान्त) ये पत्र बाइबिल के आधार पर लिखे गए।

3. Answer- (b)

Exp-देवबंद आन्दोलन-

- 1866-67 ई. में मुहम्मद कासिम ननौतवी तथा रसीद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद स्कूल (सहारनपुर) शुरू किया गया।
- यह स्कूल परंपरागत इस्लाम में विश्वास रखता था।
- उद्देश्य- इस्लाम के अनुयायियों को इस्लाम की मूल शिक्षा देना तथा उनमें नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करना था।
- ये अंग्रेजी व्यवस्था तथा अलीगढ़ आन्दोलन के खिलाफ थे।
- इस आन्दोलन ने 1885 ई. में कांग्रेस के निर्माण का स्वागत किया तथा इनका मानना था कि भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।

4. Answer- (c)

Exp- नक़्शबंदी सिलसिला-

- इसकी स्थापना बगदाद में ख्वाजा बहाउद्दीन नक़्शबंदी ने की। भारत में (उच्छ में) इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की।
- ये सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। इस सिलसिले के संत ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद सरहिन्दी ने स्वयं को मुजहिद अलिफसानी (सुधारक) कहा व अकबर की उदारनीतियों का विरोध किया।

5. Answer- (a)

Exp- चोल मूर्ति कला-

- चोल साम्राज्य में मंदिरों की सजावट के लिए मूर्तियों का विशेष महत्त्व था, नटराज की मूर्ति चोल मूर्तिकला का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।
- ऐहोल की रावणपहाड़ी गुफा की मूर्ति से पता चलता है कि चालुक्य साम्राज्य के समय भी नटराज की मूर्ति बनी थी लेकिन चोल शासन के समय यह चरम पर पहुँची।

6. Answer- (d)

Exp-

- अलवर भी क्रांतिकारी भावनाओं से अछूता नहीं था। अलवर के दीवान फैजुल्ला खाँ की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराजा बन्नेसिंह ने अंग्रेजों की सहायताार्थ आगरा सेना भेजी। अलवर राज्य की गुर्जर जनता की सहानुभूति भी क्रांतिकारियों के साथ थी।
- बीकानेर महाराज सरदारसिंह राजस्थान का अकेला ऐसा शासक था जो सेना लेकर विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर भी गया। वह राज्य सेना के 5000 घुड़सवार और पैदल सैनिक लेकर पंजाब के हाँसी, सिरसा और हिसार जिलों में गया बाडलू स्थान पर बीकानेर की सेना को क्रांतिकारियों ने परास्त किया महाराज की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने बीकानेर को टी.बी. परगने के 41 गांव दिए।
- बाँसवाड़ा का शासक महारावल लक्ष्मण सिंह भी विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सहयोगी बना रहा। 11 दिसम्बर, 1857 को तांत्या टोपे ने बाँसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। महारावल राजधानी छोड़कर भाग गया।

7. Answer- (c)

- डंकेरी चोट-जयनारायण व्यास
- काला बादल-भैरवलाल
- खूनियाँ रौ राज-अर्जुनलाल सेठी
- सपनो आयो-हीरालाल शास्त्री

8. Answer- (d)

9. Answer- (c)

Exp- महाराणा कुंभा-

- महाराणा कुंभा 1433 ई. में मेवाड़ का शासक बना
- 1437 ई. में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया।
- 1453 ई. में कुंभा ने मारवाड़ से मण्डोर छीन लिया।
- 1456 ई. में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कतुबुद्दीन के बीच चम्पानेर की संधि हुई।
- कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभस्वामी तथा श्रृंगारचंवरी का मंदिर, एकलिंगजी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाये, जो अपनी विशालता एवं तक्षककला के कारण अद्भुत हैं।

10. Answer- (c)

Exp-

- सिर- बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा।
- कण्ठ- थमण्यो, थेड्यो, आड़, मूँठया, झालरा, ठुस्सी।
- गले और वक्ष- तुलसी, बजड़ी, हालरो, हाँसली, तिमणियाँ, पोत, चन्द्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मांदल्या, चपकली, हंसहार, सरी, कण्ठी।
- कान- कर्णफूल, पीपलपत्रा, फूल झूमका, अंगोट्या, झेला, लटकन, टोटी।
- हाथ- कड़ा, कंकण, मोकड़ी (लाख से निर्मित चूड़ी), कात (काँच की चूड़ी), नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी।
- उंगली- बींटी, दामणा, हथपान, छड़ा।
- पांव- कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नूपुर, झाँझर, नेवरी।
- नाक- नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चोप, भँवरकड़ी।
- कमर- कन्दोरा या करधनी।
- दांत- रखन और चूपा।

11. Answer- (a)

Exp- जानकी देवी बजाज-

- इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारीलाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ई. में मध्यप्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ।
- 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा।

12. Answer- (a)

Exp- सर्वगी सम्प्रदाय-

- मुख्य केंद्र- सांगलिया धूणी, सीकर
- स्थापना- लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 ई. में
- अनुयायियों का मुख्य अभिवादन 'जय साहेब' है।
- यह सम्प्रदाय जाति-पात के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है।

13. Answer- (a)

Exp-

- चारबैंत में गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है।
- सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परम्पराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी।
- जमनालाल बजाज जी के देहान्त के बाद इनको गौसेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया।
- ये जयपुर प्रजामण्डल के 1944 ई के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गईं।

14. Answer- (b)

Exp- पंचामृतसंकल्प- यह भारत की जलवायु कार्यवाई के लिए पाँच संकल्प है, जिसमें पाँच प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं जो निम्न है-

1. 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना।
2. 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।
3. 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताएं नवीकरणीय संसाधनों से पूरी करना।

4. 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाना।
5. 2030 तक 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी करना।

15. Answer- (c)

Exp-

1. बॉन चैलेंज- बॉन चैलेंज एक वैश्विक प्रयास है जिसका उद्देश्य दुनिया की खराब हो चुकी और कटी हुई भूमि को फिर से बहाल करना है। इसका प्रारंभिक लक्ष्य 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर था, जिसे बाद में 2014 के न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स के तहत बढ़ाकर 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया।
2. सतत विकास लक्ष्य- SDG लक्ष्य 15.3 का मुख्य केंद्र 'भूमि क्षरण तटस्थता' प्राप्त करना है।
3. UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) की स्थापना 1994 में हुई थी।

16. Answer- (c)

17. Answer- (a)

18. उत्तर- (b)

सिंगरौली	—	मध्यप्रदेश
करनपुरा	—	झारखण्ड
बिसरामपुर	—	छत्तीसगढ़
अन्तरगांव	—	तेलंगाना

19. Answer- (b)

Exp- हिमाद्रि श्रेणी -

- यह हिमालय की सबसे उत्तरी तथा सबसे ऊँची पर्वतशृंखला है।
- इस श्रेणी की क्रोड ग्रेनाइट शैलों से बनी है, जिसके आस-पास कायान्तरित और अवसादी शैलें भी मिलती हैं।
- इस श्रेणी के पश्चिमी छोर पर नंगापर्वत शिखर तथा पूर्वी छोर पर नामचावरवा शिखर है। संसार की सबसे ऊँची पर्वत चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। काँचनजंगा मकालू, धौलागिरि तथा अन्नपूर्णा आदि हिमाद्रि की अन्य चोटियाँ हैं।
- हिमाद्रि पर्वत श्रेणी वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है।
- इसलिए परिवहन खर्च बचाने और अधिक चीनी प्राप्त करने के लिए चीनी मिलें उत्पादन क्षेत्र के पास ही लगाई जाती हैं।

20. Answer- (c)

Exp- मुख्य औद्योगिक प्रदेश-

- मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश, बेंगलुरु-तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुरुग्राम-दिल्ली-मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोलम-थिरुवनंथपुरम औद्योगिक प्रदेश।

लघु औद्योगिक प्रदेश-

- अंबाला-अमृतसर औद्योगिक प्रदेश, सहारनपुर-मुजफ्फरनगर-बिजनौर औद्योगिक प्रदेश, इंदौर-देवास-उज्जैन औद्योगिक प्रदेश, जयपुर-

अजमेर औद्योगिक प्रदेश, कोल्हापुर-दक्षिणी कन्नड़ औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी मालाबार औद्योगिक प्रदेश, मध्य मालाबार औद्योगिक प्रदेश, अदीलाबाद-निजामाबाद औद्योगिक प्रदेश, इलाहाबाद-वाराणसी-मिर्जापुर औद्योगिक प्रदेश, भोजपुर-मुंगेर औद्योगिक प्रदेश, दुर्ग-रायपुर औद्योगिक प्रदेश, बिलासपुर-कोरबा औद्योगिक प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी औद्योगिक प्रदेश।

21. Answer- (a)

Exp- भारत भौतिक विविधताओं का देश है। यहाँ लगभग सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के 29.3 प्रतिशत भाग पर पर्वत, 27.7 प्रतिशत भाग पर पठार तथा 43 प्रतिशत भाग पर मैदान फैले हुए हैं।

22. Answer- (b)

Exp- बूँदी की पर्वत-श्रेणी दोहरी पर्वतमाला है, जिसकी लम्बाई लगभग 96 कि.मी. है।

23. Answer- (d)

Exp-

- बनास नदी- बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, जो कुम्भलगढ़ से 5 कि.मी. दूर स्थित है।
- बेड़च नदी- इसका उद्गम गोगुन्दा की पहाड़ियाँ हैं, जो उदयपुर के निकट हैं। उदयपुर के निकट आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, किन्तु उदयसागर झील से निकलने के पश्चात् इसे बेड़च कहते हैं।
- कोठारी नदी- यह बनास की सहायक नदी है, जो राजसमंद जिले के उत्तरी भाग से निकलने के पश्चात् लगभग 145 कि.मी. प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है।
- खारी नदी- इस नदी का उद्गम राजसमन्द जिले के बिजरातल ग्राम की पहाड़ी है।

24. Answer- (c)

25. Answer- (a)

26. Exp-

मध्यम प्रकार की काली मृदा-

- विस्तार- कोटा, बूँदी, बारां, झालावाड़ जिलों
- यह गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है।
- इस मृदा में कच्छारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है।
- इस मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम होता है, किन्तु कैल्शियम और पोटैश पर्याप्त मात्रा में होता है।

27. Answer- (b)

28. Answer- (a)

29. Answer- (a)

- सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार स्पष्ट किया है कि यदि किसी अनुच्छेद का अर्थ निकालने में दुविधा हो, तो उद्देशिका का सहारा लिया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान की आत्मा और दर्शन को दर्शाती है।

बेरुबारी यूनियन मामले-1960 में इसे 'संविधान निर्माताओं के मन को खोलने वाली कुंजी' कहा गया था। चूँकि कारण स्पष्ट करता है कि उद्देशिका क्यों व्याख्या में सहायक है।

30. Answer (d)

38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा

43क. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना

45. छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध

46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

31. Answer- (d)

Exp- संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। विदेशियों को नहीं-

1. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 व 30)।
2. लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार।
3. सार्वजनिक पदों, जैसे- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायावादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार।

32. Answer- (d)

Exp- अनुच्छेद-51(क)- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

33. Answer- (c)

Exp-

243च- सदस्यता के लिए निरर्हताएं

243ज- पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा

243ट- पंचायतों के लिए निर्वाचन

34. Answer- (a)

Exp- केन्द्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाने वाले चुनावों के दौरान होने वाले व्यय का वहन-

- यदि केवल संसद के चुनाव हो रहे हैं, तो व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है,
- यदि केवल राज्य विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो व्यय पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- संसद और राज्य विधानसभा के एक साथ चुनाव होने की स्थिति में, व्यय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।
- चुनाव में पूंजीगत उपकरणों, मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित व्यय और मतदाता पहचान पत्र योजना पर होने वाला व्यय केंद्र और राज्य के मध्य समान रूप से साझा किया जाता है।

35. Answer- (c)

Exp- तदर्थ न्यायाधीश-

- नियुक्ति- भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
- कब नियुक्त किया जाता है?- जब उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम
- इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीशसंबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है।

36. Exp- राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र तीन बीकानेर जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे।

37. Exp- पंचायत समितियों में भी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं।

- एक लाख तक की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में 15 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और यदि जनसंख्या एक लाख से अधिक हो जाती है, तो प्रत्येक 15000 या उसके अतिरिक्त भाग के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दो बढ़ जाती है।

38. Answer- (a)

भारत में नागरिक चार्टर की असफलता का कारण मानकों का अस्पष्ट और सामान्य होना है। जब मानक विशिष्ट नहीं होते, तो नागरिक यह दावा नहीं कर पाते कि सेवा में देरी हुई है या नहीं।

39. Answer- (b)

नीति मूल्यांकनका दायरा केवल बजट तक सीमित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि नीति ने अपने निर्धारित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है।

40. Answer- (c)

Exp- संविधान के अनुच्छेद-136के तहत भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी भी मामले या वाद में पारित या किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है।

41. Answer- (c) Exp- जगन्नाथ पहाड़िया-

- इनका संबंध भुसावर, भरतपुर से था।
- इनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया तब यह राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे।
- राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे तथा इन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की।
- ये वर्ष 1989-90 में बिहार तथा वर्ष 2009-2014 में हरियाणा के राज्यपाल बने थे।

42. Answer- (d)

Exp-राजस्थान निम्नलिखित मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी रहे थे- मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया

43. Answer- (c)

Exp-नए राज्य के गठन से पहले राजधानी और उच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए श्री बी.आर. पटेल, कर्नल टी.सी. पुरी और श्री एस.पी. सिन्हा की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने 27 मार्च, 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि जयपुर को नए राज्य की राजधानी बनाया जाए और उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित किया जाए।

44. Answer- (c)

Exp- राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट-2026-27 में खुड़ी-जैसलमेर में अल्ट्रा लकजरी स्पेशल टूरिज्म जोन, कुलधरा में पर्यटक सुविधा केन्द्र, भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर, झुंझुनूं में वार म्यूजियम और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को शामिल करते हुए 'थार सांस्कृतिक सर्किट' बनाने की घोषणा की गयी है।

45. Answer- (a)

exp-

जिला

केंद्र

अलवर - Centre of Excellence for Onion and Vegetables,

श्रीगंगानगर - Centre of Excellence for Kinnow

बांसवाड़ा - Centre of Excellence for Mango

जोधपुर, कोटा व उदयपुर - Organic Food Market

46. Answer- (d)

Exp- प्रचालित जोत धारक-

- राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 68.88 लाख थी अर्थात् भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े श्रेणियों की वर्गीकृत भूमि जोत, कुल जोतों का क्रमशः 40.12 प्रतिशत, 21.90 प्रतिशत, 18.50 प्रतिशत, 14.79 प्रतिशत एवं 4.69 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है व बड़े आकार वर्गों की जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि विखंडन में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया, अर्थात् जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।
- वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमान्त, लघु व अर्द्ध मध्यम आकार की जोतों के क्षेत्रफल में क्रमशः 19.79 प्रतिशत, 10.50 प्रतिशत व 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (तालिका-1.1)। इसके विपरीत बड़े आकार एवं मध्यम आकार की

जोतों के कुल क्षेत्रफल में क्रमशः 13.20 प्रतिशत एवं 0.27 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में प्रचालित भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा है जो वर्ष 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो 11.07 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

47. Answer- (c)

Exp- राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2024-

- लागू- 8 दिसम्बर, 2024
- प्रभावी- 31 मार्च, 2029
- इस नीति का प्रमुख उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जो राजस्थान में एम.एस.एम.ई. को उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने में सक्षम बनाए। इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक "वन स्टॉप शॉप" समाधान के रूप में तैयार किया गया है, जो लाभ और सहायता प्राप्त करने में सुलभ पहुंच को सुनिश्चित करता है।

48. Answer- (a)

Exp-

- राजस्थान राज्य भण्डारण निगम राज्य में कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक, भण्डारण के लिए गोदामों का विकास एवं प्रबन्धन करने वाली नोडल एजेंसी है।
- वर्तमान में राज्य के 36 जिलों में 97 गोदाम हैं जिनकी दिसम्बर, 2025 तक कुल भंडारण क्षमता 17.25 लाख मैट्रिक टन है।

49. Answer- (a)

Exp- राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान-

अवस्थित- महापुरा, जयपुर

कार्य-

- विद्यालयों की कक्षा 1-12 तक संस्कृत शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्यपुस्तकें एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना तथा शैक्षिक मानदंडों के साथ सख्खण सुनिश्चित करना।
- शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेवारत शिक्षकों को सहयोग करना।
- संस्कृत को सार्वजनिक भाषा के रूप में बढ़ावा देना, संचार कौशल को बढ़ाना और इसके प्रचार एवं शोधकार्य में सहायता करना।

50. Answer- (b)

exp- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना-

- लाँच- 13 फरवरी, 2024
- उद्देश्य- 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र लगाकर प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना।
- इस योजना के माध्यम से अधिकतम ₹78,000 (3 किलोवाट या उससे अधिक) का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
- राजस्थान में 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

51. Answer- (d)

Exp- राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति 2025

- लागू- 7 दिसम्बर, 2025
- उद्देश्य- सूक्ष्म व्यापार उद्यमों सहित छोटे व्यापारियों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करना है, साथ ही व्यापार क्षेत्र में नए निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।
प्रावधान-
- नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों की स्थापना के लिए, ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा और ₹1 करोड़ से अधिक और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सी. जी.टी.एम.एस.ई.) योजना के अंतर्गत, नवीन सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों को ₹5 करोड़ तक के ऋण कवरेज पर देय गारंटी शुल्क की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए दी जाएगी।
- बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति सूक्ष्म श्रेणी के खुदरा व्यापारियों के लिए, प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत (₹1 लाख तक) प्रतिपूर्ति, पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
- ई-कॉमर्स प्रोत्साहन सूक्ष्म व्यापार उद्यमों को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹50,000 तक की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क (शिपिंग शुल्क को छोड़कर) की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- विशेष श्रेणियों हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांगव्यक्तियों के स्वामित्व वाले व्यापार उद्यमों को ₹1 करोड़ से अधिक और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा।

52. Answer- (b)

Exp- हासमान प्रभाव-

- राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा अत्यधिक उधारी से बाजार में तरलता की कमी हो जाती है और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। इससे निजी क्षेत्र के लिए धन की उपलब्धता कम होती है। इसलिए निवेश में गिरावट आती है और संवृद्धि मंद पड़ जाती है। यदि सरकार उधार ली गयी धनराशि लोकलुभावन योजनाओं के लिए राजस्व व्यय के रूप में खर्च करती है, तो इससे क्राउडिंग आउट हो सकता है।

53. Answer- (b)

Exp- पीएम-प्रणाम(PM-PRANAAM)-

- PM-PRANAAM-PM Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment, and Amelioration of Mother-Earth
- प्रारम्भ- वर्ष 2023 में

- उद्देश्य- उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर, भूमि के स्वास्थ्य को बचाना।

54. Answer- (a)

55. Answer- (c)

Exp-

- 16वें वित्त आयोग ने पांच वर्षों की अवधि में 9.47 लाख करोड़ रुपए के अनुदानों का सुझाव दिया है। इनमें निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनुदान शामिल हैं- (i) शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय, और (ii) आपदा प्रबंधन।
- 16वें वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित अनुदानों को बंद कर दिया है- (i) राजस्व घाटा अनुदान, (ii) शिक्षा, न्याय, सांख्यिकी और कृषि के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान, और (iii) राज्य-विशिष्ट अनुदान।

56. Answer- (b)

57. Answer- (d)

58. उत्तर: (a)

59. उत्तर: (C)

विस्तृत व्याख्या:

- प्लवन के नियमके अनुसार कोई वस्तु तभी तैरती है जब उसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर या उससे अधिक हो।
- जहाज का आकार ऐसा होता है कि वह अपने भार के बराबर जल विस्थापित कर देता है।

60. उत्तर: (B)

व्याख्या: पंखा चलाने से हवा की गति बढ़ती है जिससे हमें पसीने के वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होती है, लेकिन कमरे की हवा का वास्तविक तापमान अणुओं के घर्षण और मोटर की ऊष्मा के कारण बढ़ जाता है।

61. उत्तर: (a)

एस्पिरिन, प्रोस्टाग्लैंडीन निर्माण को बाधित करती है। इसकी एंटी-प्लेटलेट गतिविधि के कारण इसे हार्ट अटैक के जोखिम वाले रोगियों को दिया जाता है।

62. उत्तर: (D)

63. उत्तर: (A)

64. Answer- (d)

65. Answer- (d)

Exp-

ब्रह्मोस एयरोस्पेस का सबसे बड़ा संयंत्र – लखनऊ

- स्थान: उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा
- क्षेत्रफल: 80 हेक्टेयर, लागत ₹300 करोड़

- उत्पादन क्षमता: 80–100 ब्रह्मोस मिसाइल/वर्ष
- विशेषता: ब्रह्मोस एनजी (नई पीढ़ी) मिसाइल निर्माण
- अन्य केंद्र: हैदराबाद, नागपुर, पिलानी, तिरुवनंतपुरम
- ब्रह्मोस मिसाइल: सुपरसोनिक, 2.8–3.5 मैक गति, 290–400 किमी रेंज, बहु-प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता

66. Answer- (c)

Exp- भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत (Polar Research Vessel - PRV)

● विकासकर्ता:

- GRSE (Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd)
- कॉम्सबर्ग (नॉर्वे) के साथ साझेदारी

● उद्देश्य:

- ध्रुवीय क्षेत्रों (आर्कटिक और अंटार्कटिका) में वैज्ञानिक अनुसंधान
- जलवायु परिवर्तन, समुद्र विज्ञान, और रसद सहयोग
- भारत की अंटार्कटिक/दक्षिणी महासागर अभियानों को सशक्त बनाना
- स्वदेशी क्षमता विकसित करना

67. Answer- (a)

Exp- GRAIL मिशन (NASA)

- NASA के GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) मिशन से यह पता चला कि चंद्रमा की पृथ्वी की ओर और पीछे की सतहों में अंतर का मुख्य कारण पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव और भीतरी ताप स्रोतों में अंतर है।
- मिशन में दो यान शामिल थे – Ebb और Flow, जो चंद्रमा की कक्षा में घूमते रहे और उसके गुरुत्वीय क्षेत्र का सटीक नक्शा तैयार किया।
- प्रक्षेपण: 2011, Delta II रॉकेट से, स्थान: केप कैनावेरल
- संचालन: Jet Propulsion Laboratory (JPL)
- वैज्ञानिक निर्देशन: MIT
- उद्देश्य: चंद्रमा की आंतरिक संरचना, थर्मल विकास और ज्वालामुखीय इतिहास की जानकारी।

68. Answer- (c)

Exp- 'बियॉन्ड स्क्रीन्स' – भारत की पहली उद्योग-संचालित डिजिटल डिटॉक्स पहल

- स्थान- कर्नाटक
- सहयोगी संगठन:
 - कर्नाटक सरकार (IT, BT, S&T विभाग)
 - अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ (AIGF)
 - कहमाइंड हेल्थकेयर प्रा. लि.
- उद्देश्य:
 - डिजिटल लत से बचाव
 - संतुलित तकनीकी उपयोग को बढ़ावा
 - स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल डिटॉक्स रणनीतियों का समावेश

69. Answer- (c)

Exp- **आयरनवुड (Ironwood TPU)-**

- पीढ़ी: यह गूगल की सातवीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) है।
- प्रकार: Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)
- ASIC वे चिप्स होती हैं जो विशिष्ट कार्य, जैसे AI और मशीन लर्निंग, के लिए डिजाइन की जाती हैं।
- उद्देश्य: AI मॉडल्स को तेजी से रन करना।
- यह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट की तरह कार्य करता है, जिसे कंप्यूटर का "मस्तिष्क" माना जाता है।

70. Answer- (d)

Exp- **जीनोम-संपादित चावल किस्में-**

- **प्रमुख किस्में:**
 - DRR Rice 100 (कमला)
 - Pusa DST Rice 1
- तकनीक: CRISPR-Cas आधारित (SDN 1 व 2)
- विकास संस्था: ICAR
- लाभ: बेहतर उत्पादन, जल संरक्षण, जलवायु सहनशीलता
- इसमें 250+ राष्ट्रीय संस्थान, CSIR लैब्स, विश्वविद्यालय भागीदार हैं।

71. Answer- (d)

Exp- **एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड-**

- अवस्थित- पचपदरा, बालोतरा
- वित्तीय निवेश- ₹79,459 करोड़
- क्षमता-9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
- पेट्रोकेमिकल क्षमता- 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष एकीकृत उत्पादन क्षमता
- उद्यम- संयुक्त उद्यम (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार)
- हिस्सेदारी- एचपीसीएल (74 प्रतिशत) और राजस्थान सरकार (26 प्रतिशत)
- यह भारत की प्रथम ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है।

72. Answer- (b)

Exp- **श्री केसरी चंद मालू-**

- यह राजस्थान के जाने-माने संगीतकार और वीणा कैसेट्स के संस्थापक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया।
- इनका जन्मवर्ष 1946 में सुजानगढ़ (चूरू) में हुआ था।
- इन्होंने राजस्थानी लोक संगीत-संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- सम्मान- समग्र कला साधना अवॉर्ड (राजस्थान संगीत नाटक अकादमी)
- डागर घराना अवॉर्ड (महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन)
- इन्होंने घूमर, चीरमी, और कांगसियो जैसे सदाबहार राजस्थानी गीतों के एलबम प्रोड्यूस किए।

73. Answer- (a)

Exp- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा योजना) की आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेशवासियों देश में कर्नाटक और तमिलनाडू के अलावा सभी राज्यों में इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं।

74. Answer- (a)

Exp- **इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस, मीडिया एंड वोटर एजुकेशन: स्ट्रेथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू इन्फॉर्मड पार्टिसिपेशन**

- आयोजन तिथि- 15 जुलाई, 2026
- आयोजन स्थल- जयपुर
- विषय- इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस, मीडिया एंड वोटर एजुकेशन: स्ट्रेथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू इन्फॉर्मड पार्टिसिपेशन
- आयोजक-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के 'आईआईआईडीईएम' (नई दिल्ली) तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के सहयोग से।
- वैश्विक सहभागिता-भारत, जॉर्जिया, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस और गुयाना
- घोषणा- इलेक्टोरल लिटरसी क्लब का विस्तार देशव्यापी अभियान के रूप में किया जाएगा और देश के प्रत्येक विद्यालय में इसकी स्थापना होगी।
- वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान श्री नवीन महाजन हैं।

75. Answer- (a)

Exp- **कामराजार बंदरगाह-**

- हाल ही में कामराजार बंदरगाह 18-मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह (विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाद) बना है।
- इसके लिए 'कैपिटल ड्रेजिंग चरण-VI' परियोजना के तहत बाहरी पहुंच मार्ग की गहराई को 20.0 मीटर से बढ़ाकर 23.0 मीटर और आंतरिक प्रवेश मार्ग को 22.0 मीटर किया गया है।
- यह बंदरगाह 18.0 मीटर के परिचालन ड्राफ्ट के साथ अब 1,70,000 टन तक के पूरी तरह से लदे कैपसाइज विशाल जहाजों को संभालने में सक्षम है।
- इस परियोजना में लगभग ₹440 करोड़ का निवेश किया गया है।

76. Answer- (b)

Exp- भारत सरकार ने औषधि नियम, 1945 के तहत नवी मुंबई हवाई अड्डे को औषधियों के आयात द्वार के रूप में अधिसूचित किया है। इस नए संशोधन के साथ प्रवेश द्वारों (सड़क/रेल/जहाज/हवाई मार्ग) की कुल संख्या 42 हो गई है।

77. Answer- (c)

Exp- **राजस्थान में शहरी अवसंरचना विकास और अर्बन चैलेंज फंड-**

- हाल ही में जयपुर के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 28 जून, 2026 को राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

- इस समझौता के तहत केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से राज्य के शहरी निकायों में आगामी 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे का समावेशी विकास किया जाएगा।
- इसके तहत राज्य में लगभग ₹15,800 करोड़ की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
- वित्तीय अंशदान-
➤ अर्बन चैलेंज फंड एक प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण व्यवस्था है। इसके तहत कुल परियोजना लागत का विभाजन निम्न प्रकार है-

हितधारक	अंशदान प्रतिशत	राजस्थान के संदर्भ में राशि
केंद्र सरकार (UCF के माध्यम से)	25%	लगभग ₹3,950 करोड़
राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय	25%	लगभग ₹3,950 करोड़
वित्तीय संस्थान/हुडको (HUDCO)	50%	लगभग ₹7,900 करोड़
कुल प्रस्तावित लागत (राजस्थान)	100%	लगभग ₹15,800 करोड़

78. Answer- (d)

Exp- भीम एवं भोपालसागर बांध आधुनिकीकरण परियोजना-

- हाल ही में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और भीम विधायक हरिसिंह रावत ने राजसमंद जिले में स्थित भीम बांध और भोपालसागर बांध तथा उनकी नहर प्रणालियों के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों का शिलान्यास किया है।
- यह कार्य मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है।
- इस संपूर्ण परियोजना के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है तथा परियोजना का कार्य 24 अप्रैल, 2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- ऐतिहासिक सन्दर्भ-
➤ भीम बांध-इसका निर्माण वर्ष 1950 में किया गया था।
➤ भोपालसागर बांध-इसका निर्माण वर्ष 1956 में किया गया था।
➤ अवस्थिति-यह दोनों बांध राजसमंद जिला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

79. Answer- (b)

Exp-राज्यसभा निर्वाचन-2026-

- राजस्थान से राज्यसभा चुनाव-2026 के लिए तीन प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया है।
- राजस्थान से राज्यसभा के लिए तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
- निर्वाचित सदस्य-
1. डॉ. अलका सिंह- भारतीय जनता पार्टी
2. डॉ. सतीश पूनिया- भारतीय जनता पार्टी
3. श्री नीरज डांगी- इण्डियन नेशनल कांग्रेस

- वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य-

क्र.सं.	नाम	दल
1.	श्री नीरज डांगी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस(कांग्रेस)
2.	डॉ. सतीश पूनिया	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
3.	डॉ. अलका सिंह	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
4.	श्री घनश्याम तिवारी	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
5.	श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला	इण्डियन नेशनल कांग्रेस(कांग्रेस)
6.	श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक	इण्डियन नेशनल कांग्रेस(कांग्रेस)
7.	श्री प्रमोद कुमार	इण्डियन नेशनल कांग्रेस(कांग्रेस)
8.	श्री चुन्नीलाल गरासिया	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
9.	श्री मदन राठौर	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
10.	श्रीमती सोनिया गांधी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस(कांग्रेस)

80. Answer- (a)

Exp- नवगठित जिलों में होगा 'नागरिक सुरक्षा कोर' का गठन-

- हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16 जून, 2026 को 8 नवगठित जिलों में 'नागरिक सुरक्षा कोर' का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।
- यह स्वीकृति वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के क्रम में हुई है।
- नागरिक सुरक्षा कोर नवगठित जिलों में आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा सहायक होगी है।
- Note- आठ नवगठित जिलों (बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, फलौदी, सलूमबर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ एवं ब्यावर)

81. Answer- (c)

Exp-

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने गुजरात में भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) बाधा रहित (बैरियर-लेस) टोलिंग प्रणाली के शुभारंभ की घोषणा की है।
- यह प्रणाली राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के सूत-भरूच खंड पर स्थित चोरायासी टोल प्लाजा पर शुरू हुई है।

82. Answer- (d)

Exp-

- हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 5 मई, 2026 को संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
- इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करना था।
- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026-

- यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि अर्थात् 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का प्रावधान करता है।

83. Answer- (b)

Exp-संसद रत्न पुरस्कार 2026-

- हाल ही में संसद रत्न अवॉर्ड-2026 के लिए 12 व्यक्तिगत सांसदों (10 लोकसभा और 2 राज्यसभा) और 4 संसदीय स्थायी समितियों को चुना गया है।
- चयनित सांसद-
 1. जगदंबिका पाल (उत्तर प्रदेश), व्यक्तिगत श्रेणी में
 2. पी.पी. चौधरी (राजस्थान), व्यक्तिगत श्रेणी में
 3. निशिकांत दुबे (झारखंड), व्यक्तिगत श्रेणी में
 4. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (महाराष्ट्र), व्यक्तिगत श्रेणी में
 5. प्रवीण पटेल (उत्तर प्रदेश)
 6. विद्युत बरन महतो (झारखंड)
 7. लुंबाराम चौधरी (राजस्थान)
 8. डॉ. हेमंत विष्णु सावरा (महाराष्ट्र)
 9. स्मिता उदय वाघ (महाराष्ट्र)
 10. नरेश गणपत म्हस्के (महाराष्ट्र)
 11. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र) तथा
 12. नरहरि अमीन (गुजरात)
- समितियां-
 1. कृषि संबंधी समिति
 2. वित्त समिति
 3. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति
 4. कोयला एवं खान समिति

84. Answer- (c)

Exp-यह रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया।

- इसकी मारक क्षमता 35,000 किमी से अधिक है।
- यह मिसाइल आधुनिक रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम है।
- पश्चिमी देशों में इस मिसाइल को 'सैटर्न I' नाम से भी जाना जाता है।

85. Answer- (c)

Exp- ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026-

- भारत 6.428 स्कोर के साथ 13वें स्थान पर रहा।

86. Answer- (d)

Exp- यह सम्मेलन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया।

87. Answer- (b)

88. उत्तर : (b)

समाधान : सरकार का यह कदम इस धारणा पर आधारित है कि रोड टैक्स घटाने से लोग EV खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। अन्य विकल्प

तर्कसंगत पूर्वधारणा नहीं हैं।

89. उत्तर : (d)

समाधान : तर्क (A) मजबूत है क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा से कागज की बचत होती है।

तर्क (C) भी मजबूत है क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।

तर्क (B) सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है।

90. उत्तर : (b)

समाधान : कथन में साफ कहा गया है कि कोई अभियंता डॉक्टर नहीं है। यह निष्कर्ष सीधे निकलता है। "कुछ शिक्षक अभियंता हैं।" का आधार कथनों में नहीं है।

91. उत्तर- (b)

दर = 10%

समय = 2 वर्ष

दोनों ब्याजों का अंतर = 52 रूपये

मूलधन = दोनों ब्याजों का अंतर $\times (100/\text{दर})^2$

मूलधन = $52 \times (100/\text{दर})^2 = 5200$ रूपये

92. उत्तर : (d)

समाधान:

$64 = 4^3$ $125 = 5^3$

$216 = 6^3$ $343 = 7^3$

$512 = 8^3$ $729 = 9^3$

729 (9^3) इस क्रम से बाहर है, इसलिए भिन्न है।

93. उत्तर : (a)

प्रत्येक अक्षर को +1 कर कोड बनाया गया है।

CAT $\rightarrow$ DBU

PEN $\rightarrow$ QFO

DOG $\rightarrow$ EPH

94. Ans. (c) : क्षेत्रफल D के बाकी लोगों को टीका लगाये जाने वालों की संख्या

$(100-40)/100 \times 250000 = 60 \times 2500 = 150000$

95. Ans. (a) : माना गाँव की कुल जनसंख्या x है।

शिक्षित लोगों की संख्या = $x \times \frac{40}{100} = \frac{2x}{5}$

अशिक्षित लोगों की संख्या = $x \times \frac{2x}{5} = \frac{3x}{5}$

प्रश्नानुसार, अशिक्षित लोगों की संख्या = 360

$\frac{3x}{5} = 360$

$x = \frac{360 \times 5}{3}$

गाँव की कुल जनसंख्या (x) = 600

96. Ans : (b)

एक-एक अंक से बने त्रिभुजों की संख्या = 8

दो-दो अंक से बने त्रिभुजों की संख्या = (1, 2), (3, 4), (1, 3), (2, 4)

कुल संख्या = 8 + 4 = 12

97. Ans. (d)

98. Ans. (b) : दिया है - $P : Q : R : S = 3 : 5 : 4 : 2$

माना $P = 3x$, $Q = 5x$, $R = 4x$, $S = 2x$

प्रश्नानुसार,

$$Q = S + 1500$$

$$5x = 2x + 1500$$

$$5x - 2x = 1500$$

$$3x = 1500 \Rightarrow x = \frac{1500}{3} = 500$$

$$\text{अतः R का हिस्सा} = 4x = 4 \times 500 = ₹2000$$

99. उत्तर- (b)

माना परीक्षा में उपस्थित छात्र = 100%

प्रश्नानुसार,

$$100 - [(20 - 10) + (15 - 10) + 10] = 300$$

$$100 (10 + 5 + 10) = 300$$

$$100 - 25 = 300$$

$$75\% = 300$$

$$\therefore 100\% = \frac{300}{75} \times 100 = 400$$

अतः परीक्षा में बैठे छात्र = 400

100. उत्तर- (c)

माना मूलधन = P

15 वर्षों के बाद धनराशि = 2P

$$SI = (2P - P) = P$$

प्रश्नानुसार,

$$P = \frac{P \times r \times 15}{100} \Rightarrow r = \frac{20}{3}\%$$

$$\text{ब्याज की दर (r)} = 6\frac{2}{3}\%$$

समसामयिकी पत्रिका टेस्ट : (सितंबर - 2026)

कुल प्रश्न : 100

अंक : 200

- हाल ही में जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से 'जयपुर घोषणापत्र' को पारित किया गया है, यह कार्य समूह के कौनसे मुख्य क्षेत्रों पर आधारित है-
 - एआई और पर्यटन
 - पर्यटन कौशल और क्षमता निर्माण
 - पर्यटन आदान-प्रदान और निर्बाध यात्रा सुविधा
 - सतत और जिम्मेदार पर्यटन
 कूट:

(a) केवल 1, 2 और 3	(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4	(d) 1, 2, 3 और 4
- फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैटरर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन के सन्दर्भ में असुमेलित विकल्प का चयन करे-
 - संस्करण- आठवां
 - आयोजन तिथि- 1 अगस्त, 2026
 - आयोजन स्थल- सीतापुरा, जयपुर
 - मुख्य अतिथि- वासुदेव देवनानी
- हाल ही में सुर्खियों में रहे 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडीजिनस फार्म' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
 - यह खुडी गांव, पाली जिले में खोला जायेगा।
 - इस केंद्र पर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े की प्रजातियों के नस्ल सुधार व संरक्षण पर काम होगा।
 कूट:

(a) केवल 1	(b) केवल 2
(c) 1 और 2	(d) न तो 1 और न 2
- 16 अगस्त, 2026 को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शिलान्यास किए गये 'अलवर सरस डेयरी प्लांट' की क्षमता है-
 - 5 लाख लीटर/दिन
 - 4 लाख लीटर/दिन
 - 3 लाख लीटर/दिन
 - 7 लाख लीटर/दिन
- वर्ष 2026 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान से चयनित होने वाले शिक्षक है-
 - दिव्येंदु सेन
 - वर्तिका गुलाटी
 - सूर्यकांत देवव्रत
 कूट:

(a) केवल 1 और 2	(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3	(d) 1, 2 और 3
- हाल ही में राज्य में 300 करोड़ की लागत से कहां पर एआई हब बनेगा?
 - जयपुर
 - अलवर
 - जोधपुर
 - सीकर
- मक्का संयुक्त रक्षा समझौता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
 - यह सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच 11 अगस्त, 2026 को हस्ताक्षरित हुआ है।
 - यह सामूहिक रक्षा का सिद्धांत की परिपालना पर आधारित है।
 - इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत स्थापित किया गया है।
 कूट:

(a) केवल 1 और 2	(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1	(d) 1, 2 और 3
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के दूधतलाई वन परिक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव शुभारंभ किस तिथि को किया?
 - 1 अगस्त, 2026 को
 - 3 अगस्त, 2026 को
 - 7 अगस्त, 2026 को
 - 19 अगस्त, 2026 को
- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय सम्मेलन के सन्दर्भ में सुमेलित विकल्प है-
 - आयोजन तिथि- 17 अगस्त से 28 अगस्त, 2026
 - आयोजन स्थल- उलानबटार, मंगोलिया
 - विषय- Restoring Land. Restoring Hope
 कूट:

(a) केवल 1 और 2	(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3	(d) 1, 2 और 3
- गोबरधन योजना के सन्दर्भ में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए।
 - अनुमोदन वर्ष- अगस्त, 2026
 - वित्तीय परिव्यय- ₹21,731 करोड़
 - कार्यान्वयन अवधि- वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 (10 वर्ष)
 - मंत्रालय- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

“सम्पूर्ण टेस्ट पेपर देने के लिए SAMYAK एप डाउनलोड करें---



सम्यक् मार्गदर्शन = सर्वश्रेष्ठ परिणाम

RAS 2024 में TOP 10 में 7, TOP 100 में 56, सहित 690+ चयन

— सभी सफल प्रतिभाओं को हार्दिक बधाई! —

RANK 2  VIRENDRA CHARAN	RANK 3  NAVNEET SHARMA	RANK 4  RAVINDRA SINGH	RANK 5  VIKASH SIYAG	RANK 6  AISHWARYA KANWAR	RANK 7  DINESH	RANK 9  BHOOPENDER SINGH			
RANK 12  KULDEEP SHARMA	RANK 13  KAILASH KUMAR	RANK 16  KAILASH RANWA	RANK 18  UMANG RAWAL	RANK 23  SAHDEV BIDADA	RANK 24  PARAMVEER SINGH	RANK 25  SWAROOP SINGH	RANK 26  AANCHAL NAGPAL	RANK 27  MAMTA LIMBA	RANK 28  ARIHANT JAIN
RANK 29  SIMRAN SHEKHAWAT	RANK 30  VINAY MOHAN	RANK 31  ANSHIKA AGARWAL	RANK 33  LOKENDRA SINGH	RANK 34  VIKAS CHOUDHARY	RANK 35  SANJU	RANK 36  KRISHANPAL SHEKHAWAT	RANK 43  JITENDRA	RANK 45  AMAR SINGH RATHORE	RANK 46  MANASVINI VERMA
RANK 48  TULSI	RANK 49  RAMAVTAR MUNDEL	RANK 50  DHARMRAJ SINGH RAO	RANK 52  BHOOMIKA TRIVEDI	RANK 55  RONAK	RANK 57  POONAM	RANK 58  SACHIN AGRAWAL	RANK 59  PARUL CHOUDHARY	RANK 61  KAMLESH KR SHARMA	RANK 65  ARIMARDAN CHAUHAN
RANK 66  UNNAT KISHOR RAJORA	RANK 70  KRITIKA GAUR	RANK 71  URMILA VISHNOI	RANK 73  JAYESH PRAJAPAT	RANK 74  MAHENDRA DAN	RANK 76  SIDDHARTH DHAKAD	RANK 77  JYOTSANA RANAWAT	RANK 78  CHOUDHARY MADHU ROOPARAM	RANK 79  NITESH GUPTA	RANK 80  VIKASH BISHNOI
RANK 82  DAMODAR PAREEK	RANK 83  KAILASH KUMAR	RANK 84  SHYAM SUNDER MEENA	RANK 85  MOHIT GODARA	RANK 86  NARASI RAM BISHNOI	RANK 87  RAM RATAN BATESAR	RANK 88  MAHENDRA CHOUDHARY	RANK 99  GHAMANDA RAM	RANK 100  VANDANA PATEL	+069...

Distance Learning Program

Samyak द्वारा गुणवत्तापूर्ण व परिणामोन्मुखी तैयारी **Online** भी



विशेषताएँ



नवीनतम सिलेबस, Prelims-Mains एवं RPSC Pattern के अनुसार पूर्णतः Exam-Oriented Study Material



Online Learning एवं Self-Study दोनों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया कंटेंट



Topic-Wise महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुव्यवस्थित संग्रह



सरल एवं प्रभावी हिंदी में Conceptual Clarity के साथ Updated Facts



अनुभवी Faculty, Subject Experts एवं Toppers द्वारा प्रमाणित सामग्री



NCERT एवं Rajasthan Board आधारित आवश्यक तथ्यों का समावेश



ONLINE COURSE & TEST SERIES AVAILABLE ON APP



Online Course Features

- Live From Classroom
- Printed Booklets
- Personal Mentorship
- Test Series

Offline & Online Separate Batches For Hindi & English Medium

HEAD OFFICE: NEAR RIDDHI - SIDDHI, JAIPUR **9875170111**